{ विश्वास वही रफ्तार नई }

बालाघाट
शुक्रवार 10 जुलाई 2026
आषाढ कृष्ण 10 विक्रम सम्वत 2083
वर्ष 16, अंक 286
पृष्ठ 12
मूल्य ₹ 7.00

पद्मेश मीडिया समूह का प्रकाशन

बालाघाट एक्सप्रेस

हिन्दी दैनिक

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

सेंसेक्स	-	78,285.07
निफ्टी	-	24,430.35
सोना	-	1,55,044
चांदी	-	2,45,000
डॉलर	-	95.38

खास खबर

विदेश से कचरा आयात सबसे बड़ा देशद्रोह- मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई । मद्रास हाईकोर्ट ने विदेशों से भारत में कचरा आयात करने के मामलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे देश की संप्रभुता और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया है। अदालत ने कहा कि जानबूझकर विदेशी कचरा मंगाना केवल पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन नहीं, बल्कि देशद्रोह जैसा गंभीर कृत्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत किसी भी कीमत पर दुनिया का कूड़ाघर नहीं बन सकता। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित कंपनियों को 60 दिनों के भीतर आयातित कचरा उसी देश में वापस भेजने का निर्देश दिया, जहां से वह लाया गया था। अदालत ने कहा कि पर्यावरण और राष्ट्रीय हितों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में चिट फंड धोखाधड़ी, ईडी की बड़ी कार्रवाई

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई क्रिप्टोकरेंसी निवेश, शेयर बाजार प्रशिक्षण योजनाओं और संदिग्ध धन शोधन से जुड़े बड़े चिट फंड धोखाधड़ी मामले की जारी जांच के तहत की गई। छापेमारी पश्चिम बर्दवान के अंडाल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) के कर्मचारी दिलीप मलिक के आवास पर, हावड़ा में सौरव चटर्जी के घर और नदिया में कारोबारी शुभ्र कांति नाग उर्फ बाबाई नाग से जुड़े परिसरों पर हुई, जहाँ केंद्रीय बल भी तैनात थे। जानकारी के अनुसार, दिलीप और उनके बेटे दिगंत मलिक पर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि उन्होंने लोगों को ठगने के उद्देश्य से कोलकाता में कार्यालय खोला और दिगंत ने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर भारी धन जुटाया।

सपा के पूर्व विधायक के ठिकानों पर रेड

झांसी। अखिलेश यादव के करीबी और सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 जगहों पर छापा मारा। झांसी में सपा नेता के आवास समेत 6 ठिकानों और लखनऊ के 2 फ्लैटों समेत 3 जगह पर करीब 16 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। ईडी की टीम सुबह 6 बजे पूर्व विधायक के ठिकानों पर पहुंची और रात करीब साढ़े 9 बजे वापस रवाना हुई। टीम ने स्पेस मून सिटी हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ी 500 फ्लॉ की फाइल जब्त की है। ईडी दीप नारायण की प्रापर्टी, लेनदेन और मनी लॉड्रिंग की जांच की। जिन जगहों पर रेड पड़ी, उसके बाहर फोर्स तैनात की गई। किसी को अंदर-बाहर जाने नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक, ईडी टीम ने एक-एक कमरे की तलाशी ली। पूर्व विधायक और उनके घरवालों भी पूछताछ की।

कुछ ना कहना

टीएमसी के बागियों को भाजपा ने दिया टिकट

सुष्मिता-सुखेंदु शेखर समेत तीन नेताओं को राज्यसभा टिकट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तीन पूर्व राज्यसभा सांसद को बड़ा इनाम मिला है। सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बड़ाईक को भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।

तीनों नेताओं ने गुरुवार को ही भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने कुछ ही घंटों बाद उन्हें टिकट देकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया। यह उपचुनाव उन तीन सीटों पर हो रहा है जो इन नेताओं के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव आयोग ने इन सीटों पर 24 जुलाई को मतदान कराने का एलान किया है। दूसरी ओर भाजपा ने गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के लिए मंजलपुर से सतीशभाई गोविंदभाई पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है।

हम सिर्फ विकास चाहते हैं-प्रकाश चिक बड़ाईक

राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रकाश चिक बड़ाईक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले 49 वर्षों में, 34 साल के वाम शासन और 15 साल के तृणमूल शासन के दौरान कई विकास कार्य पूरे नहीं हो सके। राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल की कमी रही। पांच साल तक 100 दिन रोजगार योजना का पैसा रुका रहा और गरीबों के लिए कई योजनाएं प्रभावित हुईं।

बड़ाईक ने आगे कहा कि इस बजट में उत्तर बंगाल में एम्स, कई मेडिकल कॉलेज, सिलीगुड़ी से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन और हासीमारा में एयरपोर्ट का प्रस्ताव है। हम सिर्फ विकास चाहते हैं। अगर पहले ही राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल होता, तो ये समस्याएं पैदा नहीं होतीं।

टीएमसी छोड़ने के बाद भाजपा में नई पारी

बता दें कि पिछले महीने सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बड़ाईक ने टीएमसी से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी थी। इसके बाद से ही उनके अगले कदम को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं। गुरुवार को इन सभी अटकलों पर विराम लग गया, जब तीनों नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।

सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर रॉय और प्रकाश चिक बड़ाईक टीएमसी के प्रमुख चेहरों में गिने जाते थे। ऐसे नेताओं का पहले पार्टी छोड़ना और फिर भाजपा की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि बंगाल की राजनीति में भाजपा सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि राज्यसभा में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है।

दीदी को झटके पर झटका!

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े सियासी झटके लग चुके हैं। इसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद हुई, जहां विधायक ऋत्रब्रत बनर्जी की अगुवाई में विधायकों के एक बड़े गुट ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इस अंदरूनी फूट के कारण विधानसभा के भीतर ही ममता बनर्जी को अपनों के तीखे तेवर झेलने पड़े।

फ्रीज बैंक खातों के मामले में टीएमसी को अंतरिम राहत

-कलकत्ता हाईकोर्ट ने विशेष अधिकारी की निगरानी में बैंक खाते संचालित करने की दी अनुमति

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उसके फ्रीज़ किए गए तीन बैंक खातों का सीमित उपयोग करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है, जिनकी निगरानी में पार्टी इन खातों से केवल दैनिक प्रशासनिक और कानूनी खर्च के लिए लेन-देन कर सकेगी।

हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि खातों से धनराशि का उपयोग केवल पार्टी के नियमित संचालन और कानूनी व्यय के लिए किया जाएगा। किसी अन्य प्रकार के बड़े या छोटे खर्च की अनुमति विशेष अधिकारी नहीं देंगे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि खातों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं में से दो व्यक्ति विशेष अधिकारी के समक्ष चेक प्रस्तुत करेंगे, जिन पर उनके प्रति-हस्ताक्षर के बाद ही बैंक भुगतान करेगा।

विशेष अधिकारी का मानदेय इन्हीं खातों से दिया जाएगा

अदालत ने विशेष अधिकारी के लिए 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया है, जिसका भुगतान संबंधित बैंक खातों से किया जा सकेगा। ये बैंक खाते पश्चिम बंगाल पुलिस ने पार्टी फंड के कथित दुरुपयोग की शिकायत के आधार पर फ्रीज़ किए थे। शिकायत बागी विधायक विश्वनाथ दास की ओर से दर्ज कराई गई थी। टीएमसी ने आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा था कि खातों के फ्रीज़ होने से पार्टी का नियमित कामकाज प्रभावित हो रहा है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया शिकायत सामान्य प्रकृति की प्रतीत होती है और उसमें किसी विशिष्ट वित्तीय लेनदेन का उल्लेख नहीं है।

एक राष्ट्र, एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में होगी देरी, मानसून सत्र में पेश होने की संभावना कम

नई दिल्ली। देश में प्रस्तावित एक राष्ट्र, एक चुनाव व्यवस्था को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट अभी सामने आने में समय लग सकता है। जानकारी के अनुसार, समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और कई महत्वपूर्ण पक्षों पर विचार-विमर्श जारी है। ऐसे में संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान रिपोर्ट पेश होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, समिति अभी विभिन्न राज्यों, संवैधानिक विशेषज्ञों और अन्य संबंधित पक्षों से मिले सुझावों का अध्ययन कर रही है। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तावित व्यवस्था के सभी संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की गहराई से समीक्षा की जाए। इसी कारण रिपोर्ट तैयार करने में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। बताया जा रहा है कि समिति जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहती। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले सभी सदस्यों के बीच व्यापक सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कई बिंदुओं पर अभी भी विस्तार से चर्चा बाकी है, जिसके चलते रिपोर्ट की समयसीमा आगे बढ़ सकती है। गौरतलब है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है, ताकि बार-बार होने वाले चुनावों पर होने वाला खर्च कम हो और प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। हालांकि, इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधनों की आवश्यकता होगी और व्यापक राजनीतिक सहमति भी जरूरी मानी जा रही है। फिलहाल सभी की नजर संयुक्त संसदीय समिति की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके आधार पर सरकार आगे की रणनीति तय करेगी।

वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों से 7 साल तक परमिट नहीं लगेगा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत, बैटरी (इलेक्ट्रिक), मेथनॉल, एथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को अब परमिट की अनिवार्यता से 7 साल तक की छूट मिलेगी। यह कदम न केवल परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत देगा, बल्कि देश के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) के लक्ष्य और एक स्थायी परिवहन प्रणाली के निर्माण की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इस पहल से परिवहन कंपनियां और ऑपरेटर वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों को अपनाने के लिए अधिक प्रोत्साहित होंगे, जिससे हरित भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66(1) के तहत, आमतौर पर माल ढोने वाले ट्रकों, बसों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों को संचालन के लिए परमिट लेना अनिवार्य होता है। यह परमिट प्रणाली सड़कों पर वाहनों की संख्या को विनियमित करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और राजस्व जुटाने में मदद करती है। हालांकि, सरकार ने अब बैटरी इलेक्ट्रिक, मेथनॉल, एथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे साफ ईंधन से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को इस परमिट की अनिवार्यता से सात साल तक की छूट प्रदान की है। यह छूट उन सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी जो इन वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग करते हैं, बशर्ते वे कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करें। सरकार का मानना है कि इस कदम से परिवहन कंपनियों और वाहन मालिकों को परमिट से जुड़ी औपचारिकताओं और खर्च से राहत मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रिक और अन्य क्लीन फ्यूल वाले ट्रकों व बसों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो सकेगी।

हालांकि, सरकार ने इस राहत के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। इस छूट का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगा जिनमें एआईएस-140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) यानी जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा। यह डिवाइस वाहन की वास्तविक समय की लोकेशन, गति और अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे संबंधित एजेंसियां वाहनों की बेहतर निगरानी कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था सुरक्षा बढ़ाने, नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और परिवहन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है। यदि किसी वाहन में निर्धारित मानक का वीएलटीडी नहीं होगा, तो उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

सात साल तक परमिट की अनिवार्यता से छूट मिलने से वाणिज्यिक वाहन संचालकों की परिचालन लागत काफी कम हो सकती है। परमिट फीस, कागजी कार्यवाही और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर होने वाला खर्च बचेगा, जिससे छोटे और बड़े दोनों तरह के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को राहत मिलेगी। यह छूट वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों में निवेश को अधिक आकर्षक बनाएगी और नवाचार को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही, पर्यावरण को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, मेथनॉल और एथेनॉल जैसे स्वच्छ ईंधनों के उपयोग से वायु प्रदूषण कम होगा और शहरों की हवा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

अभिषेक शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में राहत देते हुए कहा कि वह उनकी छवि और व्यक्तित्व का कथित दुरुपयोग करने वाली विभिन्न आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा। इस मामले में अदालत ने समन भी जारी किया है। कोर्ट अभिषेक शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स के संरक्षण की मांग की है। अभिषेक शर्मा की ओर से पेश वकील ने यूआरएल की जानकारी के साथ अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ पोस्ट हटाई जा चुकी हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी भी दो ऐसी पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें क्रिकेटर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है।

प्रदूषण को लेकर अवैध डाइंग-प्रिंटिंग इकाइयों पर हाईकोर्ट सख्त

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में अवैध डाइंग और प्रिंटिंग इकाइयों से फैल रहे प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और 14 जुलाई 2026 तक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा कि जब संबंधित विभाग स्वयं अवैध इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर चुके थे, तो अब तक उनका पालन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने विभागों की निष्क्रियता पर असंतोष जताते हुए जवाब तलब किया।

याचिकाकर्ता शैलेंद्र भंडारी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि शहर की कई आवासीय कॉलोनियों में अवैध रूप से डाइंग और प्रिंटिंग इकाइयां संचालित हो रही हैं। इन इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पानी बिना शोधन के खुले क्षेत्रों में छोड़ा जा रहा है, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार को 24 मार्च और 6 अप्रैल को जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन 7 जुलाई तक न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट की गई। कोर्ट ने कहा कि संबंधित विभागों ने अक्टूबर 2025 में जारी अपने ही आदेशों का भी पालन नहीं किया।

तेज रफ्तार कार लॉरी से टकराई, 7 की मौत, दो गंभीर रुप से घायल

बेंगलुरु। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गुरुवार तड़के एक कार और लॉरी की आमने-सामने की टक्कर होने से सात लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा एनएच-52 पर अराबैल घाट इलाके में बालागारा क्रॉस के पास रात करीब 1.30 बजे हुआ। पुलिस ने बताया कि घायलों को पहले पास के अस्पताल ले जाया गया और बाद में हुबली रेफर कर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक एमयूवी में ड्राइवर समेत नौ लोग सवार थे और वे धारवाड़ से धर्मस्थल और चिकमगलूर की यात्रा पर जा रहे थे। जानकारी से पता चला है कि गाड़ी का ड्राइवर एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ पार्ट-टाइम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर संजीव तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। वह सड़क के एकदम दाईं ओर चला गया और अंकोला की ओर से आ रही लॉरी से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मरने वाले सभी लोग धारवाड़ के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान ड्राइवर संजय अंगड़ी (33), बसवराज (48), अभिषेक ईश्वर (28), अक्षय (26), अभिषेक (26) और मंजूनाथ चुलाकी (32) में हुई है।

रिटायर्ड परिवहन अधिकारी के यहां 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और 1.62 करोड़ नगद मिले

35 करोड़ का बेहिसाब खजाना दबा बैठे थे साहब

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एक रिटायर्ड परिवहन अधिकारी के आवास पर छापेमारी के बाद मिले अकूत खजाने ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। विजिलेंस टीम की कई दिनों तक चली कार्रवाई में सामने आई संपत्तियों और निवेश का कुल मूल्य करीब 35 करोड़ रुपये आंका गया है। अलीगंज स्थित चंद्रलोक कॉलोनी में रिटायर्ड सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ललित कुमार के घर से 1.62 करोड़ रुपये नकद, 13 किलोग्राम सोना, 9 किलोग्राम चांदी, बेशकीमती हीरे-जेवरात और करोड़ों रुपये की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए, जिससे विजिलेंस टीम के अधिकारी भी चकाचौंध रह गए। इसके अतिरिक्त, बैंक निवेश, डाकघर जमा, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में भी 1 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के कागजात मिले, जो इस अधिकारी के कुबेर होने की कहानी बयां करते हैं।

इस चौंकाने वाले खुलासे की शुरुआत साल 2024 में हुई थी, जब ललित कुमार आगरा में एआरटीओ के पद पर तैनात थे। उस समय उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का एक मामला दर्ज किया गया था। शुरुआती जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद कानपुर स्थित एंटी करप्शन थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। राज्य सरकार के सीधे निर्देश पर विजिलेंस टीम ने इस मामले की गहन जांच शुरू की। जांच अधिकारी ने अदालत से तलाशी वारंट हासिल किया और फिर मंगलवार और बुधवार को ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान टीम को घर के अलग-अलग कोनों में, विशेष रूप से पैकेटों में छिपाकर रखे गए 1.62 करोड़ रुपये नकद मिले। इसके साथ ही, 13 किलोग्राम सोना और 9 किलोग्राम चांदी (जो बिस्कुट, बार और आभूषणों के रूप में थी) बरामद हुई। बरामद नकद, सोना और चांदी की अनुमानित कीमत मकान सहित लगभग 20 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच में लखनऊ और नोएडा जैसे प्रमुख शहरों में कई आवासीय मकानों, फ्लॉटों, कृषि भूमि और फ्लैटों से जुड़े दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। इनमें अंसल एपी और आम्रपाली स्प्रिंग मीडोज जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैट भी शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 13 करोड़ रुपये है। छापेमारी में टोयोटा इनोवा और हुंडई आई-20 जैसी लग्जरी कारें और एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई। इसके अलावा, घर की साज-सज्जा और घरेलू सामान पर भी भारी खर्च का ब्योरा तैयार किया गया है। विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि बरामद की गई सभी चल और अचल संपत्तियों का गहन सत्यापन किया जा रहा है।

खड़े ट्रक से टकराई कार, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

भोपाल। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में गुरुवार तड़के एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जानकारी दी कि यह हादसा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भरौला गांव के पास हुआ, जब एक कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा तड़के साढ़े तीन बजे सिद्धबाबा धाम के पास हुआ। इस घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक महिला ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मीडिया रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें फंसे लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मृतकों में एक पुरुष, तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सभी मृतक अनूपपुर जिले के लिलहाटोला गांव के रहने वाले थे और चित्रकूट जा रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतकों के परिजन अनूपपुर जिले से उमरिया पहुंच रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

ऐम्स के कार्यवाहक निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस की कार्रवाई टली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबित डीएनए पितृत्व विवाद से जुड़े मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ऐम्स) के कार्यवाहक निदेशक के खिलाफ प्रस्तावित अवमानना कार्रवाई उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार करने के बाद वापस ले ली। अदालत ने भविष्य में न्यायालय के आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा भी जताई।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की डबल बैंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अवमानना नोटिस की कार्यवाही को टाल दिया। अदालत ने पहले ऐम्स के कार्यवाहक निदेशक को व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हालांकि, उनकी ओर से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के बजाय संस्थान की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया, जिस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया और प्रस्तुत जवाब न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं था। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्यवाहक निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने पर विचार किया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि आदेश की व्याख्या हलफनामा दाखिल करने के रूप में की गई थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि उसका निर्देश स्पष्ट था और व्यक्तिगत स्पष्टीकरण अपेक्षित था। बाद में ऐम्स के कार्यवाहक निदेशक ने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी त्रुटि दोबारा नहीं होगी। इस पर संतोष व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माफी स्वीकार कर अवमानना नोटिस जारी करने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई।

यह मामला ऐम्स द्वारा कराए गए डीएनए परीक्षण और उससे संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से जुड़ा है।

5 माह से नहीं मिला मानदेय, आशा कार्यकर्ताओं ने मचाया हंगामा

कलेक्ट्रेट में सौपा ज्ञापन, विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की लगाई गुहार

कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ी कार्यकर्ताए, किसी और को ज्ञापन देने से किया इंकार

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाली आशा कार्यकर्ता व सहयोगिनी को पिछले 05 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जिसके चलते उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।इसके अलावा उनकी वर्षो से लंबित मांगे भी अब तक पूरी नही हो पायी है।जिससे आशा कार्यकर्ताएं प्रदेश सरकार से खासा नाराज हैं जिन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां विभिन्न कार्यो के मनादेय का भुगतान न होने सहित वर्षो से लंबित विभिन मांगे पूरी न होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले गुरुवार को नगर में एक रैली निकाली।जहा रैली के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुचकर ज्ञापन सौपा है।आशा कार्यकर्ताओं के अनुसार उनके द्वारा विगत 5 माह से गर्भवती महिला का कार्य या अन्य सभी कार्य किए गए है लेकिन उनका भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा ऐसे अन्य कार्य हैं जिनका भुगतान शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है।जिले के सभी 10 विकासखंड की आशा कार्यकर्ताओं ने 5 माह का बकाया भुगतान कराने की प्रमुख मांग को लेकर सौपे गए इस ज्ञापन में विभिन्न कार्यो का भुगतान करने सहित अन्य लंबित मांगो को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है।

ब्याज पर कर्ज उठाकर चलाना पड़ रहा काम

सौपे गए इस ज्ञापन के दौरान आशा कार्यकर्ता संघ से जुड़े पदाधिकारियो ने बताया कि बालाघाट जिले में लगभग 2000 आशा कार्यकर्ता स्कीम वर्कर के रूप में कार्यरत हैं। वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।लेकिन मानदेय सहित अन्य मामलों में उन्हें तरह-तरह से परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी मांगे भी पूरी नहीं की जा रही है।यहां तक कि विभिन्न पर्व में भी उन्हें भुगतान नही किया गया है। वही दबाव बनाकर काम लिया जा रहा है जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी है। उन्होंने बताया कि समय पर मानदेय न मिलने के चलते उन्हें भारी ब्याज पर कर्ज उठाना पड़ रहा है लेकिन उस कर्ज को चुकाने के लिए भी उन्हें परेशानी हो रही है।अब तो कर्ज देने वालों ने भी उन्हें कर्ज देना बंद कर दिया है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च सहित अन्य आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए वे पायी पायी को मोहताज हो गई है। बावजूद इसके भी उन्हें पिछले 5 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

05 माह से नहीं मिला मानदेय घर कैसे चलाएं

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 5 माह के मानदेय का भुगतान नहीं मिला है। हर माह किए जा रहे कार्यों की आंशिक राशि ही उनके खातों में जमा की जाती है, जबकि बची हुई राशि का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। सहयोगिनीयो द्वारा इस बचत राशि की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए गए हैं।जिले के सभी 10 विकासखंड की आशा कार्यकर्ताओं ने बकाया भुगतान कराने की प्रमुख मांग को लेकर सौपे गए इस ज्ञापन में विभिन्न कार्यों का भुगतान करने सहित अन्य लंबित मांगो को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है।आशा कार्यकर्ताओं के अनुसार उनसे गर्भवती महिला का कार्य के अलावा आशा बहनों से शासन प्रशासन के सभी प्रकार के काम जैसे टीवी कास्ट, हेड काउंटर सर्वे, घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड जैसे कार्य कराए जा रहे हैं लेकिन उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। भुगतान न मिलने के चलते उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने जल्द से जल्द संपूर्ण राशि का एकमुश्त तत्काल भुगतान किए जाने की मांग की है।

इन मांगों को लेकर सौपा गया ज्ञापन

स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के आधीन योजना में कार्यरत समस्त आशा कर्मचारियों को - न्यूनत्तम रू.26000/- से लेकर रू.48000/- प्रतिमाह देने, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं मितानीन, फेसिलिटेटर, बी.टी.टी., बीसी, एसपीएस, को-आर्डिनेटर एवं अन्य को पद अनुसार वेतन राशि भुगतान सुनिश्चित करने,आशा योजना में कार्यरत कर्मचारियों का पदोन्नति कैडर बनाने, वार्षिक वेतनवृद्धि (एनुअल इंक्रीमेंट) भी प्रदान करने, समान कार्य का समान पारिश्रमिक राशि का भुगतान करने,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अन्तर्गत कर्मचारियों का संविलियन करने, ठेका प्रथा एवं निजी एनजीओ को सौंपने की प्रक्रिया को तत्काल समाप्त करने,उन्हें ईपीएफ एवं ईएसआई के दायरे में लाने, सेवानिवृत्त पश्चात् कम से कम 50,हजार रु पेंशन राशि का भुगतान करने,कार्य के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होने पर अथवा सामान्य मृत्यु होने पर रू. 05 लाख की राशि बतौर मुआवजा के रूप में भुगतान करने,सेवानिवृत्त सुविधा (रिटायर बेनिफिट) के रूप में एक मुश्त राशि रू.10 लाख भुगतान करने,अनुभवी आशा वर्कर्स को टीकाकरण के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, उम्र का बंधन हटाते हुये योग्यताधारी आशा वर्कर्स को एएनएम तथा आशा सहयोगिनी फेसिलिटेटर के पद पर पदोन्नति प्रदान करने,वर्ष में दो बार गणवेश (यूनिफार्म) उपलब्ध कराने, अथवा ड्रेसकोड का भुगतान के साथ प्रतिमाह धुलाई भत्ता प्रदान करने,टीकाकरण कार्य के लिये विगत दो दशकों से लागू प्रतिदिन रू. 75 से रू.100 में बढ़ोत्तरी करते हुये रू. 1000 किए जाने, समस्त चिकित्सालयों में विश्रामस्थल (रेस्ट रूम) की व्यवस्था करने, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिये आशा वर्कर्स के द्वारा किये गये सफर, के लिए यात्रा भत्ता (टीए-डीए) का भुगतान करने, असंगठित कामगारों के लिए लागू प्रधानमंत्री श्रमयोगी मागयन लाभार्थी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष ही रखी गई है। इस समयावधि को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करे, ताकि इसका लाभ आशा कर्मचारियोंको प्राप्त हो सके।राज्यस्तरीय स्थानीय मांग पत्र (संलग्न प्रतिलिपि) को यथाशीघ्र लागू करने सहित अपनी अन्य मांगों को पूरा कराने की गुहार लगाई है।

डिलीवरी के वक्त पैसों के लिए परेशान करती है महिला चिकित्सक

आशा कार्यकर्ताओ ने जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर की महिला चिकित्सको पर भी गंभीर आरोप लगाए है।उन्होंने बताया कि महिला सर्जन आशाओं के माध्यम से पैसा लेती हैं।जो आशा पैसे नहीं दिलाती, उनके द्वारा लाए गए केस पर ध्यान नहीं दिया जाता और बाद में उल्टा आरोप आशाओं पर ही लगा दिया जाता है। उनका कहना है कि इस स्थिति में हितग्राहियों को मजबूरन प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है।उन्होंने अस्पताल में होने वाली अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी मांग की है।

स्वास्थ विभाग में सबके लिए बजट है तो हमारे लिए क्यो नही-गीता कटरे

अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता संघ राष्ट्रीय महामंत्री गीता कटरे ने बताया कि आज 5 माह के बकाया मान्यदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर देश भर के करीब 18 प्रदेशो में प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आशा योजना में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र एवं स्थायी समाधान किए जाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि हम वर्ष 2006 से काम कर रहे हैं हमारा मान्यदेय 24000 होना चाहिए लेकिन उसे नहीं बढ़ाया जा रहा है, सेवानिवृत्त होने पर एक साथ 50,000 रु पेंशन के तौर पर मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रही है। महंगाई के इस दौर में पांच-पांच माह का मान्यदेय रोक कर रखा जाता है,हमसे 50 से 60 तरह के काम लिए जाते हैं उसका भुगतान भी नहीं किया जाता, बीएमओ सीएचएमओ से शिकायत करो तो वह कहते हैं कि ऊपर से बजट नहीं आया है स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा विभाग है सभी कर्मचारियों के लिए बजट आता है तो फिर हमारे लिए बजट क्यों नहीं आता. उन्होंने बताया कि हम लोग हंगामा इसलिए मचा रहे थे क्योंकि हम कलेक्टर से मिलकर उन्हें अपनी व्यवस्था सुनना चाहते हैं लेकिन जब भी ज्ञापन लेकर आओ तो, गेट बंद कर दिया जाता है कोई भी आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ज्ञापन दे दो ,ऐसा नहीं चलेगा इसीलिए हमने आज हंगामा मचाया है। इस पर भी यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगामी समय में ठोस रणनीति बनाई जाएगी।

किरनापुर के समर्पित समाजसेवी मंगल प्रसाद रैकवार भोपाल मे हुए सम्मानित

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। प्रदेश की राजधानी भोपाल मे अनादि टीवी न्यूज चैनल भोपाल द्वारा एक भव्य एवं गरिमामयी राज्यस्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमे मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत एवं राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल मुख्य आतिथ्य बतौर आमंत्रित रहे! उनकी इस विशेष गरिमामयी उपस्थिति में प्रदेश के जांबाज पुलिसकर्मियों और समाज के प्रति समर्पित समाजसेवियों को सम्मानित किया गया।इस प्रतिष्ठित मंच पर बालाघाट

जिले के किरनापुर के समर्पित समाजसेवी मंगल प्रसाद रैकवार जी को उनके उत्कृष्ट निस्वार्थ और निरंतर जनसेवा के कार्यों के लिए समर्पित समाजसेवी सम्मान से नवाजा गया है।

अतिथियों ने थपथपाई पीठ, मंगल प्रसाद रैकवार के कार्यों को सराहा

कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत और राज्यसभा सांसद रजनीश अग्रवाल सहित अनादि टीवी न्यूज चैनल एंव कृपलानी ग्रुप के प्रमुख ओमप्रकाश कृपलानी जी ने मंगल प्रसाद रैकवार जी को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथियों ने रैकवार जी के सेवा कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि समाज को ऐसे ही समर्पित और कर्मठ नायकों की आवश्यकता है जो बिना किसी स्वार्थ के अंतिम छोर के व्यक्ति की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

किरनापुर क्षेत्र में हर्ष की लहर

जैसे ही मंगल प्रसाद रैकवार जी को प्रदेश स्तर पर सम्मानित होने की खबर बालाघाट के किरनापुर पहुंची वैसे ही समूचे किरनापुर क्षेत्र में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया। इस बड़ी उपलब्धि पर जिलेवासियों, इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। एवं समाजसेवी मंगल प्रसाद रैकवार को बधाई एवं शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया है।

इनका कहना है

यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि बालाघाट और किरनापुर की देवतुल्य जनता का सम्मान है। यह पुरस्कार मुझे समाज सेवा के पथ पर और अधिक ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणा देगा।

मंगल प्रसाद रैकवार
समाजसेवी, किरनापुर

गुम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मै धर्मेन्द्र पिता शिखरचंद मरकाम उम्र 32 वर्ष ग्राम बुढियागांव थाना लामता जिला बालाघाट(म.प्र.) का निवासी हुं।

मैने 01 जुलाई को अपने पिता श्री शिखरचंद पिता भैयालाल मरकाम उम्र 54 वर्ष को इलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया था, किन्तु 03 जुलाई को 04 बजे मेरे पिता जिला अस्पताल से बिना बताये कही चले गये तलास करने पर भी नही मिले। जिस किसी को मेरे पिता दिखे कृपया उक्त नम्बर पर संपर्क करे।

धर्मेन्द्र मरकाम
ग्राम बुढ़ियागाँव थाना लामता
जिला बालाघाट(म.प्र.)
मों न.- 6265994964,7746923156

अनेक लोगों की अमिट यादें छोड़ गया विशाल बरगद का पेड़

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। बीते दो दिनों से पीडब्ल्यूडी मार्ग पर पुरानी गुजरी चौक किरनापुर मे गिरे विशाल बरगद के पेड़ को हटाने के लिए ग्राम पंचायत किरनापुर द्वारा की जा रही काफी मशक्कत की जा रही हैं। जिसके चलते बड़ी मुश्किल से दो पहिया वाहन चालकों के आवागमन के लिए अब तक मार्ग की बहाली हो पाई है। किन्तु फिर भी पेड़ की कटाई किए जाने के चलते वाहन चालकों द्वारा जबरन आवागमन करने

से दुर्घटना की संभावना बनी हुई हैं। बताए कि बुधवार को पुराने गुजरी चौक किरनापुर मे सुबह 9 बजे विशाल बरगद का पेड़ धराशाही हो गया था जो ग्राम वासियो के लिए अटूट आस्था का केन्द्र भी था। इस पेड़ से अनेक लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। भीषण गर्मी के दिनों मे जहां यह पेड़ राहगीरों को शीतल छांव प्रदान किया करता था तो दूसरी तरफ इस पेड़ की छाँव मे छोटे छोटे दुकानदार अपनी आजीविका चलाकर पेट पालने का काम भी किया करते थे। जैसे कि दीपावली के समय इस पेड़ के नीचे कुम्हार समुदाय के लोग दीपक, माता लक्ष्मी की छोटी छोटी मूर्तियों को बेचने का व्यवसाय किया करते थे तो कुछ लोग रांगोली की दुकान सजाया करते थे। गर्मी के दिनों मे देशी आम एवं जामुन बेचने वाले सहित अन्य छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों द्वारा इसी पेड़ के नीचे बैठकर सामान बेचा करते थे। लेकिन इस विशाल बरगद के पेड़ के गिर जाने से शायद अब वो नजारे फिर से दिखाई ही ना दे। कई लोगों के लिए अमिट यादें छोड़ गया गुजरी चौक का बरगद का विशाल पेड़ जिसके पी डब्ल्यू डी मार्ग पर गिर जाने से विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को इसे हटाए जाने की सूचना दिए जाने के बावजूद भी मार्ग से हटाने की पहल नहीं की गई। इसके चलते उक्त स्थल से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया था। जिस पर ग्राम पंचायत किरनापुर प्रबंधन द्वारा पहल करते हुए कर्मचारियों के माध्यम से हटाए जाने का काम किया जा रहा हैं।

सीमा तक सड़क पहुंची, लेकिन मेरा गांव आज भी इंतजार में, पूर्व सैनिक ने पक्के मार्ग के लिए लगाई गुहार

किरनापुर से सिर्फ 3 किमी दूर ग्राम जराही तक आज भी नहीं पहुंची पक्की सड़क , बरसात में 2,500 ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। जिले की किरनापुर तहसील से महज तीन किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जराही पहुच मार्ग आज भी पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। आजादी के लगभग 79 वर्ष बाद भी गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को कच्चे और बदहाल मार्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में यह रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे गांव तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं रहता। इस गंभीर समस्या को लेकर भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार तोमेश्वर रहांगडाले ने शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है। पूर्व सैनिक तोमेश्वर रहांगडाले ने बताया कि उन्होंने भारतीय सेना में लगभग 20 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। सेना में रहते हुए उन्होंने देश के कई दुर्गम एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान राष्ट्र की रक्षा करते हुए गंभीर चोटें भी झेलीं, जिसमें उनकी रीढ़ की हड्डी और पसलियों में चोट आई। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद जब वे अपने पैतृक गांव लौटे तो उन्हें सबसे अधिक पीड़ा इस बात की हुई कि उनका गांव आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। उन्होंने कहा कि जिन सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में उन्होंने देश की सेवा की, वहां तक सड़कें बन चुकी हैं, लेकिन उनका अपना गांव आज भी विकास की राह देख रहा है। उनका कहना है कि यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे ग्रामीणों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सूबेदार रहांगडाले ने बताया कि ग्राम जराही की आबादी लगभग 2,500 है। गांव को तहसील मुख्यालय किरनापुर तथा मुख्य लांजी-बालाघाट मार्ग से जोड़ने वाली करीब दो किलोमीटर सड़क आज भी कच्ची है। ग्रामीणों को बड़गांव जोड़ मार्ग के माध्यम से आवागमन

करना पड़ता है। बारिश के मौसम में यह रास्ता कीचड़ से भर जाता है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं गर्मी और अन्य मौसम में सड़क पर उड़ने वाली धूल लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। उन्होंने बताया कि सड़क नहीं होने से सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, किसानों, बुजुर्गों और मरीजों को उठानी पड़ती है। बरसात के दौरान कई बार वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में भी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में विलंब होता है और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। पूर्व सैनिक ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार जनसुनवाई में आवेदन दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी सड़क निर्माण की मांग रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। वर्षों बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के मुख्य पहुंच मार्ग के अभाव में उन्हें प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में सड़क पूरी तरह खराब हो जाती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, किसानों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो आने वाले समय में आंदोलन करने पर भी विचार किया जाएगा। सूबेदार तोमेश्वर रहांगडाले ने मुख्यमंत्री, क्षेत्रीय विधायक, सांसद एवं जिला प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्राम जराही को तहसील मुख्यालय और मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क का शीघ्र डामरीकरण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क बनने से न केवल गांव के 2,500 ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि विद्यार्थियों, किसानों, मरीजों और आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि वर्षों पुरानी इस मांग पर शासन-प्रशासन गंभीरता से विचार करेगा और जल्द ही गांव को पक्की सड़क की सौगात मिलेगी।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला बालाघाट (म.प्र)

क्रमांक / 5194/ अति.कले./वि.अधि./2026
बालाघाट दिनांक 08/06/2026

आम-सूचना

हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विवाह पंजीयन हेतु आवेदकगण हिताय खोब्रागडे उम्र-23 वर्ष पिता श्री सुरेश खोब्रागडे जाति महार निवासी ग्राम कनेरी ,पो. लवेरी, तह. किरनापुर जिला बालाघाट (म.प्र) एवं आवेदिका निकिता शेन्द्रे उम्र 24 वर्ष पिता श्री बारेलाल शेन्दे जाति अहीर निवासी ग्राम कनेरी,पो. लवेरी, तह. किरनापुर जिला बालाघाट (म.प्र) ने उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे उन्हे विवाह पंजीयन जारी किया जाना है विवाह पंजीयन हेतु सुनवाई दिनांक 10/07/2026 को नियत की गई है।अत: उक्त विवाह पंजीयन के सबंध में जिस किसी भी व्यक्ती को कोई आपत्ति है तो वह सुनवाई 10/07/2026 तक न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी बालाघाट के समक्ष न्यायालयीन समय प्रात: 10:00 बजे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत करें। नियत समयवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

अपर कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार
हिन्दु,विवाह जिला बालाघाट

बारबेड वायर (कांटेदार तार) एवं चेन लिंक जाली उचित दाम पर उपलब्ध

लघु उद्योग निगम भोपाल से संबद्ध

निर्माता
तिरूपति इंजीनियरिंग वर्क्स
मयूर टॉकिज के सामने हनुमान चौक, बालाघाट
फोन:- 07632-243531
मो:- 8989976858, 9425139998

बालाघाट सिटी न्यूज़

पद्मेश न्यूज
बालाघाट एक्सप्रेस
/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

राज्य पुरस्कार स्काउट-गाइड जांच शिविर का जिला शिक्षा अधिकारी ने किया आकस्मिक निरीक्षण

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार 6 से 10 जुलाई 2026 तक जिला प्रशिक्षण केंद्र, वारासिवनी में आयोजित राज्य पुरस्कार स्काउट-गाइड जांच शिविर के तीसरे दिन 08 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनश्री जैन ने शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया। शिविर पहुंचने पर स्काउट-गाइड कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर, स्कार्फ पहनाकर तथा जनरल सैल्यूट के साथ सम्मानपूर्वक स्वागत किया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति के सौंदर्यीकरण का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान श्रीमती जैन ने जिला प्रशिक्षण केंद्र के विभिन्न कक्षों का अवलोकन किया तथा स्काउट-गाइड प्रतिभागियों से सीधे संवाद कर प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्काउटिंग, सु-नागरिकता, अनुशासन एवं सेवा भावना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को जीवन में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राज्य पुरस्कार जांच शिविर में शामिल सभी स्काउट-गाइड को सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। जिला परियोजना समन्वयक श्री मोहित डहरिया ने प्रतिभागियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 6 से 10 जुलाई तक आयोजित इस राज्य पुरस्कार जांच शिविर में कुल 80 स्काउट-गाइड भाग ले रहे हैं, जिनमें भोपाल के 16, विदिशा के 6, जबलपुर के 14 तथा सर्वाधिक 41 प्रतिभागी बालाघाट जिले से शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिविर की व्यवस्थाओं एवं प्रशिक्षण की सराहना करते हुए जिले के सभी विद्यालयों में स्काउट-गाइड गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। शिविर का संचालन शिविर संचालक श्री रमेश बारिया के नेतृत्व में किया जा रहा है। सहायक शिविर संचालक के रूप में रामचंद्र सोलंकी, नायक राजपूत, श्रीमती सायराबानो, सुश्री निर्मला बेनर्जी एवं श्रीमती रिजवाना परवीन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बालाघाट जिले में शिविर के संचालन की जिम्मेदारी जिला संगठन आयुक्त इनेंद्र डहरवाल निभा रहे हैं। इस अवसर पर जिलासंघ बालाघाट के कोषाध्यक्ष भेजेंद्र चौधरी, डीटीसी डोलीराम भगत, सचिव राजकुमार टेमरे, सोहनलाल पटले, सुरेंद्र सिंह पंद्रे, नंदकिशोर आड़े, भुनेंद्र सौलेकर, श्रीमती लक्ष्मी विष्णु पटले, श्रीमती नीता बोपचे, श्रीमती रत्नमाला गौरे सहित अन्य जिलों से आए स्काउटर-गाइडर संजू मेवाड़े, शुभम ठाकुर, भागीरथ शर्मा, श्रीमती फरहद खान, श्रीमती निशा शेंडांगे तथा कुमारी रितिका कुशवाहा उपस्थित रहे।

भाजपा में आरोप बनाम जवाब की जंग तेज, अध्यक्ष ने सुधीर चिले के सभी आरोपों को किया खारिज

नपा. अध्यक्ष बोलीं- टेंडर से लेकर विकास कार्य तक सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी, सबूत हो तो सामने लाएं, पीआईसी सदस्यों ने कहा- सुर्खियां बटोरने के लिए लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

नगर पालिका परिषद बालाघाट में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। जहां पहले नगर पालिका में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता था, वहीं अब भाजपा के पार्षद और पदाधिकारी ही एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। एक दिन पूर्व वार्ड क्रमांक-16 के भाजपा पार्षद सुधीर चिले द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष सहित प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों पर वार्ड के विकास कार्य रोकने, पक्षपात करने, ठेकेदारी कराने तथा गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के बाद 9 जुलाई को नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने सभापतियों के साथ प्रेसवार्ता आयोजित कर सभी आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। नगर पालिका अध्यक्ष के कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में अध्यक्ष भारती ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि पार्षद सुधीर चिले द्वारा लगाए गए सभी आरोप तथ्यहीन, निराधार और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी प्रणाली के तहत संपन्न होती है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिस ठेकेदार के दस्तावेज पूर्ण होते हैं और जिसकी निविदा दर निम्नानुसार सबसे कम होती है, उसी को कार्य आवंटित किया जाता है। इसलिए यह कहना कि अध्यक्ष की मर्जी से किसी विशेष व्यक्ति या पार्षद को टेंडर दिए जा रहे

हैं, पूरी तरह निराधार है।

अध्यक्ष भारती ठाकुर ने भारत माता की प्रतिमा को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि भारत माता की फाइबर प्रतिमा की कुल लागत लगभग 2 लाख 27 हजार रुपये है, जिसमें प्रतिमा निर्माण से लेकर छत्र तैयार करने तथा रंग-रोगन तक का पूरा कार्य मूर्तिकार द्वारा किया जाना है। इसके लिए नगर पालिका को अलग से रंग-रोगन पर कोई अतिरिक्त राशि खर्च नहीं करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस विषय में भी बिना तथ्य के जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रेसवार्ता के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने पार्षद सुधीर चिले के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके वार्ड क्रमांक-16 में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। अध्यक्ष ने मीडिया के सामने संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि वार्ड में कई विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि कई कार्य स्वीकृत होकर प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और नगर पालिका सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्षद द्वारा लगाए गए आरोपों की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और वरिष्ठ नेताओं को भी दे दी गई है। संगठन पूरे मामले से अवगत है और पार्टी स्तर पर भी इस विषय पर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। प्रेसवार्ता में मौजूद प्रेसिडेंट इन काउंसिल सदस्य वकील वाधवा ने भी पार्षद सुधीर चिले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका का कोई भी सभापति ठेकेदारी और सप्लाई का कार्य नहीं कर रहा है। उनके अनुसार यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और बिना किसी प्रमाण के लगाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सभापति पद से हटाए जाने के बाद सुर्खियों में बने रहने और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सभापति संगीता खगेश कावरे ने भी पार्षद द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की भाषा और आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं, वह न केवल असत्य हैं बल्कि महिला सम्मान के भी विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि यदि वह चाहतीं तो पार्षद सुधीर चिले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मामला दर्ज करा सकती थीं, लेकिन पार्टी अनुशासन और संगठन का सम्मान करते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रमाण के किसी की छवि धूमिल करना उचित नहीं है और इस प्रकार की राजनीति से संगठन की छवि भी प्रभावित होती है। नगर पालिका अध्यक्ष और सभापतियों ने संयुक्त रूप से कहा कि नगर पालिका में सभी कार्य नियमानुसार और पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। किसी भी पार्षद के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और यदि किसी को किसी विषय पर आपत्ति है तो उसे संगठन और वैधानिक मंच पर उठाना चाहिए, न कि मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाना चाहिए। इधर, भाजपा के भीतर खुलकर सामने आए इस विवाद ने नगर पालिका की राजनीति को गर्मा दिया है। एक ओर भाजपा पार्षद सुधीर चिले नगर पालिका की कार्यप्रणाली, ठेकेदारी और विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर नगर पालिका अध्यक्ष और पीआईसी सदस्य सभी आरोपों को निराधार बताते हुए दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में पार्टी संगठन क्या रुख अपनाता है और अंदरूनी विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

कुए की जहरीली गैस ने फिर छीनी दो जिंदगी

कुएं में मोटर सुधारने उतरे 2 लोगों की जहरीली गैस से मौत, किरनापुर के ग्राम दहेदी के पिपरटोला का मामला, गांव में मातम, अब तक 4 लोगो की जहरीली गैस से हो चुकी है मौत

पद्मेश न्यूज। किरनापुर। जिले में जहरीली गैस के संपर्क में आने से लोगों की हो रही मौत के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।जहां कुएं में उतरने के पहले जहरीली गैस की जांच ना करना, लोगों के लिए मौत का सबब बन रहा है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन्ही, मामलों के बीच के किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दहेदी के पिपरटोला में गुरुवार की शाम जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों व्यक्ति मोटर सुधारने कुएं में उतरे थे,जो जहरीली गैस के संपर्क में आ गए,जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।मृतको के नाम पीपरटोला टोला निवासी 45 वर्षीय महेश पिता भरत लाल चौधरी और 55 वर्षीय युवराज पिता चंदन लाल बिसेन बताया गया है। जिनके शव का पोस्टमार्टम करने के लिए अस्पताल लाया गया है।घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

जहरीली गैस के सम्पर्क में आने से बिगड़ी दोनों की हालत, मौके पर हुई मौत

प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जुलाई गुरुवार की शाम करीब 5:30 बजे, ग्राम पिपरटोला निवासी महेश चौधरी एवं युवराज बिसेन कुएं में लगी मोटर सुधारने के लिए कुए में नीचे उतरे थे। इसी दौरान कुएं के भीतर मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आने से दोनों की हालत बिगड़ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर एकत्र हो गए। जिन्होंने मामले की सूचना तत्काल किरनापुर थाना प्रभारी राजकुमार चौधरी को दी।जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।दोनों शवों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम बालाघाट से घटनास्थल पहुंची।जिन्होंने दोनों व्यक्ति के शव को कुए से निकाल कर पुलिस के सुपुर्द किया है।घटर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

अब तक जहरीली गैस से जिले में हो चुकी है चार मौत

आपको बताएं की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत होने का यह कोई पहला मामला नहीं है बल्कि इसके पूर्व भी जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो लोगों की मौत हो चुकी है।जानकारी के मुताबिक जिले में पिछले 15 दिनों के भीतर कुएं की जहरीली गैस से मौत का यह तीसरा मामला है और अब तक कुल 04 लोगों की जान जा चुकी है।ज्ञात हो कि इससे पहले 25 जून को सितकुटोला में लक्ष्मण लिल्हारे की जहरीली गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई थी, तो वही 7 जुलाई को भरवेली के मरारीटोला में अशोक कावरे की भी इसी तरह कुएं की गैस की वजह से मौत हो गई थी।अब किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दहेदी के पिपरटोला में जहरीली गैस के संपर्क में आने से एक साथ दो लोगो की मौत हो चुकी है।बार-बार हो रहे इन हादसों से मृतकों के परिवारों सहित पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है।

अवैध संबंध ने उजाड़ा परिवार- पत्नी को 11 केवी करंट से मौत के घाट उतारने वाले पति को आजीवन कारावास

विशेष न्यायाधीश गौतम सिंह मरकाम की अदालत का फैसला

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश गौतम सिह मरकाम की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी नेमीचंद पिता ओमकार शरणागत 37 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बैहर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम तुमड़ीभाट निवासी इस आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी पुष्पलता की एक साजिश के तहत विद्युत करंट से हत्या करने का आरोप था।विद्वान अदालत ने इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 7 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किए हैं।

अभियोजन के अनुसार 22 मार्च 2024 को सुबह ग्राम तुमड़ीभाट शासकीय स्कूल के आगे महुआ के पेड़ के पास झाड़ियों में एक महिला की लाश देखी गई थी इसके आसपास करंट के तार जले हुए दिखे रहे थे। खबर फैलते गांव के वहां पर पहुंच गए महिला की पहचान पुष्पलता शरणागत के नाम से की गई जिसकी करंट लगने से मौत होने की संभावना व्यक्त की गई। मृतिका की पुत्री आरशी शरणागत मौके पर पहुंची और उसे आरोपी नेमीचंद द्वारा पत्नी पुष्पलता की विद्युत करंट से मारकर हत्या करने जानकारी दी गई थी। जिसने बैहर थाना में रिपोर्ट की गई थी। जहां मर्ग जांच उपरांत यह घटना सामने आई थी। नेमीचंद तुमड़ीभाट में अपनी पत्नी पुष्पलता और बच्चों के साथ ग्राम तुमड़ीभाट में रहता था और वह इलेक्ट्रिशियन का कार्य करता था जबकि उसकी पत्नी पुष्पलता घर के सामने छोटी सी किराना दुकान चलती थी और सिलाई का काम भी करती थी।

अवैध संबंध के शक में रची खौफनाक साजिश

पुष्पलता को अपने पति नेमीचंद पर शक था कि उसका अवैध संबंध मंजूलता से है। नेमीचंद ने अपनी पत्नी पुष्पलता को रास्ते से हटाने के लिए उसे जान से मारने की योजना बनाई। 21 मार्च 2024 को दिन के 2:30 बजे से 3:00 बजे के मध्य नेमीचंद ने असाटी प्लाईवुड एवं हार्डवेयर कम्पाउंडरटोला बैहर की दुकान से 1 किलो लोहे का सेंटरिंग तार और दो गुच्छी लाइन डोरी रेशम का सफेद धागा लिया और अपनी पत्नी पुष्प लता की हत्या करने के आशय से उसने महुआ झाड़ के पास झाड़ियां में लपेटकर बिछा दिया और तार के एक छोर को रेशम के सफेद धागे से बांधकर 11 के व्ही विद्युत लाइन के ऊपर से धागा निकालकर रोड किनारे बारहमासी में बांध दिया और घर आकर खाना खाने के पश्चात पत्नी पुष्पलता से कहा कि वह रात 10:30 बजे महुआ झाड़ के पास मंजूलता को बुला रहा है। वहा चलकर अपने मन का समाधान कर ले। और उसने पुष्प लता से कहा कि जब तक मंजूलता ना आए वह झाड़ियों में जाकर छुपी रहे। जैसे ही पुष्पलता झाड़ियां के पास गई तभी आरोपी नेमीचंद ने रेशम के धागे को खींचकर लोहे के सेंटरिंग जी आई तार को 11 के व्ही विद्युत लाइन से जोड़ दिया। जिसके करंट के चपेट में आने से पुष्पलता को करंट लगा और उसकी वही मौत हो गई। तार में फाल्ट आने से वहां पर अंधेरा हो गया। इसके बाद आरोपी नेमीचंद ने वहां से भाग कर घर में आकर सो गया। और दूसरे दिन 22 मार्च को सुबह घटना में प्रयुक्त सामग्री को घर में लाकर छिपा दिया और बैहर चला गया। इसके बाद शासकीय स्कूल के आगे महुआ के पेड़ के पास पुष्पलता की लाश बैहर पुलिस द्वारा बरामद की गई।

नेमीचंद को किया गया गिरफ्तार- अदालत ने सुनाई सजा

मर्ग जांच उपरांत इस मामले में नेमीचंद के विरुद्ध धारा 302 और 201 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया और विवेचना अनुसंधान उपरांत विद्वान अदालत में अभियोग पत्र पेश किया गया था। यह मामला बालाघाट के विद्युत अधिनियम के विद्वान विशेष न्यायाधीश गौतम सिह मरकाम की विद्वान अदालत में चला। जहां अभियोजन पक्ष आरोपी नेमीचंद के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत में मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी नेमीचंद शरणागत को पत्नी की हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 201 भादवि के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किये। इस मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रदीप सोनी द्वारा की गई थी।

10 साल से जस की तस समस्या-हल्की बारिश में जिला अस्पताल की पुलिस चौकी और जिला क्षय केंद्र के सामने भर जाता है पानी

जलभराव से फैलती है गंदगी और दुर्गंध, मरीजों, कर्मचारियों और आम लोगों को हर बारिश में उठानी पड़ रही परेशानी, अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी बरकरार

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शहीद भगत सिंह शासकीय जिला अस्पताल परिसर में एक ओर जहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं वहीं दूसरी ओर अस्पताल परिसर की मूलभूत व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं। जिला अस्पताल पुलिस चौकी और जिला क्षय केंद्र (टीबी कार्यालय) के सामने हल्की बारिश होते ही जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। बारिश का पानी घंटों तक जमा रहने से आसपास की गंदगी और कचरा भी उसी पानी में एकत्र हो जाता है। जिससे दुर्गंध फैलने लगती है और पूरे परिसर का वातावरण अस्वच्छ हो जाता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह समस्या एक-दो दिन या एक-दो वर्ष पुरानी नहीं, बल्कि लगभग 10 वर्षों से लगातार बनी हुई है। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन की ओर से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने या स्थल का दोबारा समतलीकरण कराने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। परिणामस्वरूप हर बारिश के साथ यही स्थिति दोहराई जाती है और मरीजों, उनके परिजनों, कर्मचारियों तथा पुलिसकर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार जिस भवन में जिला अस्पताल पुलिस चौकी संचालित है। उसी से लगे कक्ष में जिला क्षय केंद्र का कार्यालय भी संचालित होता है। प्रतिदिन यहां टीबी मरीजों सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक, अस्पताल कर्मचारी और पुलिस अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यालयों के सामने जलभराव होना न केवल लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करता है। बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर चिंता का विषय है।

निर्माण कार्य में लापरवाही बनी समस्या की जड़

स्थानीय कर्मचारियों और जानकारों के अनुसार करीब 10 वर्ष पहले जिला अस्पताल

परिसर में समतलीकरण और गट्टू लगाने का कार्य कराया गया था। उस समय अधिकांश परिसर को समतल किया गया।लेकिन इस भवन के सामने मौजूद चिचले हिस्से को समुचित रूप से भरकर समतल नहीं किया गया। पुराने गड्ढेनुमा स्थान पर ही पेवर ब्लॉक बिछा दिए गए। जिससे बारिश का पानी निकलने के बजाय वहीं जमा होने लगा। निर्माण कार्य के दौरान बरती गई यह लापरवाही आज भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।

गंदगी और दुर्गंध से बिगड़ता है अस्पताल का माहौल

बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी में आसपास का कचरा, पत्तियां और अन्य गंदगी भी बहकर आ जाती है। इससे कुछ ही समय में पानी बदबूदार हो जाता है और पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैलने लगती है। अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में इस प्रकार का वातावरण मरीजों के स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं माना जा सकता। स्वच्छता अभियान और संक्रमण नियंत्रण के दावों के बीच यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है। जलभराव के कारण मरीजों, उनके परिजनों, पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार फिसलने का खतरा भी बना रहता है। बरसात के दिनों में यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है, जिससे कार्यालयों तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है। विशेष रूप से बुजुर्ग मरीजों और दिव्यांगजनों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रबंधन को जानकारी- फिर भी समाधान नहीं

अस्पताल परिसर में वर्षों से बनी इस समस्या की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी है। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। यदि समय रहते उचित ढलान बनाकर जल निकासी की व्यवस्था कर दी जाती या दोबारा समतलीकरण कराया जाता, तो इस समस्या से आसानी से निजात मिल सकती थी।

स्थायी समाधान की आवश्यकता

जिला अस्पताल पूरे जिले का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है। जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में परिसर की स्वच्छता, सुरक्षित आवागमन और बेहतर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लगातार 10 वर्षों से चली आ रही इस समस्या का शीघ्र स्थायी समाधान किया जाना आवश्यक है।ताकि मरीजों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को राहत मिल सके तथा अस्पताल परिसर स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बना रहे।

ममता फाउंडेशन ने ग्राम बांदरी में किया पौधरोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बांदरी में ममता फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों, युवाओं और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और लगातार घटते वन क्षेत्र को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। केवल पौधारोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौधों की नियमित देखरेख और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि लगाए गए पौधे भविष्य में बड़े वृक्ष बनकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस अवसर पर श्री बुद्ध सिंह उईके, संदीप शरणागत, अखिलेश क्षीरसागर, अंकुश चौरे, जितेंद्र पटेल, राहुल परते, रंजीत भलावी, राजू इनवाती, दीपक बिसेन, जागेश्वर गौतम , सोमेश एवं अमन गजभिए सहित संस्था से जुड़े सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। सभी ने पौधारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का आह्वान किया।

थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों के तोड़े ताले

नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद, पुलिस फुटेज खंगालने में जुटी

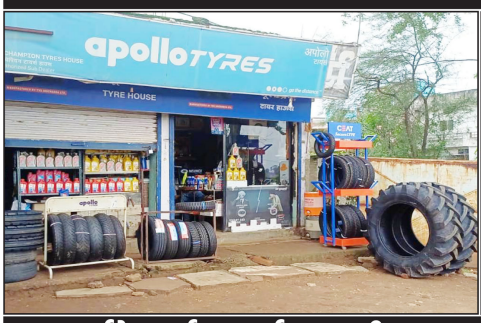

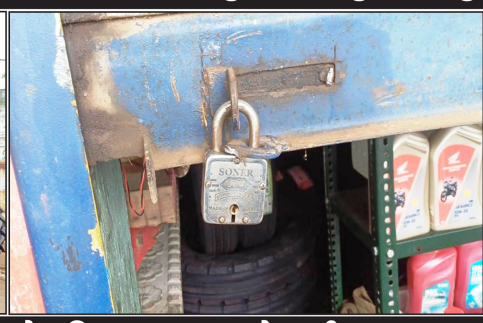

हाईवे मार्ग पर हुई इस बड़ी वारदात से पुलिस गश्त पर उठे गंभीर सवाल, दुकानदार और व्यापारियों में आक्रोश

रिपोर्टर।
पदमेश न्यूज। लालबर्रा।

नगर मुख्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लालबर्रा से बालाघाट एवं लालबर्रा से सिवनी हाईवे मार्ग पर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोर लाखों रुपये की सामग्री और नगद राशि लेकर फरार हो गये । हाईवे जैसे मुख्य मार्ग और थाने के इतने नजदीक हुई इस वारदात से स्थानीय व्यापारियों और आम जनता में पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दे कि बुधवार और गुरुवार की बीती रात्रि में अज्ञात चोरों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने स्थित श्रीराम कंप्यूटर सेंटर, सिवनी मार्ग मजार के आगे स्थित चैम्पियन टायर की दुकान, लहरी मोटर पार्ट्स की दुकान और सा ताज मिल को अपना निशाना बनाया। चोरों ने इन चारों दुकानों के ताले तोड़कर अंदर रखी सामग्री को बुरी तरह से तोड़फोड़ कर नुकसान पहुँचाया और दुकानों में रखी नगद राशि सहित लाखों रूपये का कीमती सामान लेकर फरार हो गये । गुरुवार की सुबह जब दुकान संचालकों को घटना की जानकारी मिली, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस चोरी से दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। वही चैम्पियन टायर दुकान के अंदर से नगद 22 हजार पांच सौ रूपये एवं अन्य दुकानों से भी नगद राशि एवं लाखों रूपये की सामग्री को नुकसान पहुंचाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।

सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर

चोरी की यह पूरी वारदात श्री राम कम्प्यूटर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हालांकि, चोरों ने चतुराई दिखाते हुए अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था, जिसके कारण उनके चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही लालबर्रा पुलिस मौके पर पहुँची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाल रही है ताकि चोरों का पता लगाया जा सके।

पुलिस गश्त पर उठे सवाल, सख्त कार्यवाही की मांग

थाने से कुछ ही दूरी पर और मुख्य हाईवे रोड पर एक साथ चार दुकानों में चोरी होने से स्थानीय लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर गहरा रोष है। जागरूक नागरिकों का कहना है कि यदि मुख्य मार्ग पर ही दुकानें सुरक्षित नहीं हैं, तो अंदरूनी इलाकों का क्या हाल होगा? पीड़ित दुकानदारों सहित क्षेत्र के समस्त व्यापारियों एवं पीड़ित दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अज्ञात नकाबपोश चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की जाये। साथ ही क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये। वही पुलिस ने पीड़ित दुकानदारों की शिकायत पर अज्ञात चोरो के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओ के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी हैं।

गल्ले में रखे नगद 22500 रूपये ले गये चोर - उत्पल

चैम्पियन टायर दुकान के संचालक उत्पल वैदिक पटले ने बताया कि मेरी टायर, बैटरी और ऑयल की दुकान है और मैं रोज की तरह सुबह लगभग 10 बजे अपनी दुकान खोलने पहुंचा था, जैसे ही मैं सुबह काउंटर खोलने आया, तो मैंने देखा कि शटर के दोनों ताले और कुंदे टूटे हुए थे, यह देखकर मैं हैरान रह गया। वहीं जब मैंने दूसरा शटर खोलकर अंदर देखा, तो काउंटर के पास सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और चोरों ने दुकान के गल्ले को पूरी तरह खंगाल गल्ले में रखे 22500 रूपये नगद लेकर फरार हो गये। श्री पटले ने बताया कि चोरो के द्वारा जो राशि दुकान से चोरी की गई है, वह किसी को देने के लिये मेरे द्वारा दुकान में रखी गई थी। मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे है, परंतु आसपास में लगे सीसीटीव्ही कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो उसमें चोर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी चोरों ने पूरी तरह से चेहरा ढका हुआ है, जिसके कारण उनको पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की छानबीन - नितिन

कम्प्युटर दुकान संचालक नितिन भारद्वाज ने बताया कि रोज़ाना की तरह सुबह करीब 9:30 बजे जब अपनी दुकान खोलने पहुंचे, तो उन्होने देखा कि दुकान का बोर्ड जो उनके द्वारा रोज़ रात को दुकान बंद करने के पहले अंदर दुकान में रखा जाता है, वह बोर्ड सुबह बाहर निकला हुआ था, जिसके बाद उन्हे शक हुआ और उन्होने ताले की तरफ नजर दौड़ाई, तो दुकान की सांकल कटी हुई थी, जिससे उन्हे दुकान में चोरी का आभास हुआ। श्री भारद्वाज ने बताया कि चोरों ने बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है और उनके द्वारा दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के रुख (दिशा) को ऊपर की ओर मोड़ दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद चोर दुकान के भीतर दाखिल हुए और पैसों वाले ड्रॉअर (गल्ले) को खोलकर अच्छी तरह से खंगाला। साथ ही कुछ अन्य सामानों को भी टटोला, लेकिन नकदी और कोई कीमती चीज हाथ न लगने पर चोरों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। श्री भारद्वाज ने बताया कि मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम सें ज्ञात हुआ है कि चोरों ने उसी रात क्षेत्र में कुछ अन्य जगहों पर भी इसी तरह ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया है। दुकान के भीतर दो और बाहर एक कैमरा लगा हुआ हैं और सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

पोस्ट ऑफिस में आधार अपडेट के नाम पर अवैध वसूली

मामला उजागर होने पर ऑपरेटर ने लौटाए रूपये, मामला लालबर्रा पोस्ट ऑफिस का

पदमेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय स्थित उपडाकघर में आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर हितग्राहियों से अवैध वसूली का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। शासन के नियमों को ताक पर रखकर बच्चों के नि:शुल्क आधार कार्ड बनाने के बदले

भी अवैध रूप से रुपयों की मांग की जा रही थी। मामला उजागर होने और मीडिया की सक्रियता के बाद डरे हुए ऑपरेटर ने हितग्राही के पैसे तो वापस कर दिए। लेकिन इस घटना ने पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार केवाटोला (कंजई) निवासी कुमारी चारवी पिता राजेश ठकरेले गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे अपना आधार कार्ड अपडेट कराने अपने पिता के साथ लालबर्रा पोस्ट ऑफिस पहुंची थीं। टोकन नंबर 23 पर उनके आधार अपडेशन का कार्य किया गया। कार्य पूरा होने के बाद काउंटर पर मौजूद कम्प्यूटर ऑपरेटर राहुल जामरे द्वारा अपडेशन शुल्क के रूप में अवैध रूप से उनसे 125 रुपये की मांग की गई। वही आवेदिका के पिता के पास चिल्लर न होने के कारण उन्होंने ऑपरेटर को 130 रुपये दिये। इस पर ऑपरेटर ने 5 रुपये वापस करने के बजाय केवल 10 रुपये लौटाए। ऑपरेटर के इस अजीब और संदेहास्पद व्यवहार से आशंकित होकर आवेदिका के पिता सीधे उप डाकपाल अधिकारी के पास पहुंचे और नियमों की जानकारी ली। जैसे ही पीड़ित ने उप डाकपाल से इस संबंध में पूछताछ और शिकायत की, डाकघर परिसर में हड़कंप मच गया। मामले की जांच में शिकायत पूरी तरह सही पाई गई, जिसके बाद उप डाकपाल अधिकारी ने कंप्यूटर ऑपरेटर को कड़ी फटकार लगाई। खुद को घिरता देख ऑपरेटर राहुल जामरे ने अपनी गलती स्वीकार किया और आवेदिका के पिता को तत्काल 120 रुपये वापस लौटा दिया। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह क्षेत्र के कई अभिभावक अपने ब%चों का आधार कार्ड बनवाने आये थे। नियमानुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नया आधार कार्ड पूरी तरह नि:शुल्क बनता है और सिस्टम से निकलने वाली रसीद पर भी शून्य या नि:शुल्क लिखा होता है। इसके बावजूद कंप्यूटर ऑपरेटर हितग्राहियों से अवैध राशि वसूल रहा था। जब कुछ ग्रामीणों ने राशि लेने का विरोध किया, तो ऑपरेटर के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने डाकघर प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लालबर्रा पोस्ट ऑफिस में रोजाना औसतन 50 से अधिक आधार कार्ड अपडेट और नये आधार कार्ड बनाये जाते हैं। जागरूक नागरिकों और मीडिया की सक्रियता से यह मामला तो उजागर हो गया, लेकिन अंदेशा जताया जा रहा है कि रोजाना सीधे-साधे और अनपढ़ ग्रामीणों से आधार के नाम पर मोटी रकम की अवैध वसूली कर बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि डाक विभाग के उ%च अधिकारी ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट कर्मियों पर क्या ठोस और दंडात्मक कार्यवाही करते हैं, ताकि भविष्य में गरीब ग्रामीणों को इस तरह की लूट का शिकार न होना पड़े।

ऑपरेटर के द्वारा गलती से ली गई है राशि-उपडाकपाल

उपडाकपाल श्रीमती वर्षा वरकड़े ने बताया कि डाकघर में आधार अपडेशन और नए नामांकन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है और रोज लोग आधार से संबंधित काम के लिये डाकघर पहुंच रहे। इस अपडेशन कार्य में एक ब' ची के अनिवार्य आधार अपडेट के दौरान ऑपरेटर के द्वारा गलती से 120 ले लिये गये है, जबकि वसूली गई इस राशि का रसीद में कोई उल्लेख या प्रिंट नहीं था। श्रीमती वरकड़े ने बताया कि नियमों के तहत यह अपडेट पूरी तरह निशुल्क होना चाहिए था, लेकिन ऑपरेटर ने हितग्राही से शुल्क लिया है जिसके हम क्षमा मांगते है और संबंधित हितग्राही को राशि वापस कर दी गई है। यह हमारे डाकघर का पहला और एकलौता मामला है जो मेरे संज्ञान में आया है। रसीद न देखने के कारण यह असमंजस पैदा हुआ। साथ ही यह भी बताया कि आधार से संबंधित कार्यों के शुल्क के संबंध में पूर्व में रेट लिस्ट लगाई गई थी, परंतु बारिश के कारण वह खराब होकर निकल गई। आम जनता की सुविधा के लिए जल्द ही नई रेट लिस्ट परिसर में लगवा दी जाएगी। उपडाकपाल श्रीमती वरकड़े ने आम जनता को आश्वस्त किया है कि ब' चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, केवल वयस्कों के लिए ही नियमानुसार शुल्क निर्धारित है। भविष्य में इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति नही होगी।

विधायक अनुभा मुंजारे ने किया खमरिया सब स्टेशन का निरीक्षण

स्टेशन में जलभराव पर ठेकेदार को लगाई फटकार, बस्ती के लिए अलग फीडर लगाने किया निर्देशित

पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय से लगभग 8 किमी दूर स्थित विद्युत सब स्टेशन खमरिया का क्षेत्रीय विधायक अनुभा मुंजारे के द्वारा बुधवार को क्षेत्रीय जनता और किसानों को हो बिजली की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आई। निरीक्षण के दौरान सब स्टेशन परिसर में जलभराव की स्थिति देख विधायक ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित ठेकेदार को पानी निकासी के लिए तत्काल उचित उपाय करने के सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि खमरिया के ग्रामीण और किसान पिछले कई दिनों से अघोषित बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या से जूझ रहे थे, जिससे फसलों की सिंचाई और रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे थे, उनके द्वारा अनेक बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई परंतु समाधान नहीं हो पाया। जिसके बार जनता के द्वारा क्षेत्रीय विधायक श्रीमती मुंजारे को अपनी समस्या से अवगत करवाया गया और जनता की इस परेशानी को देखते हुए विधायक स्वयं अधिकारियों की टीम के साथ सब स्टेशन का जायजा लेने पहुँची और उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जनता को बिजली संकट से राहत दिलाना उनकी प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं ग्रामीणों के द्वारा भी अपनी समस्याएं सीधे विधायक के समक्ष रखीं गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विधायक ने अधिकारियों को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।

खमरिया बस्ती के लिए बनेगा अलग फीडर, वोल्टेज समस्या होगी दूर

निरीक्षण के दौरान विधायक श्रीमती मुंजारे ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में बिजली सप्लाई की लचर व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की। खमरिया बस्ती में लंबे समय से बनी हुई लो-वोल्टेज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने अधिकारियों को इसका स्थाई समाधान करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही, बस्ती की विद्युत व्यवस्था को सुचारू और मजबूत बनाने के लिए विधायक ने खमरिया बस्ती हेतु अलग से एक नया फीडर तैयार करने के निर्देश दिए और इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव प्रेषित करने को कहा गया। इस महत्वपूर्ण औचक निरीक्षण के अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि, विद्युत विभाग के आला अधिकारी व कर्मचारी, खमरिया ब्लॉक के बड़ी संख्या में किसान भाई और स्थानीय ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

खेत में काम कर रही महिला और परिजनों के साथ गाली-गलौज व मारपीट

पदमेश न्यूज। लालबर्रा। थाना लालबर्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहगांव धपेरा में खेत में काम कर रही एक महिला और उसके परिजनों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर लालबर्रा पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मोहगांव धपेरा निवासी श्रीमती नूतन आचार्य पति लक्ष्मीनारायण आचार्य बीते बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे अपने बेटे निश्चय आचार्य एवं सहयोगी रेखा बनोटे के साथ अपने खेत में कृषि कार्य कर रही थीं। इसी दौरान अचानक वहां दो व्यक्ति पहुंचे और उन्हें खेत में काम करने से मना करने लगे और कहने लगे कि उन्होंने यह जमीन लक्ष्मीनारायण से खरीद ली है और अब वे ही इस पर खेती करेंगे। जब पीड़िता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जमीन उनकी खुद की है और वही खेती करेंगे, तो दोनों आरोपी उग्र हो गए। आरोपियों ने पीड़िता और उनके परिजनों को मां-बहन की अत्यंत गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। पीड़िता और उनके परिजनों के द्वारा गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उनके साथ लात-घूसों (हाथ-मुक्कों) से मारपीट शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में पीड़िता के सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं और काफी दर्द हो रहा है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़ित परिवार को दोबारा खेत में काम करने पर जान से खत्म करने की खुली धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता ने अपने देवर विवेक कुमार बीरनवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद वे परिजनों के साथ लालबर्रा थाने पहुंचीं और मामले की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। लालबर्रा पुलिस ने पीड़िता नूतन आचार्य की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय नंदेश्वर पिता दुर्गाजी नंदेश्वर तथा मदनलाल कनौजे पिता स्व. भैयालाल कनौजे के विरूध्द भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 296 (बी), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है।

कृषि उपज मंडी में धान तुलाई में पकड़ी गई चोरी

40 किलो की जगह तौली जा रही थी 43 किलो धान मचा हड़कंप

रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। वारासिवनी।

जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी वारासिवनी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मंडी परिसर में किसानों की गाढ़ी कमाई की चोरी एक गंभीर मामला सामने आया है। ९ जुलाई की शाम करीब ५ बजे धान की तुलाई को लेकर मंडी में उस वक्त भारी हंगामा और आक्रोश की स्थिति निर्मित हो गई। जब एक किसान की सजगता के कारण तौल में हो रही ढाई से तीन किलोग्राम की सीधी चोरी पकड़ी गई। निर्धारित मात्रा से अधिक धान तौले जाने पर किसान और तौल करने वालो के बीच तीखी बहस हुई जिसके बाद मौके पर पहुंची मंडी अधिकारी ने पंचनामा की कार्यवाही की हैं।

यह हैं मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कोस्ते निवासी किसान नरेंद्र बिसेन अपनी करीब १३ क्विंटल धान बेचने के लिए वारासिवनी कृषि उपज मंडी लेकर आए थे। मंडी में उन्होंने धान के दो ढेर लगाए थे। इसमें से एक ढेर को व्यापारी दीपक रामचंदानी ने रामचंदानी राइस मिल के लिए २९६० रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा था पर्ची के अनुसार यह धान कुल ८ क्विंटल थी। धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंडी परिसर में तौलकर्ताओं हमालों द्वारा धान को बोरियों में भरकर तौल कांटे पर नापा जा रहा था। नियमानुसार प्रति बोरी धान का वजन ४०.७०० किलोग्राम होना चाहिए था और कांटे पर किसान को यही वजन दिखाया भी जा रहा था। लेकिन पूरी धान तौलने के बाद हमाल अचानक भरी हुई बोरियों में से चुपके से धान निकालने लगे। हमालों की इस संदिग्ध गतिविधि को देखकर किसान नरेंद्र बिसेन को शक हो गया। उन्होंने तुरंत दखल देते हुए तौले जा चुके बोरों को दोबारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर रखने को कहा। जब किसान के संदेह पर एक बोरी को पुन: कांटे पर चढ़ाया गया तो जिस बोरी का वजन ४०.७०० किलोग्राम होना चाहिए था उसका वास्तविक वजन ४३ किलोग्राम से भी अधिक निकला। यानी प्रति बोरी करीब ढाई से तीन किलो धान अधिक ली जा रही थी। इसके बाद जब दूसरी बोरियों को भी कांटे पर रखा गया तो उनमें भी ४३ किलो से ज्यादा वजन पाया गया। यदि यह चोरी नहीं पकड़ी जाती तो प्रति बोरी ३ किलो के हिसाब से किसान को प्रति क्विंटल लगभग ७.८ किलो धान का सीधा नुकसान उठाना पड़ता। तौल में इतनी बड़ी गड़बड़ी उजागर होते ही किसान नरेंद्र बिसेन का आक्रोश फूट पड़ा। देखते ही देखते मंडी परिसर में मौजूद अन्य किसान और उनके परिचितों की भारी भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ती देख तत्काल मंडी प्रबंधन को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही मंडी अधिकारी जयमाला भालाधरे मौके पर पहुंचीं उन्होंने निष्पक्षता दिखाते हुए स्वयं अपनी मौजूदगी में बोरियों को पुन: किलो कांटे पर रखवाया। भौतिक सत्यापन के दौरान अधिकारी के सामने भी बोरियों का वजन ४३ किलोग्राम से अधिक ही आया। इसके बाद पीड़ित किसान की मांग और साक्ष्यों के आधार पर मंडी अधिकारी के द्वारा ऑफिस में पंचनामा कार्यवाही की गई।

किसानों में आक्रोश कार्यवाही करने की मांग

वारासिवनी कृषि उपज मंडी जिले की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है जहां केवल वारासिवनी ही नहीं बल्कि जिले की विभिन्न तहसीलों से सैकड़ों किसान अपनी उपज बेचने आते हैं। किसानों का आरोप है कि मंडी में धान चोरी या अधिक तौल का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन ठोस कार्यवाही नही होने के कारण इसके हौसले बुलंद हैं। किसानों ने मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ताकि भविष्य में किसी अन्य किसान के साथ ऐसा धोखा ना हो सके।

मंडी में चोरी की प्रथा बंद हो प्रबंधन इसमें प्रबंधन की गलती है-नरेंद्र बिसेन

किसान नरेंद्र बिसेन ने बताया कि मैं कोस्ते रहता हूं धान बेचने के लिए हम वारासिवनी मंडी आए थे। धान बिकने पर तौल कर रहे थे उन्होंने काटा मुझे ४०.७०० किलोग्राम का बताया लेकिन यह फिर बाद में बोरी से धान निकालने लगे तो मुझे संदेह हुआ। मैंने फिर बोरी का कांटा करवाया तो उसमें ४३.२०० किलोग्राम धान थी हर बोरी में धान ज्यादा थी। प्रांगण प्रभारी से संपर्क किया गया तो जयमाला भालाधरे मंडी की अधिकारी है उन्हें मौके पर बुलाया गया। जिन्होंने ४३ किलोग्राम स्वयं देखा जबकि ४०.५०० किलोग्राम इन्होंने लेना चाहिए एक बोरी का वजन ५०० ग्राम होता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की चोरी बंद हो प्रबंधन यहां कार्यवाही करें और इसमें प्रबंधन की गलती है । किसान की धान चोरी होती है और जब यहां चोरी हो रही है तो किसान क्यों आएगा ऐसे कांटे वालों को तो बंद कर देना चाहिए ईमानदारी से किसान की धान तौले और चोरी बंद हो यही चाहते हैं।

बोरी में अधिक धान पाई गई तौल करने वालों की गड़बड़ी है कार्यवाही की जा रही है-जयमाला भालाधरे

मंडी अधिकारी जयमाला भालाधरे ने बताया कि किसान नरेंद्र बिसेन के द्वारा धान बेचने के लिए लाई गई था। जिसे तौलने वाले लोगों ने ४०.७०० किलोग्राम पहले किसान को दिखाया। फिर किस के संदेह पर पुन: तौल करवाया गया तो उसमें ४३ किलोग्राम धान निकाला इसका मेरे द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया। जहां पर सभी बोरी में अधिक धान देखी गई तो यह तौल करने वालों की गड़बड़ी है जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

भालू शिकार मामले में तीसरा आरोपी दुर्गा भलावी गिरफ्तार, कोर्ट से मिली रिमांड

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। खैरलाँजी वन विभाग के अंतर्गत भंडारबोड़ी सर्किल के ग्राम पिपरटोला में हुए भालू शिकार और उसके शव को क्षत.विक्षत करने के मामले में ९ जुलाई को वन विभाग ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। इस जघन्य मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए वन विभाग की टीम ने तीसरे आरोपी दुर्गा पिता ब्रज भलावी उम्र ४० वर्ष निवासी पिपरटोला को गिरफ्तार कर वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । जहां से वन विभाग को उसकी पूछताछ के लिए रिमांड मिल गई है। इस प्रकार अब तक गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी वन विभाग की कस्टडी में हैं जिनसे घटना से जुड़े अन्य अहम सुराग जुटाने के लिए सघन पूछताछ की जा रही है। चौथा आरोपी अभी भी फरार है जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश

दे रही हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पिपरटोला बीट के कक्ष क्रमांक ८१३ से लगी राजस्व भूमि पर जंगली सूअर का शिकार करने के लिए लोहे के तारों का अवैध बिजली करेंट फैलाया था। इस जाल में एक वयस्क नर भालू फंसा और मौके पर ही तड़प.तड़प कर उसकी मौत हो गई। भालू की मौत से घबराये आरोपियों ने बेहद क्रूर तरीका अपना कर कुल्हाड़ी व धारदार हथियारों से भालू के शव को ७ टुकड़ों में काट डाला। इन टुकड़ों को पास ही स्थित किसान जियालाल धुर्वे के खेत में बने एक कुएं में फेंक दिया ताकि शिकार का कोई सबूत ना बचे। यह खौफ नाक मामला ४ जुलाई को तब सामने आया जब खेत मालिक जियालाल धुर्वे अपने खेत पहुंचे और उन्हें कुएं में वन्यजीव के क्षत.विक्षत अवशेष तैरते दिखे। वन विभाग ने इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ संशोधन अधिनियम २०२२ की धाराओं में केस दर्ज किया है। जिसमें सुरेंद्र पिता हरिराम गोंड उम्र ४० वर्ष ,छबिलाल पिता टीकाराम उइके उम्र ३८ वर्ष ,दुर्गा पिता ब्रज भलावी उम्र ४० वर्ष तीनो निवासी पिपरटोला को गिरफ्तार किया जा चूका हैं। इन तीनों को न्यायालय से वन विभाग के द्वारा रिमांड में लेकर इस शिकार रैकेट में शामिल अन्य संभावित चेहरों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।

केरल के विद्यार्थियों का जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में हुआ स्वागत

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में केरल राज्य से आए विद्यार्थियों का पारंपरिक एवं भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार में उत्साह और राष्ट्रीय एकता की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। विद्यालय के प्राचार्य संदीप जैन ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रवजन नीति के अंतर्गत कक्षा ९ वीं के विद्यार्थियों का आदान प्रदान हिन्दी भाषी एवं अहिन्दी भाषी राज्यों के बीच किया जाता है। इसी क्रम में केरल के पथानामथिट्टा जिले से कक्षा ९ वीं के २४ विद्यार्थी यहां अध्ययन हेतु पहुंचे हैं एवं जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी से इतनी ही संख्या में कक्षा ९ वीं के विद्यार्थी स्टाफ के संरक्षण में जनवि पट्टमथिट्टा केरल भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, वेशभूषा एवं जीवनशैली से परिचित कराना है। जिससे वे ना केवल हिन्दी भाषा को बेहतर ढंग से सीख सकें,बल्कि राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता की भावना को भी आत्मसात कर सकें। बालाघाट की परंपरा के अनुरूप अतिथियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी गई। प्राचार्य संदीप जैन, उप प्राचार्य रणवीर सिंह, वरिष्ठ शिक्षक बी आर पटेल एवं माइग्रेशन प्रभारी डॉ बी सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर तथा तिलक लगाकर विद्यार्थियों का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त विद्यार्थी एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने आपसी भाईचारे सांस्कृतिक समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदेश को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया।

चावल रीसाईक्लिंग मामले में ज़ब्त ट्रकों की संख्या बढ़कर हुई १८

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। जिले में सरकारी चावल की रीसाईक्लिंग के संदिग्ध मामले में एसआईटी ने अपनी जांच और कार्यवाही का दायरा और बढ़ा दिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ६ और संदिग्ध ट्रकों को ज़ब्त किया है जिसके बाद इस मामले में अब तक ज़ब्त किए गए ट्रकों की कुल संख्या १८ पर पहुँच चुकी है। यह पूरा मामला ३ जून की रात को सामने आया था जब छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एथेनॉल प्लांट के लिए बालाघाट एफसीआई गोदाम से तीन ट्रक कस्टम मिल्ड राइस लेकर रवाना हुए थे। मुखबिर की सूचना पर कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने वारासिवनी स्थित संचेती राईस मिल पर औचक कार्यवाही की थी। वहां टीम ने एक ट्रक को रोका जिसमें २४२ क्विंटल सीएमआर चावल लोड था। जब मामले की आगे तफ्तीश की गई तो पता चला कि इसके साथ निकले दो अन्य ट्रक एथेनॉल प्लांट पहुँचे ही नहीं थे। लापत्ता हुए दोनों ट्रक बाद में सिवनी के भोरकल खापा की एक इंडस्ट्री में खड़े मिले लेकिन उनमें से सरकारी चावल गायब था। वारासिवनी पुलिस ने उन्हें ज़ब्त किया और कड़ाई से की गई जांच के बाद ७ और संदिग्ध ट्रकों की पहचान की

गई थी। पुलिस के द्वारा की जा रही लगातार जांच के दौरान अब ६ और ट्रकों को ज़ब्त किया गया है। इन ट्रकों के क्रमांक क्रमश: सीजी ०४ एमके ७७२९, एमपी २२ जेड जे ४५१९,जे एच ०२ बीपी ०५०९, सी जी ०४ एनयू ०५३६, एम ४० बी जी ३८९६ ,एमएच ४० सी एम ७४९२ हैं। इन नए ट्रकों की जब्ती के बाद कुल गाड़ियों की संख्या १८ हो गई है। जांच अधिकारियों को अंदेशा है कि सरकारी चावल को एथेनॉल प्लांट के नाम पर कागजों में निकालकर प्लांट पहुँचने से पहले ही अन्य ठिकानों पर डंप किया जा रहा था। इस मामले को लेकर वारासिवनी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा ३१६,३ और ३/५ के तहत दर्ज अपराध में फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही हैं।

सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिला चिकित्सालय रिफर

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी मेंढ़की मार्ग पर स्थित कोस्ते नाले के पास बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। सिकंदा पावर हाउस के सामने हुए इस एक्सीडेंट में ड्यूटी पर जा रहे एक २८ वर्षीय युवक को गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित मानेश्वर उम्र २८ वर्ष जो वारासिवनी के वार्ड नंबर १ का निवासी है सिकंदा पावर हाउस में कार्यरत है। रोज की तरह वह बीती रात भी अपनी नाइट ड्यूटी निभाने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वह पावर हाउस के सामने पहुँचा अज्ञात कारणों के चलते वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि अंकित सड़क पर जा गिरा और मौके पर ही लहूलुहान होकर अचेत हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को गंभीर हालत में देख तत्काल संजीवनी १०८ एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। राहगीरों की मदद से घायल अंकित को तुरंत वारासिवनी के सिविल अस्पताल लाया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने अंकित की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उसका प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए तत्काल जिला चिकित्सालय रिफर कर दिया। फिलहाल जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है।

खेत में काम करने गए सीआरपीएफजवान को सांप ने डसा अस्पताल में उपचार जारी

पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। वारासिवनी जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तुमाड़ी में गुरुवार की सुबह खेत में काम करने गए एक सीआरपीएफ जवान को साँप ने काट दिया। पीड़ित जवान को तत्काल परिजनों के द्वारा वारासिवनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम तुमाड़ी निवासी पंकज पिता लेखराम कटरे उम्र ३८ वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कार्यरत हैं और वर्तमान में नागपुर में तैनात हैं। इन दिनों वे छुट्टी लेकर अपने गृह ग्राम तुमाड़ी आए हुए हैं। घर पर रहने के दौरान वे अपने परिवार के साथ खेती किसानी के कार्यों में हाथ बंटा रहे थे। रोजाना की तरह गुरुवार सुबह करीब ६ बजे पंकज अपने खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। सुबह करीब ९.३० बजे जब वे खेत में काम में व्यस्त थे अचानक उन्हें पैर में किसी जीव के काटने का तीखा अहसास हुआ। पंकज ने तुरंत सतर्क होकर आसपास सांप को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। हालांकि पैर पर सांप के काटने के स्पष्ट निशान देखकर वे समझ गए कि उन्हें सर्पदंश हुआ है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पंकज ने तत्काल घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। उन्होंने पंकज

को तुरंत वारासिवनी के सिविल अस्पताल पहुँचाया जहाँ डॉक्टर की निगरानी में उनका उपचार जारी है।

एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार ने किया ग्रामों का औचक निरीक्षण, स्कूल-आंगनवाड़ी व पेयजल व्यवस्था का लिया जायजा

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट गोपाल सोनी के निर्देशानुसार गुरुवार को तहसीलदार सुश्री छवि पंत ने तहसील बालाघाट अंतर्गत ग्राम बघोली, अमेड़ा एवं रट्टा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने संबंधित हल्कों में पटवारियों की उपस्थिति एवं शासकीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अभिलेखों का परीक्षण कर राजस्व कार्यों में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इस दौरान तहसीलदार ने शासकीय विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं ग्राम पंचायत भवनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल भवन एवं आंगनवाड़ी भवनों की स्थिति का जायजा लेते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को उपलब्ध पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को पेयजल संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तहसीलदार सुश्री छवि पंत ने विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन (मिड-डे मील) की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कटती जमीन, उजड़ते गांव-गंगा कटाव पर कब बनेगी राष्ट्रीय नीति?

गंगा भारतीय सभ्यता की जीवनरेखा है। इसकी धारा ने सदियों से खेतों को उपजाऊ बनाया, शहरों को बसाया और करोड़ों लोगों की आजीविका को सहारा दिया। लेकिन यही गंगा आज बिहार के दियारा क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए हर वर्ष भय, असुरक्षा और विस्थापन का कारण बन रही है। मानसून के साथ नदी का बढ़ता कटाव सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि, मकानों और लोगों की जीवनभर की कमाई को निगल जाता है। बाढ़ का पानी कुछ दिनों में उतर जाता है, लेकिन कटाव से उजड़े परिवारों का दर्द वर्षों तक नहीं मिटता। यही कारण है कि गंगा का कटाव केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानवीय संकट है। बिहार में बाढ़ पर हर साल चर्चा होती है, राहत पैकेज घोषित होते हैं और बचाव कार्यों की समीक्षा भी होती है। इसके विपरीत गंगा कटाव का संकट अक्सर सीमित प्रशासनिक कार्रवाई तक सिमट जाता है। जिन किसानों की पुश्तैनी जमीन नदी में समा जाती है, उनके लिए न तो पर्याप्त पुनर्वास की व्यवस्था है और न ही कोई दीर्घकालिक नीति। परिणामस्वरूप हर मानसून हजारों परिवार इस आशंका में जीते हैं कि अगला नंबर कहीं उनके घर या खेत का न हो। मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, भोजपुर, पटना, लखीसराय और सारण सहित गंगा के किनारे बसे अनेक जिले वर्षों से इस त्रासदी का सामना कर रहे हैं। नदी का बदलता प्रवाह खेतों, बगीचों और आबादी वाले इलाकों को लगातार काटता हुआ आगे बढ़ता है। इससे केवल भूमि का नुकसान नहीं होता, बल्कि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ती है। जिन परिवारों की आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है, उनके सामने जीवन का गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। बिहार के मुंगेर जिले के सदर प्रखंड का टीकारामपुर इस समस्या का जीवंत उदाहरण है। यहां पिछले कई वर्षों से ग्रामीण स्थायी कटावरोधी उपायों की मांग कर रहे हैं। हाल के महीनों में कटाव की रफ्तार इतनी तेज हुई कि बड़ी मात्रा में उपजाऊ कृषि भूमि गंगा में समा गई। कई किसानों की खड़ी फसलें देखते-ही-देखते नदी की भेंट चढ़ गईं और अब नदी गांव की आबादी के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लोगों के सामने केवल आर्थिक नुकसान का नहीं, बल्कि अपने घर-बार से विस्थापित होने का वास्तविक खतरा खड़ा है।दियारा क्षेत्र में भूमि केवल खेती का साधन नहीं होती, बल्कि परिवार की पहचान, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का आधार भी होती है। जब कोई किसान अपनी जमीन खोता है, तो उसके साथ उसकी आय, सामाजिक स्थिरता और अगली पीढ़ी की संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं। इसलिए गंगा कटाव को केवल जल संसाधन विभाग या आपदा प्रबंधन का विषय मानना पर्याप्त नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और आजीविका से जुड़ा राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है।गंगा के कटाव को केवल प्रकृति का अपरिहार्य परिणाम मान लेना वास्तविकता से आंखें मूंद लेने जैसा होगा। नदी का स्वाभाविक प्रवाह, तलछट का जमाव और धारा का बदलना अपनी जगह है, लेकिन अनियोजित मानवीय हस्तक्षेप ने इस समस्या को और गंभीर बनाया है। कई स्थानों पर बिना समग्र अध्ययन के कराए गए तट संरक्षण कार्य, अवैज्ञानिक तटबंध, अनियंत्रित बालू खनन और पर्यावरणीय असंतुलन ने नदी के स्वभाव को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक स्थान पर किया गया कटावरोधी निर्माण कई बार नदी की धारा को दूसरी दिशा में मोड़ देता है, जिससे दूसरे गांव खतरे की चपेट में आ जाते हैं।

क्या हमारी थाली सुरक्षित है?

महाराष्ट्र के चौंकाने वाले खाद्य नमूना आँकड़ों से पूरे भारत के लिए सबक -पूरे भारत में जीरो टॉलरेंस टू फूड एडल्टरेशन की नीति लागू की जाए -समग्र व्यापक विश्लेषण

वैश्विक स्तरपर भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है, लेकिन यदि नागरिकों की थाली में परोसा जाने वाला भोजन ही सुरक्षित न हो तो विकास की चमक फीकी पड़ जाती है। 3 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत खाद्य सुरक्षा संबंधी आँकड़ों ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र एफडीए के पास 1 जून 2026 तक 13,474 खाद्य नमूनों का लॉबिंत स्टॉक (बैकलॉग) परीक्षण के लिए उपलब्ध था।इसके बाद विभाग ने अभियान चलाकर 7,494 नमूनों का परीक्षण किया।जांचे गए 7,494 खाद्य नमूनों में से 4,091 नमूने (लगभग 54 प्रतिशत) जो लगभग आधे से अधिक हैं मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। यह आँकड़ा केवल महाराष्ट्र की चिंता नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए चेतावनी है कि खाद्य सुरक्षा को अब केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य अभियान के रूप में देखा जाए।भारत में हर दिन करोड़ों लोग होटल, ढाबों, स्ट्रीट फूड,मिठाई की दुकानों, डेयरियों पैकेज्ड फूड,ऑनलाइन फूड डिलीवरी और स्थानीय बाजारों से खाद्य सामग्री खरीदते हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यदि इन उत्पादों में मिलावट,गलत लेबलिंग, रसायनों का अत्यधिक उपयोग या स्वच्छता का अभाव है, तो इसका सीधा प्रभाव नागरिकों के स्वास्थ्य,बच्चों के विकास, बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता और देश की उत्पादकता पर पड़ता है। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास का विषय भी है।महाराष्ट्र के आँकड़ों ने यह स्पष्ट किया है कि केवलकानून बनाना पर्याप्त नहीं है।यदि निरीक्षण नियमित न हों, दोषियों पर त्वरित कार्रवाई न हो और नागरिकों में जागरूकता न बढ़े, तो खाद्य सुरक्षा कानून कागज़ों तक सीमित रह जाते हैं।इसलिए अब समय है कि पूरे भारत में जीरो टॉलरेंस टू फूड एडल्टरेशन की नीति लागू की जाए। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन का नेतृत्व करते हुए तुकाराम मुंडे द्वारा अपनाई गई कठोर प्रशासनिक कार्यशैली और हरियाणा में आर.एस. भट्ट द्वारा नियमों के सख्ती से पालन कराने वाली कार्यसंस्कृति जैसी प्रशासनिक सख्ती सोशल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में चर्चित यदि इसी प्रकार की पारदर्शी, जवाबदेह और जीरो-टॉलरेंस आधारित कार्यशैली देश के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक आयुक्त, आयुक्तालय, जिलाधिकारी, पुलिस प्रमुख, परिवहन आयुक्त, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, नगर आयुक्त, स्वास्थ्य आयुक्त और अन्य प्रशासनिक प्रमुख अपनाएँ, तो शासन व्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन संभव है। यह कहना एक नैतिक आदर्श है कि ऐसी व्यवस्था भारत को सतयुग जैसी सुशासन व्यवस्था की दिशा में ले जा सकती है अर्थात ऐसी व्यवस्था जहाँ कानून का सम्मान हो, भ्रष्टाचार न्यूनतम हो और नागरिकों का हित सर्वोपरि हो।देश में समय-समय पर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने कठोर, निष्पक्ष और परिणामोन्मुख कार्यशैली का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसी ही सख्त, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक शैली जिसे कई लोग तुकाराम मुंडे मॉडल जैसी कार्यसंस्कृति के रूप में देखते हैं खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में भी अपनाई जा सकती है। यदि प्रत्येक राज्य के एफडीए आयुक्त प्रतिदिन आकस्मिक निरीक्षण करें,बड़े फूड हब की नियमित जांच कराएँ, बार -बार नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस तत्काल निलंबित करें,दोषियों के नाम सार्वजनिक करें,मोबाइल फुडटेस्टिंग वैन बढ़ाएँ, प्रयोगशालाओं की संख्या दोगुनी करें,त्योहारों से पहले विशेष अभियान चलाएँ,तो मिलावट करने वालों में भय उत्पन्न होगा और उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा। साथियों बात अगर हम फूड हब के लिए राष्ट्रीय मानकों को समझने की करें तो,देशभर में बड़े फूड हब विकसित हो रहे हैं। इन स्थानों पर प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार होता है। ऐसे प्रत्येक फूड हब के लिए अनिवार्य होना चाहिए एचएसीसीपी आधारित सुरक्षा प्रणाली,नियमित माइक्रो बायोलॉजिकल परीक्षण कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल तापमान निगरानी,शुद्ध पेयजल,साफ रसोई कीट नियंत्रणसी, सीटीवी आधारित निगरानी,ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट, आधुनिक तकनीक का उपयोगआज आर्टिफिशल इंटेलीजेंस, एलओ टी, क्यूआर कोड , ब्लॉकचैन और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी तकनीकें खाद्य सुरक्षा को नई दिशा दे सकती हैं।कल्पना कीजिए यदि प्रत्येक पैकेज पर क्यूर आर कोड स्कैन करते ही उपभोक्ता को निर्माण तिथि, प्रयोगशाला रिपोर्ट, लाइसेंस संख्या और निरीक्षण इतिहास दिखाई दे, तो मिलावट की संभावना सटीकता से स्वतः कम हो जाएगी। साथियो,यह विषय किसी सरकार, किसी अधिकारी या किसी राजनीतिक दल का नहीं,बल्कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन का है।यदि देश का प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी, चाहे वह खाद्य सुरक्षा आयुक्त हो, स्वास्थ्य अधिकारी, परिवहन अधिकारी, नगर आयुक्त या किसी अन्य विभाग का प्रमुख—कानून के प्रति वही निष्ठा, पारदर्शिता और शून्य सहनशीलता कीकार्यसंस्कृति अपनाए जिसकी अपेक्षा नागरिक करते हैं,तो शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार संभव है। सुशासन का अर्थ किसी एक व्यक्ति पर निर्भर व्यवस्था नहीं, बल्कि ऐसी संस्थागत संस्कृति है जहाँ नियम सब पर समान रूप से लागू हों, भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान न हो और नागरिक का स्वास्थ्य, सम्मान तथा अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता बने। यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव होगी और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर भारत एक अधिक स्वस्थ, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में सटीकता से स्थापित हो सकता है।

-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

मुफ्त दवा योजना पर संकट नहीं समाधान की जरूरत

-कांतिलाल मांडोत

जीवनरक्षक दवाओं की कमी गरीब मरीजों के लिए गंभीर चुनौती लेकिन समय रहते व्यवस्था सुधारकर सरकार भरोसा फिर मजबूत कर सकती है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल केवल एक चिकित्सा संस्थान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लाखों मरीजों की उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन हजारों मरीज दूर-दराज के गांवों और कस्बों से यहां इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के साथ सरकार की निशुल्क दवा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब इलाज के बाद डॉक्टर की लिखी दवाएं अस्पताल के काउंटर पर उपलब्ध नहीं होतीं तो मरीज और उसके परिजनों की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। हाल के दिनों में जीवनरक्षक दवाओं सहित बड़ी संख्या में दवाओं की अनुपलब्धता की खबरें सामने आई हैं। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

गरीब और मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहता है। निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदना हर परिवार के लिए आसान नहीं होता। विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए नियमित दवाएं जीवन का आधार होती हैं। यदि ऐसी दवाएं समय पर नहीं मिलें तो बीमारी बढ़ सकती है और आर्थिक बोझ भी कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि निशुल्क दवा योजना को राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिन मरीजों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक भेजा गया, कई दिनों बाद आने के लिए कहा गया या फिर बाहर से दवा खरीदने की सलाह दी गई, उनकी परेशानी को सहज रूप से समझा जा सकता है। जो मरीज सैकड़ों किलोमीटर दूर से किराया खर्च करके अस्पताल पहुंचता है, उसके लिए केवल दवा ही नहीं बल्कि दोबारा आने-जाने का खर्च भी बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे मरीजों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यह इलाज कराए या परिवार का खर्च चलाए। यह भी सच है कि यह समस्या केवल जयपुर तक सीमित नहीं दिखाई देती। प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में समय-समय पर कुछ दवाओं की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं सप्लाई में देरी होती है तो कहीं खरीद प्रक्रिया पूरी होने तक मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। इससे सरकार की अच्छी योजनाओं की छवि प्रभावित होती है। जनता यह नहीं देखती कि कमी किस स्तर पर हुई है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अस्पताल पहुंचने पर दवा मिलनी चाहिए। हालांकि इस पूरे विषय को केवल आलोचना के दृष्टिकोण से देखना भी उचित नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने पिछले कई वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना जैसी पहल ने लाखों गरीब परिवारों को राहत दी है। यदि ये योजनाएं नहीं होतीं तो गरीब मरीजों का इलाज और भी कठिन हो जाता। इसलिए यह कहना उचित होगा कि योजना में कमी नहीं है बल्कि उसके क्रियान्वयन के कुछ हिस्सों में सुधार की आवश्यकता है। अस्पताल प्रशासन का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ दवाएं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से उपलब्ध नहीं हो पातीं तो स्थानीय स्तर पर खरीद की जाती है। कई बार आपूर्ति करने वाली कंपनियों की ओर से विलंब होने के कारण अस्थायी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि वास्तव में ऐसा है तो इसका समाधान भी प्रशासनिक स्तर पर संभव है। दवाओं की उपलब्धता का नियमित आकलन, समय रहते नई खरीद प्रक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था से इस प्रकार की कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी उतनी ही अधिक होती हैं। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में करोड़ों लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आसान कार्य नहीं है। दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और कई बार अनुमान से अधिक मरीज आने के कारण स्टॉक जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस समस्या को केवल लापरवाही कह देना भी पूरी तस्वीर नहीं दर्शाता। आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रशासन और दवा आपूर्ति एजेंसियां मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिससे आवश्यक दवाओं का भंडार हमेशा सुरक्षित रहे। तकनीक का बेहतर उपयोग भी इस दिशा में बड़ा समाधान बन सकता है। यदि सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं का ऑनलाइन स्टॉक रियल टाइम अपडेट हो तो यह पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में बची है और कब नई खेप की आवश्यकता होगी। इससे आपूर्ति में होने वाली देरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। मरीजों को भी मोबाइल या हेल्पलाइन के माध्यम से यह जानकारी मिल सके कि संबंधित दवा किस अस्पताल में उपलब्ध है। इससे उन्हें अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के साथ संवाद की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। यदि किसी दवा की अस्थायी कमी है तो मरीज को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि दवा कब तक उपलब्ध होगी या उसका सुरक्षित विकल्प क्या है। कई बार जानकारी के अभाव में मरीज अधिक परेशान हो जाता है। संवेदनशील व्यवहार और स्पष्ट सूचना भी आधी समस्या का समाधान कर देती है। इस विषय में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहने के बजाय स्थानीय स्तर पर समस्याओं की जानकारी सरकार तक पहुंचानी चाहिए। जहां भी दवा की कमी हो, वहां तत्काल समाधान के लिए प्रयास होने चाहिए। स्वास्थ्य सेवा राजनीति का नहीं बल्कि मानवता का विषय है। इसलिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए। सरकार के सामने यह अवसर भी है कि वह इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लेकर पूरे प्रदेश में दवा आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करे। जिन अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं की कमी है वहां तत्काल अतिरिक्त स्टॉक भेजा जाए। खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा तेज बनाया जाए। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है, वहां जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। इससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा। अंततः किसी भी कल्याणकारी सरकार की पहचान केवल योजनाएं बनाने से नहीं बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने से होती है। राजस्थान की निशुल्क दवा योजना लाखों लोगों के लिए वरदान रही है और इसे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यदि दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए तो गरीब मरीजों को न तो जेब से खर्च करना पड़ेगा और न ही इलाज अधूरा छोड़ने की मजबूरी होगी।

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं और उनका लाभ भी समाज को मिला है। अब आवश्यकता इस बात की है कि दवा आपूर्ति से जुड़ी कमियों को शीघ्र दूर किया जाए ताकि कोई भी मरीज केवल दवा की अनुपलब्धता के कारण पीड़ा न झेले। एक संवेदनशील और उत्तरदायी स्वास्थ्य व्यवस्था ही विकसित राजस्थान की पहचान बनेगी, जहां इलाज के साथ भरोसा भी हर मरीज को समान रूप से प्राप्त हो।

हिंद-प्रशांत में भारत का बढ़ता सामर्थ्य एवं साझेदारियां

भारत आज केवल विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने जिस आत्मविश्वास, स्पष्टता और दूरदृष्टि का परिचय दिया है, उसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी है। कभी जो भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए विदेशी हथियारों पर निर्भर था, वही भारत आज आधुनिक मिसाइलों, रक्षा प्रणालियों और सैन्य उपकरणों का निर्यात करने वाला विश्वसनीय राष्ट्र बन चुका है। यह परिवर्तन केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक, वैज्ञानिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का भी प्रमाण है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ताएं इस नई विदेश नीति की सफलता का सशक्त उदाहरण हैं। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों में हुए समझौते यह स्पष्ट करते हैं कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।

भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। वर्षों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल रही है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान ने रक्षा उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल, आकाश वायु रक्षा प्रणाली, पिनाका रॉकेट सिस्टम, तेजस लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक रक्षा उपकरण आज विश्व के अनेक देशों का विश्वास जीत रहे हैं। भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल आज केवल भारतीय सेना की शक्ति का प्रतीक नहीं हैं, बल्कि विश्व के अनेक देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम भी बन रही हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी अभियानों में इन हथियारों की प्रभावशीलता ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। यही कारण है कि इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण देश अपने सुखोई लड़ाकू विमानों के लिए अस्त्र मिसाइल प्राप्त करना चाहते हैं तथा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह भारत के रक्षा उद्योग के प्रति बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण है।

इंडोनेशिया हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। मलक्का जलडमरूमध्य जैसे विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग पर उसकी रणनीतिक स्थिति वैश्विक व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब?ता रक्षा सहयोग केवल दो देशों के संबंधों को मजबूत नहीं करता, बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी नया आयाम देता है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत अब किसी पर निर्भर होकर नहीं, बल्कि समान साझेदारी और परस्पर सम्मान के आधार पर संबंध स्थापित कर रहा है। भारत किसी देश पर अपनी शक्ति थोपने में विश्वास नहीं रखता। उसकी विदेश नीति का मूल मंत्र है-'वसुधैव कुटुम्बकम्', 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' और 'विश्व बंधुत्व'। यही कारण है कि भारत जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ भी विश्वासपूर्ण साझेदारी विकसित कर रहा है।

आज हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है। चीन का विस्तारवादी रवैया, दक्षिण चीन सागर में उसका सैन्यीकरण, छोटे देशों पर दबाव बनाने की नीति तथा आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। भारत ने इन परिस्थितियों में संतुलित, शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ रणनीति अपनाई है। भारत किसी के विरुद्ध युद्ध नहीं चाहता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से कोई समझौता भी नहीं करता। यही संतुलित दृष्टिकोण भारत को विश्व का विश्वसनीय साझेदार बनाता है। भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए स्पष्ट संदेश है कि नया भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत अब केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीकी युद्ध की तैयारियों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन इस दिशा में भारत की सबसे बढ़ी ताकत बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उन्होंने भारत की वैश्विक छवि को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की है। आज विश्व के बड़े राष्ट्र भारत को केवल विशाल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीय मित्र, तकनीकी साझेदार, निवेश गंतव्य और सुरक्षा सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। जी-20 की सफल अध्यक्षता, क्वाड की सक्रिय भूमिका, इंडो-पैसिफिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की आवाज तथा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व इसकी पुष्टि करता है। भारत की विदेश नीति अब केवल कूटनीतिक दस्तावेज नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय विकास का सशक्त माध्यम बन चुकी है। रक्षा निर्यात ब?ने से विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है, लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, अनुसंधान एवं नवाचार को नई गति मिल रही है और भारतीय उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत हो रहे हैं। यह विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

भारत की विदेश नीति का मूल मंत्र सदैव शांति, सह-अस्तित्व और परस्पर सम्मान रहा है। आदर्श स्थिति में किसी भी दो देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की नींव किसी तीसरे देश के प्रति वैमनस्य या शत्रुता पर नहीं, बल्कि साझा विकास, सुरक्षा और स्थिरता पर आधारित होनी चाहिए। किंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति आदर्शों से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति-संतुलन से संचालित होती है। आज चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य एवं आर्थिक गठजोड़ को सऊदी अरब तक विस्तार देने के प्रयासों में जुटे हैं। हाल के सप्ताहों में सऊदी नेतृत्व और बीजिंग के बीच बढ़ती सक्रियता इस बदलते भू-राजनीतिक समीकरण का संकेत है। यद्यपि सऊदी अरब की प्राथमिक सुरक्षा चिंताएं पाकिस्तान और चीन से अलग हैं तथा उसका प्रमुख ध्यान खाड़ी क्षेत्र में ईरान के बढ़ते प्रभाव पर केंद्रित है, फिर भी बदलते वैश्विक समीकरण भारत के लिए सतर्क रहने का संदेश देते हैं। पाकिस्तान हर परिस्थिति में भारत के विरुद्ध रणनीतिक लाभ उठाने का अवसर तलाशता है, जबकि चीन अपने विस्तारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करने का प्रयास करता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी, संतुलित और सक्रिय विदेश नीति भारत के हितों की प्रभावी सुरक्षा करती दिखाई देती है। उनकी कूटनीति केवल मित्र देशों के साथ विश्वास बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की शरारतों, षड्यंत्रों तथा सामरिक चुनौतियों का संयमित और दृढ़ता से सामना करने की क्षमता भी प्रदर्शित करती है। यही दूरगामी सोच भारत को एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

आज विश्व एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो शक्ति और शांति, विकास और सुरक्षा, तकनीक और मानवता के बीच संतुलन स्थापित कर सके। भारत इस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह सिद्ध किया है कि सशक्त राष्ट्र वही होता है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम होने के साथ-साथ विश्व शांति और मानव कल्याण का भी वाहक बने। निस्संदेह भारत अब विस्तारवाद का नहीं, विकासवाद का प्रतीक है। वह हथियारों का निर्माण युद्ध भड़काने के लिए नहीं, बल्कि शांति की रक्षा और संतुलन स्थापित करने के लिए कर रहा है। यही भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व की पहचान है। आने वाले वर्षों में भारत की यही संतुलित विदेश नीति, आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति और विश्वसनीय कूटनीतिक नेतृत्व न केवल विकसित भारत के स्वप्न को साकार करेगा, बल्कि विश्व व्यवस्था को भी अधिक सुरक्षित, संतुलित और न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करेगा।

-ललित गर्ग

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मिलेगी गति, प्रमुख कलपुर्जों पर सीमा शुल्क समाप्त

नई दिल्ली। एजेंसी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने गुरुवार को सरकार के उस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में उपयोग होने वाले प्रमुख कलपुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को समाप्त कर दिया गया है। कृष्णन ने इस कदम को देश की मूल्य श्रृंखला को और मजबूत बनाने तथा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा उद्योग को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण बदलाव करार दिया। एक कार्यक्रम से इतर बातचीत में सचिव कृष्णन ने बताया कि यह निर्णय उद्योग जगत की ओर से लगातार किए गए अनुरोधों का परिणाम है। वित्त मंत्रालय के समक्ष मामला उठाने के बाद अब इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं। उनका मानना है कि यह पहल विशेष रूप से देश के इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा उद्योग के लिए एक बड़ी राहत और प्रोत्साहन होगी। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य से यह छूट प्रदान की है। इसके तहत डिस्प्ले असेंबली, लिथियम-आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल जैसे प्रमुख कलपुर्जों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सामान पर बुनियादी सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इन तीन महत्वपूर्ण घटकों के विनिर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर बीसीडी छूट लागू करने के लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं।

सरकार ने किया काम, अब उद्योग की बारी, सीईए का एआई चुनौती पर जोर

नई दिल्ली। एजेंसी। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को उद्योगों से कृत्रिम मेधा (एआई) से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल विकास, क्षमता निर्माण और नवाचार में निवेश करने का आग्रह किया। सीआईआई जीसीसी शिखर सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने बजट में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को समर्थन देकर अपना काम कर दिया है, अब उद्योग की बारी है। नागेश्वरन ने बताया कि केंद्रीय बजट में जीसीसी के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग सेफ हार्बर व्यवस्था को सरल बनाकर और छोटे शहरों तक विस्तार को प्रोत्साहित कर सरकार ने उद्योग की लंबे समय से लंबित मांग पूरी की है। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि एआई ने पुराने कारोबारी मॉडल को चुनौती दी है, जिससे नियमित और दोहराए जाने वाले कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने आगाह किया कि केवल कम लागत पर आधारित मॉडल जोखिम में हैं, और उद्योगों को लागत-आधारित मॉडल से क्षमता-आधारित मॉडल तथा निष्पादन से नवाचार की ओर बढ़ना होगा। सीईए ने उद्योगों से क्षमता निर्माण और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हुए कहा ?कि सरकार रनवे तैयार कर सकती है, लेकिन विमान नहीं उड़ा सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि सफलता से आत्मसंतोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धी देश अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, लागत बढ़ रही है और कुशल प्रतिभा की उपलब्धता लगातार चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। भारत की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त इसी पर निर्भर करेगी कि वह एआई के लिए स्वयं को कितना तैयार करता है।

देश के आठ शहरों में प्रीमियम घरों का दबदबा, किफायती खंड पिछड़ा

नई दिल्ली। एजेंसी। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के आठ प्रमुख शहरों में जनवरी-जून 2026 की अवधि में आवासीय बिक्री में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो 1.71 लाख इकाई तक पहुंच गई। इस अवधि में प्रीमियम मकानों की मांग में उल्लेखनीय उछाल देखा गया, जिनकी कुल बिक्री में 54 प्रतिशत की प्रभावशाली हिस्सेदारी रही। नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल बिक्री 1,71,471 इकाई रही, जो पिछले साल की 1,70,201 इकाई से मामूली अधिक है। इस वृद्धि में एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले मकानों की मुख्य भूमिका रही। वहीं, किफायती (50 लाख रुपये से कम) मकानों की बिक्री 15 प्रतिशत घटकर 32,063 इकाई (कुल बिक्री का 19 फीसदी) रह गई, जबकि मध्यम आय वर्ग (50 लाख से 1 करोड़ रुपये) के मकानों की बिक्री पांच प्रतिशत घटकर 46,490 इकाई (कुल बिक्री का 27 फीसदी) रही। आठ शहरों में से दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर सभी जगह आवास बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई, जहां सालाना आधार पर सात प्रतिशत की गिरावट आई। इस वर्ष की पहली छमाही में नए आवासों की पेशकश चार प्रतिशत बढ़कर 1,87,350 इकाई हो गई। नाइट फ्रैंक इंडिया ने कहा कि बाजार के बुनियादी कारक मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू आय में वृद्धि, खरीदारों की बदलती आकांक्षाएं और गृह स्वामित्व में बढ़ता विश्वास प्रीमियम खंड को बल दे रहा है। शहरीकरण, बुनियादी ढांचा निवेश व स्थिर आर्थिक माहौल आवासीय बाजार को निरंतर सहारा दे रहे हैं।

खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ेंगीं, रसोई बजट पर दोहरी मार

मुंबई। एजेंसी। आयातित खाद्य तेलों की लगातार बढ़ती कीमतें और कमजोर मानसून के कारण घरेलू तिलहन उत्पादन पर मंडराते खतरे के चलते आने वाले महीनों में रसोई का बजट और बढ़ सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में महंगी खरीद और घरेलू उत्पादन में संभावित गिरावट के कारण उपभोक्ताओं को तत्काल राहत की संभावना नहीं है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार सरसों, सोयाबीन और पाम तेल की औसत खुदरा कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 10-12 प्रतिशत अधिक हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक बढ़ती परिवहन लागत, कमजोर रुपया और प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा खाद्य तेल का बायोडीजल में बढ़ता उपयोग आयात लागत को बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया का नया बी50 बायोडीजल कार्यक्रम वैश्विक बाजार में पाम तेल की उपलब्धता को और कम करेगा, जिससे कीमतें और बढ़ सकती हैं। वहीं इस वर्ष कमजोर और असमान मानसून का असर घरेलू तिलहन उत्पादन, विशेषकर सोयाबीन और मूंगफली पर पड़ने की आशंका है। गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में बुवाई का रकबा पिछले वर्ष की तुलना में काफी पीछे चल रहा है। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का अनुमान है कि इन चुनौतियों के कारण भारत की खाद्य तेल आयात पर निर्भरता और बढ़ेगी, जो वर्ष 2025-26 तक 16.8 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है।

शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद

सेंसेक्स 238, निफ्टी 81 अंक ऊपर आया

मुम्बई। एजेंसी। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार में ये तेजी दुनियां भर से मिले-जुले संकेतों के बाद भी खरीददारी हावी रहने से आई है। आज जहां प्रमुख सूचकांक हरे निशान पर खुले और पूरे दिन मजबूत बने रहे। हालांकि, कारोबारी सत्र के अंतिम पलों में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली पर इसके बाद भी बाजार ने अपनी तेजी बरकरार रखी। दिन के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 238 अंक उछलकर 76,741 के स्तर पर बंद हुआबंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी भी 81 अंकों की मजबूती के साथ ही 23,962 के स्तर पर बंद हुआ, जिससे निवेशकों में उत्साह का माहौल बना रहा। यह प्रदर्शन वैश्विक बाजारों से मिल रहे मिश्रित संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार की आंतरिक मजबूती को दर्शाता है। यह तेजी केवल मुख्य

सूचकांकों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जबरदस्त उछाल रहा। , जिसने बाजार की सकारात्मक भावना को और मजबूत किया। निवेशकों ने छोटे और मझोले आकार की कंपनियों में खासा उत्साह दिखाय। निफ्टी स्मॉलकैप 100 में प्रभावशाली 1.80 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 ने भी 1.38 फीसदी की शानदार रैली दिखाई। यह व्यापक बाजार में आत्मविश्वास बढ़ने और निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि का संकेत है। निफ्टी 50 के भीतर, कुछ कंपनियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और बाजार को ऊपर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सन फार्मा सबसे आगे रहा, जिसने 2.68 फीसदी की बढ़त हासिल की। इसके बाद, भारती एयरटेल में 2.28 फीसद ?, बजाज फिनसर्व में 2.17 फीसदी और इंटरग्लोब में 2.06 फीसदी की शानदार तेजी दर्ज की गई।

तेल बाजार में विरोधाभास- यूएस में कच्चे तेल का भंडार बढ़ा, पर पेट्रोल-डीजल का घटा

नई दिल्ली। एजेंसी। अमेरिका के ऊर्जा बाजार से मिले नए आंकड़े मिले-जुले संकेत दे रहे हैं। जहां एक ओर कच्चे तेल का भंडार बढ़ा है, वहीं पेट्रोल और डीजल के स्टॉक में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच पश्चिम एशिया में गहराते भू-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर दोनों को मजबूती दी है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के अनुसार 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में कच्चे तेल का भंडार 29.98 लाख बैरल बढ़कर 41.13 करोड़ बैरल हो गया, जो 10 हफ्तों की गिरावट के बाद पहली बार बढ़ा है। हालांकि, बाजार की उम्मीदों के विपरीत, पेट्रोल का भंडार 19.04 लाख बैरल घटकर 21.21 करोड़ बैरल और डीजल का स्टॉक 49.8 लाख बैरल घटकर 10.36 करोड़ बैरल पर आ गया। शुद्ध आयात में वृद्धि ने कच्चे तेल के भंडार को बढ़ाया। इन विरोधाभासी आंकड़ों के बावजूद गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1 फीसदी की तेजी देखी गई। ब्रेंट क्रूड 78.81 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 74.26 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। यह तेजी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव (अमेरिका-ईरान सैन्य कार्रवाई की पुष्टि), आपूर्ति अनिश्चितता और महंगाई की चिंताओं का परिणाम है। तनाव बढ़ने से डॉलर इंडेक्स भी 101 के करीब मजबूत हुआ है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर रहे हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें वैश्विक महंगाई की चिंताओं को बढ़ा रही हैं, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों में जल्द कटौती न करने का दबाव बढ़ा है। बाजार 2026 तक फेड की ओर से एक बार ब्याज दर बढ़ने की संभावना देख रहा है। निवेशक अब अमेरिका के बेरोजगारी दावों और हाउसिंग डेटा पर नजर बनाए हुए हैं।

अमेरिका-ईरान तनाव से सोने-चांदी के दाम में भारी गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का असर सोने-चांदी के दामों पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। गुरुवार को वैश्विक कमोडिटी बाजार कॉमेक्स पर जहां बहुमूल्य धातुओं के दाम तेजी से खुले, वहीं बाद में उनमें तेज गिरावट दर्ज की गई। घरेलू मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी सोने और चांदी की शुरुआत सुस्त रही और वे निचले स्तरों पर कारोबार करते दिखे। इससे पहले बुधवार को भी इनके दामों में तेज गिरावट आई थी। घरेलू बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी के वायदा भाव में नरमी बनी हुई है। सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 1,43,451 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो बुधवार के 1,43,711 रुपए के बंद भाव से 260 रुपए कम था। खबर लिखे जाने तक यह 480 रुपए की गिरावट के साथ 1,43,231 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 2,22,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला, जो पिछले बंद भाव 2,23,437 रुपए से 1,437 रुपए कम था। खबर लिखे जाने तक यह 1,631 रुपए की गिरावट के साथ 2,21,806 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था। इस साल सोने ने 1,80,779 रुपए और चांदी ने 4,20,048 रुपए के रिकॉर्ड स्तरों को छुआ था। मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर सोने का वायदा भाव 4,087.60 डॉलर प्रति औंस पर खुला, लेकिन खबर लिखे जाने तक यह 15.10 डॉलर की गिरावट के साथ 4,067.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। बुधवार को यह 4,082.40 डॉलर पर बंद हुआ था और 4,075 डॉलर प्रति औंस के करीब फिसल गया था। वहीं, चांदी भी 58.88 डॉलर पर खुलने के बाद 0.45 डॉलर की गिरावट दर्ज करते हुए 58.08 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। इस साल सोना 5,586.20 डॉलर और चांदी 121.79 डॉलर प्रति औंस के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिससे मौजूदा गिरावट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

आज का राशिफल

मेष- आज का दिन आपके लिए सेवा, सद्भाव और सम्मान का सुंदर संगम लेकर आया है। किसी जरूरतमंद की मदद करके आप न केवल पुण्य कमाएंगे, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी खास जगह बना सकते हैं। मन में कुछ नया और बड़ा करने की चाह जागेगी, वहीं पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने का अवसर भी मिलेगा। संतान की संगति और उनके भविष्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका सही मार्गदर्शन उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।

वृषभ- आज भाग्य आपके लिए अचानक खुशियों का कोई दरवाजा खोल सकता है। यदि किसी से मनमुटाव चल रहा है, तो बातचीत की एक पहल रिश्तों में फिर से मिठास घोल सकती है। आपका मनमौजी स्वभाव आज आपको आनंद तो देगा, लेकिन निर्णय लेते समय गंभीरता बनाए रखना भी जरूरी होगा। परिवार के साथ की गई यात्रा न केवल यादगार रहेगी बल्कि रिश्तों को और मजबूत भी बनाएगी।

मिथुन- आज का दिन सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन इसके भीतर कई महत्वपूर्ण संकेत छिपे हुए हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। धन के मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला धन फंसा सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है।

कर्क- आज का दिन आपके लिए अवसर और उपलब्धियों का मिश्रण लेकर आया है। लंबे समय से अटकी हुई कोई व्यापारिक डील आखिरकार मंजिल तक पहुंच सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रचनात्मक और डिजाइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई सुनहरा अवसर मिल सकता है। व्यापार को नई दिशा देने की आपकी कोशिशें सफल होती दिखाई देंगी।

सिंह- आज आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी और आपका प्रभाव पहले से अधिक मजबूत दिखाई देगा। संतान को करियर या नौकरी के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। भाई-बहनों का सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण आपको सम्मान, प्रशंसा या किसी विशेष उपलब्धि तक पहुंचा सकता है।

कन्या- आज का दिन व्यस्त जरूर रहेगा, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत आपको शानदार परिणाम दे सकती है। छोटी-छोटी बातों में उलझने के बजाय अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।

तुला- आज सुबह भले थोड़ी धीमी शुरुआत हो, लेकिन दिन चढ़ते-चढ़ते परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी। परिवार के भीतर चल रही किसी उलझन का समाधान बातचीत के जरिए निकल सकता है। आपकी वाणी आज खास महत्व रखेगी, इसलिए सोच-समझकर बोलें। घर में किसी अतिथि के आगमन से रौनक बढ़ेगी। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी यात्रा या घूमने-फिरने की योजना भी दिन को और खूबसूरत बना सकती है।

वृश्चिक- आज का दिन आपको धैर्य और समझदारी का महत्व समझाएगा। छोटी-छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें, क्योंकि संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किसी जरूरतमंद की सहायता करके आपको आत्मिक संतोष मिलेगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगी।

धनु- आज आपके भीतर कुछ बड़ा और नया करने की प्रेरणा जाग सकती है। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है, जो आपके लिए नए अनुभव लेकर आएगी। कार्यक्षेत्र में सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। आध्यात्म और ज्ञान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक अनुशासन रखने की जरूरत होगी।

मकर- आज खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए सबसे बड़ी समझदारी साबित होगी। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। कुछ नए विरोधी सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें।

कुंभ- आज आपके मन में ऐसे नए विचार जन्म लेंगे जो भविष्य में सफलता का आधार बन सकते हैं। व्यापार या नौकरी में रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें। माताजी आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकती हैं, जिसे आप बखूबी निभाएंगे।

मीन- आज का दिन नौकरी और करियर के क्षेत्र में नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें अब प्रगति दिखाई दे सकती है। कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के जरिए आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।

शब्दजाल - 8315

शब्दजाल में 'आ' से शुरु होने वाले दस शब्द ढूंढिए,शब्द ऊपर से नीचे व तिरछे हो सकते हैं.

आराम,आगमन,आईना,आसमान,आघात, आरोग्य,आवागमन,आमादा,आततायी, आतंक

आ	घा	त	ह	दा	प	र	तू	ग	झ आ
ज	अ	ल	म	आ	त	ता	यी	तें	शा ई
अं	इ	नु	दि	ल	दा	ल	ढा	र	ला ना
आ	कु	अ	ल	बे	ला	क	ई	रि	श लौ
स	मा	श	आ	तं	क	स	अ	ग	वी ट
री	रं	दा	चु	व	लि	आ	वा	ग	म न
आ	गा	ल	के	गा	आ	म	र	कौ	या ले
ग	बा	आ	रा	म	क	रो	प्रे	ग	श थ
म	स	मि	न	व	न	ज	ग्य	शा	जू द
न	र	ल	म	ह	र	औ	के	स	प ना
थो	आ	स	मा	न	हो	ग	या	दु	र क

शब्दजाल - 8314 का हल

जो	हु	मे	रि	जा	ट	क	ल	ध	ट जी
ज	ब्बु	क	दू	ई	जी	ने	हि	या	इ ली
जी	पो	ला	घि	का	ग	ब	द	ह	प ल
न	ग	ए	आ	मु	म	कि	न	ह	लि आ
द	र	ला	ज	रि	क	ला	कि	य	प मा
ल	इ	धि	मो	ग	प	ढा	ही	ह	जी कु
ब	सा	ल	रा	व	मा	जो	न	व	प ल
क	टि	जो	र	य	र	जा	का	मे	धि रे
र	या	बो	धि	र	व	न	जी	ला	जू ही
र	ग	ल	बो	ले	य	जा	का	उ	टे ल
धां	स	जा	रा	य	ण	ले	स	सु	रा ल

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7259

1		2	■	3		■	4	5	6
	■		■		■	7			
8				9				■	
	■		■	10			11		
	12		13				14		
15						16			
					17				18
19				20				21	
■	■		22				23		
24						25			

ऊपर से नीचे:-

१. अमिताभ, नाना पाटेकर, तब्बू की 'हम हैं बनारस के भैया' गीत वाली फिल्म-४
२. शाहरुख, विवेक, जूही की फिल्म-४
३. धर्मेन्द्र, माला सिन्हा की 'गैरों पे करम अपनों पे सितम' गीत वाली फिल्म-२
४. 'कभी तो मिलेगी कहीं' गीत वाली अशोक, प्रदीप, मीना की फिल्म-३
५. फिल्म 'परिवार' में जीतेंद्र के साथ नायिका कौन थी-२
६. शाहबाद, किरण, तब्बू, रीता की फिल्म-५
७. सनी, सुष्मिता सेन की 'कोई देख रहा छुप छुप के' गीत वाली फिल्म-२
९. 'ऐसे चेहरे में वो' गीत वाली फिरोज खान, हेमा मालिनी, रेखा की फिल्म-३
११. जॉनि, सायरा की 'दिल की महफिल सजी है' गीत वाली फिल्म-२,१,३
१२. 'इक तुम पास ना आना' गीत वाली अमिताभ, लक्ष्मी छाया की फिल्म-२,१,३
१३. अक्षयकुमार, माधुरी दीक्षित की 'दुनिया से दूर जा रहा हूँ' गीत वाली फिल्म-३
१६. राजकुमार, शत्रुघ्नसिन्हा, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म-३
१७. आमिर खान, फैजलखान, दिव्यंका की 'कमरिया लचके रे' गीत वाली फिल्म-२
१८. 'ये दुनिया वाले पूछेंगे' गीत वाली देव आनंद, आशा पारेख की फिल्म-३
२२. 'आज सजन मोहे अंग लगालो' गीत वाली फिल्म-२
२३. नसीरुद्दीनशाह, अतुल अग्निहोत्री, पूजा भट्ट की फिल्म-२

बायें से दायें:-

२. 'राह बनी खुद मंजिल' गीत वाली विश्वजीत, वहीदा की फिल्म-३
३. संजीवकुमार, सुचित्रासेन की 'हैं बिना जिंदगी से कोई' गीत वाली फिल्म-२
४. 'मैं ने तेरे लिए ही' गीत वाली अमिताभ, राजेश खन्ना, शर्मिला की फिल्म-३
७. गोविंदा, आदित्य, नीलम, मंदाकिनी की अजय कश्यप निर्देशित फिल्म-४
८. 'कितना मजा आ रहा है' गीत वाली धर्मेन्द्र, हेमा मालिनी की फिल्म-२,३
९. राजेंद्रकुमार, वहीदा की 'ये मौसम भीगा भीगा है' गीत वाली फिल्म-३
१०. 'ना जइयो परदेस' गीत वाली दिलीपकुमार, अनिलकपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी, पूनम ढिल्लों की फिल्म-२
११. जॉन अब्राहम, तारा शर्मा को 'हर तरफ हर जगह' गीत वाली फिल्म-२
१४. 'ऐ मेरे मेहबां ऐ मेरे हमनशीं' गीत वाली मनोजकुमार, साधना की फिल्म-३
१५. जीतेंद्र, रेखा की 'गोकुल की गलियों का' गीत वाली फिल्म-२,२,१
१७. 'जाओ जाओ हम से क्या' गीत वाली जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह की फिल्म-२,३
१९. अविंद्र, प्रभुदेवा, काजोल की 'चंदा रे चंदा रे कभी' गीत वाली फिल्म-३
२०. 'सिलसिला शुरू हुआ यहाँ से' गीत वाली फिल्म-३
२१. राजकपूर, नर्गिस की 'राजा की आएगी बारात' गीत वाली फिल्म-२
२३. शशि, संजीवकुमार, वहीदा, पूनम की फिल्म-३
२४. राहुलराय, शीबा की 'तेरी दोस्ती में मिला है' गीत वाली फिल्म-२,१,२
२५. 'देखो मेरा दिल मचल' गीत वाली राजेंद्रकुमार, वैजयंती की फिल्म-३

फिल्म वर्ग पहेली- 7258

वि	वा	ह	■	इ	श्क	वि	श्क	टा
छा	■	मे	■	श्क	था	■	फ	र्ज
बा	द	शा	ह	■	शै	ता	न	■
ल	■	■	सी	मा	■	■	का	ल
न	ज	र	न	■	ख	बा	ब	सं
■	मी	ना	■	न	र	ज	■	दा
आ	न	■	का	बी	■	ना	दा	न
छि	■	जो	शी	ले	■	फि	जा	■
क	शि	श	■	कि	ल	■	य	हू दी
■	खा	■	डां	न	■	आ	ज	घा

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8783

■	1	■	2	■	3	■	■	4
5	■	■	6	■	■	■	■	■
■	■	7	■	■	8	9	■	■
10	11	■	■	■	■	12	13	■
■	■	■	■	■	14	■	■	■
15	■	16	■	17	■	18	■	19
■	■	20	21	■	22	■	■	■
■	■	■	23	■	■	■	24	■
25	■	■	■	■	26	■	■	■

बाएँ से दाएँ

1. ईश वंदना-3
3. हाथ की तीसरी अंगुली-4
5. आगमन-2
6. स्वादिष्ट-3
7. हरसिंगार, पारिजात-2
8. क्रिकेट में बनते हैं-2
10. खौलना, उबलना-5
12. धनवान-3
15. खोदना-3
17. चुनाव, चयन-5
20. नसीब(अंग्रेजी-2)
22. कलर-2
23. रक्षक, संकटमोचक-3
24. कार्य, काज-2
25. सुंघनी, नस-4
26. पुराना जुकाम-3

ऊपर से नीचे

1. रुपए का सोलहवां भाग-2
2. कुलबुलाना, तड़पना-5
3. जो कभी बूढ़ा न हो-3
4. बंदूक की गोली-4
5. अभिलेख, लेख-3
7. रात, रात्रि (उर्दू-2)
9. मादा का विलोम-2
11. धुन, लगाव-3
13. चरित्र, नीयत-3
14. तफरीह-5
15. अनाज रखने की जगह-4
16. टोंटी, नलका-2
18. बहुमूल्य रत्न-2
19. अनाथ, बेसहारा-3
21. डोली उठाने वाले-3
24. सफेद का विलोम -2

शब्द पहेली -8782 का हल

झ	न्ना	■	ते	प	श	क
र	■	दा	ल	ती	ता	■
ना	खु	दा	■	रा	इ	मा
■	श	■	ला	बा	न्द	■
ब	ग	दा	द	स	म	ध न
■	बा	■	द	ल	ना	तू
ग	र	म	■	क्ष	ब	ध भ
र	■	स्त	र	कृ	ष्टि	ला
ल	ब	■	क्षा	मि	ता	ई

Jagrutidaur.com, Bangalore

दैनिक पंचांग

10 जुलाई 2026 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

शुक्रवार 2026 वर्ष का 191 वा दिन
दिशाशूल पश्चिम **ऋतु** वर्षा ।
विक्रम संवत् 2083 **शक संवत्** 1948
मास आषाढ़ (दक्षिण भारत में ज्येष्ठ)
पक्ष कृष्ण **तिथि** दशमी 08.17 बजे को समाप्त। **नक्षत्र** भरणी 13.15 बजे को समाप्त। **योग** धृति 07.15 बजे तदनन्तर शूल 03.51 बजे रात्र को समाप्त।
करण विष्टि 08.17 बजे तदनन्तर बव 18.54 बजे को समाप्त।

ग्रह	स्थिति	लग्नारंभ	समय
सूर्य	मिथुन में	कर्क	05.54 बजे से
चंद्र	मेष में	सिंह	08.10 बजे से
मंगल	वृष में	कन्या	10.22 बजे से
बुध	मिथुन में	तुला	12.33 बजे से
गुरु	कर्क में	वृश्चिक	14.48 ब.से
शुक्र	सिंह में	धनु	17.04 बजे से
शनि	मीन में	मकर	19.09 बजे से
राहु	कुंभ में	कुंभ	20.55 बजे से
केतु	सिंह में	मीन	22.28 बजे से
		मेष	23.59 बजे से
राहुकाल 10.30 से 12.00 बजे तक		वृष	01.39 बजे से
		मिथुन	03.37 बजे से

चन्द्रायु 24.9 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 22° 15'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872766
जूलियन दिन 2461231.5
कलियुग संवत् 5128
कल्पारंभ संवत् 1972949128
सृष्टि उद्गारंभ संवत् 1955885128
वीरनिर्वाण संवत् 2552
हिजरी सन् 1448 **महीना** मोहर्रम
तारीख 24 **विशेष** मासिक कार्तिगाई, योगिनी एकादशी ।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
चर	05.55 से	07.23 बजे तक	रोग	05.38 से	07.1 बजे तक
लाभ	07.23 से	08.51 बजे तक	काल	07.11 से	08.43 बजे तक
अमृत	08.51 से	10.19 बजे तक	लाभ	08.43 से	10.15 बजे तक
काल	10.19 से	11.47 बजे तक	उद्वेग	10.15 से	11.47 बजे तक
शुभ	11.47 से	01.15 बजे तक	शुभ	11.47 से	01.19 बजे तक
रोग	01.15 से	02.43 बजे तक	अमृत	01.19 से	02.51 बजे तक
उद्वेग	02.43 से	04.10 बजे तक	चर	02.51 से	04.23 बजे तक
चर	04.10 से	05.38 बजे तक	रोग	04.23 से	05.55 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, मध्यम चर, अशुभ उद्वेग, रोग व काल। सभी समय

नगर की सड़कों पर आवारा पशुओं का डेरा, दुर्घटनाओं का बना रहता अंदेशा - नगर परिषद प्रशासन निष्क्रिय

पद्मेश न्यूज। लांजी।

नगर में एक बार फिर आवारा पशुओं की सड़कों पर बढ़ती संख्या लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। बारिश का मौसम शुरू होते ही नगर की मुख्य सड़कों, बाजार क्षेत्रों और चौक-चौराहों पर मवेशियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आवारा पशुओं के कारण जहां यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वहीं दुकानदारों, राहगीरों और वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

नगर की बालाघाट रोड़, आमगांव रोड़, सालेटेकरी रोड़, भिलाई रोड़ पर दिनभर गाय, बैल और अन्य मवेशी झुंड बनाकर बैठे रहते हैं, जिससे सड़कें संकरी हो जाती हैं और बड़े वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। कई बार वाहन चालक अचानक सामने आए पशुओं को बचाने के प्रयास में दुर्घटना का शिकार होते-होते बचते हैं। विशेष रूप से शाम के समय नगर क्षेत्र में स्थिति और

भी गंभीर हो जाती है, जब सड़क पर लोगों की भीड़ के बीच मवेशियों की आवाजाही बनी रहती है। सब्जी बाजार और किराना दुकानों के सामने घूम रहे आवारा पशु व्यापारियों के लिए भी सिरदर्द बने हुए हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पशु अचानक दुकानों के सामने पहुंचकर सब्जियों और फल नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। कई बार ग्राहकों के हाथों से सामान छीन लेने जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। नगर के नागरिकों ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति खरीदारी कर थैला मोटरसाइकिल में टांग देता है तो आवारा पशु उसे भी खाने लगते हैं, जिससे लोगों को असुविधा और नुकसान दोनों उठाना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद द्वारा पहले समय-समय पर आवारा पशुओं की धरपकड़ की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन लंबे समय से इस दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। इसका परिणाम यह है कि पशुपालक भी अब अपने मवेशियों को खुला छोड़ने लगे हैं। नगर परिषद के पास आवारा पशुओं की पकड़ के लिए विशेष वाहन उपलब्ध होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आ पा रही है। नगरवासियों ने मांग की है कि नगर परिषद नियमित अभियान चलाकर आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई करे और पशु मालिकों के खिलाफ जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे। नागरिकों का मानना है कि यदि पशु मालिकों पर सख्ती की जाए तो आवारा पशुओं की समस्या पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है।

नगर के लोगों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए कहा है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो आने वाले दिनों में दुर्घटनाओं और परेशानियों में और बढ़ोतरी हो सकती है।

ढेंचा एक उत्कृष्ट हरी खाद,कृषि विभाग उपलब्ध कराया बीज

पद्मेश न्यूज। लांजी । प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा किसानों को हरी खाद के रूप में ढेंचा (कैंचा) की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में लांजी विकासखंड के ग्राम मोहझरी में कृषक पूरनलाल अवसरे के खेत का कृषि विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर फसल की प्रगति का जायजा लिया।

कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा श्री अवसरे को हरी खाद के लिए ढेंचा का बीज उपलब्ध कराया गया था। किसान ने लगभग दो एकड़ क्षेत्र में इसकी बुवाई की है। 4 जुलाई को कृषि विस्तार अधिकारी ने खेत का निरीक्षण कर फसल की स्थिति का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान ढेंचा की फसल स्वस्थ, सघन एवं अच्छी बढ़वार वाली पाई गई, जिस पर अधिकारियों ने संतोष व्यक्त करते हुए किसान की सराहना की। निरीक्षण के दौरान कृषि विस्तार अधिकारी ने पूरनलाल अवसरे को हरी खाद तैयार करने के साथ-साथ ढेंचा के बीज उत्पादन की भी सलाह दी। अधिकारियों ने बताया कि बीज उत्पादन से किसान को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, वहीं क्षेत्र के अन्य किसानों को भी गुणवत्तापूर्ण स्थानीय बीज आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। अधिकारियों ने बताया कि ढेंचा एक उत्कृष्ट हरी खाद फसल है। इसे खेत में पलटने से मिट्टी में जैविक पदार्थ एवं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे भूमि की उर्वरता, जल धारण क्षमता और मिट्टी की संरचना में उल्लेखनीय सुधार होता है। इसके परिणामस्वरूप आगामी फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होती है। कृषि विभाग ने किसानों से हरी खाद की फसलों को अपनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे मृदा स्वास्थ्य संरक्षण

के साथ-साथ टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं तकनीकी मार्गदर्शन का लाभ उठाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। डेंचा फसल के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कुलदीप गणवीर, अमित नारनौरे, कृष्णा खरे,कबीर कुमार एवं क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी अंकित मेश्राम उपस्थित थे।

ट्रेक्टर के पहियों पर लगकर सड़कों पर आने वाली मिट्टी बन सकता है दुर्घटना का कारण

पद्मेश न्यूज। लांजी। भारी बारिश और धान की रोपाई के मौसम में खेतों में ट्रैक्टरों की भागदौड़ तेज हो गई है। आधुनिक यंत्रों के इस दौर में लकड़ी के हल अब लगभग गायब हो चुके हैं। किसान भाई अब ट्रैक्टर की मदद से खेतों में कीचड़ तैयार कर धान के पौधे रोप रहे हैं।

लेकिन इस प्रक्रिया में एक गंभीर समस्या सामने आ रही है। खेत से कीचड़ बनाकर जब ट्रैक्टर सड़क पर निकलता है तो उसके टायरों में चिपकी चिकनी मिट्टी सड़क पर धीरे-धीरे गिरने लगती है। इस फिसलन भरी मिट्टी पर सायकिलो से स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राएं एवं तेजी से गुजरने वाले दोपहिया वाहन अनियंत्रित होकर फिसल जाते हैं। ऐसे कई हादसे हाल के दिनों में सामने आए हैं, जिनमें कई लोग घायल भी हुए हैं। ट्रैक्टर चालकों से अपील है कि खेत में काम पूरा होने के बाद रोड पर निकलने से पहले थोड़ा समय निकालकर अपने ट्रैक्टर को खेत के अंदर या सड़क के किनारे खड़ा कर केच व्हील, रोटावेटर एवं टायरों की मिट्टी को साफ कर लें।इससे सड़क पर मिट्टी नहीं गिरेगी और फिसलन की समस्या समाप्त हो जाएगी। एक छोटी सी सावधानी कई परिवारों को दुर्घटना से बचा सकती है।

संबल योजना के तहत स्व. देवेश तिड़के की पत्नी श्रीमती गीता तिड़के को दी दो लाख रुपये की सहायता राशि

पद्मेश न्यूज। लांजी । प्रदेश सरकार की संबल योजना के तहत स्वर्गीय देवेश तिड़के की पत्नी श्रीमती गीता तिड़के को दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। यह राशि लांजी विधानसभा के विधायक राजकुमार कर्राहे, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा कालबेले, उपाध्यक्ष संदीप रामटेककर और वार्ड नंबर 09 के पार्षद किशोर रामटेककर के हाथों दी गई। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 09 के निवासियों ने गहरी संवेदना व्यक्त की। स्वर्गीय देवेश तिडके के निधन के बाद संबल कार्ड धारक परिवार को शासन की योजना के अंतर्गत यह आर्थिक सहायता दी गई, जिससे परिवार को कुछ राहत मिली है। विधायक राजकुमार कर्राहे ने सहायता राशि सौंपते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आम जनता के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। संबल योजना के तहत सामान्य मृत्यु पर दी जाने वाली यह सहायता कई जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है। कार्यक्रम के दौरान वार्डवासियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से विधायक राजकुमार कर्राहे को अवगत कराया। विधायक ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया।

पार्षद के निवास पर हुई संगठन की बैठक

इसके बाद पार्षद किशोर रामटेककर के निवास पर अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन मजबूती और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल सर्टिफिकेट अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रमुख रूप से लांजी मंडल अध्यक्ष आलोक चौरसिया, गौरव बैस, नवीन रामटेककर, महिला मोर्चा पदाधिकारी प्रेमा सिसोदिया, श्रीमती श्यामा मुरकुटे, वार्ड के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के बीच मजबूत समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचाने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

स्कूल बसों के सुरक्षित संचालन हेतु पुलिस ने चलाया विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान

पद्मेश न्यूज। लांजी। पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश शासन के द्वारा सभी संभाग आयुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किये गये है। वर्तमान में नवीन स्कूल सत्र प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में स्कूल बसों के सुरक्षित संचालन हेतु 10 दिवसीय विशेष स्कूल बस चेकिंग अभियान चलाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा सभी मापदण्डो की जांच की जाकर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिसके तहत बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्र में उक्त अभियान चलाये जाने हेतु थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है। जिसके परिपालन में लांजी थाना पुलिस बल के द्वारा उक्त अभियान के तहत एक जांच अभियान चलाया गया है।

बस चालको की लापरवाही से होते है अनेको हादसे-

बताते कि अनेको बार देखने में आये है बस चालकों की लापरवाही से अनेको हादसे घटित होते है। तेज गति से वाहन चलाना, यातायात नियमों का पालन नही करना। जिसके चलते अक्सर दुर्घटनाएँ घटित होती है। बच्चो की सुरक्षा पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं से एक है। इसी दृष्टि में उक्त 10 दिवसीय अभियान चलाया जाये तथा विभिन्न मापदण्डों की जांच कर कार्यवाही कि जाये।

स्कूल बसों की होगी सघन जांच, नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई

थाना प्रभारी लांजी मुकेश दुबलिया ने कहा कि जारी निर्देशों के अनुसार स्कूल बसों का फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाणपत्र (क्ष्ट) की जांच की जा रही है। साथ ही बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर तथा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण होगा। इसके अलावा स्कूल बस चालकों के पास कम से कम पांच वर्ष पुराना भारी वाहन लाइसेंस होना अनिवार्य रहेगा। चालकों एवं परिचालकों का पुलिस सत्यापन भी सुनिश्चित किया जाएगा। नशे की स्थिति में वाहन संचालन रोकने के लिए चालकों की

समय-समय पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच होगी। यदि कोई चालक नशे में वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को नहीं बैठाया जाएगा। स्कूलों के आसपास तथा प्रमुख मार्गों पर स्कूल बसों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम निर्धारित की गई है, साथ ही इन्ही मानकों की नियमित निगरानी की जाएगी। इसी परिपालन में 9 जुलाई को लांजी नगर में संचालित स्कूलों के वाहनो की सघन जांच की गई। साथ ही आगामी 10 दिनों तक उक्त अभियान चलाया जायेगा जिसमे उक्त नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

न्यायालय तहसीलदार तहसील-लांजी, जिला बालाघाट

ईश्तेहार

क्र./2417/तह./2026 — लांजी, दिनांक 03/07/2026
रा.प्र.क.0610/अ-27/2025-26
मौजा बेनेगांव, प.ह.न. - 16
रा.नि.म भानेगांव, तह. लांजी

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रदुमन पिता स्व0 लोकराम, जाति कुनबी, ग्राम टेडवा, तह. लांजी, जिला बालाघाट। द्वारा मौजा बेनेगांव, प.ह.न. 16, रा.नि.म. भानेगांव, तह. लांजी, जिला बालाघाट में स्थित भूमि ख. न. 451/1, 468/1 का कमशः रकबा 0.638, 0.627 हेक्टे. भूमि के भूमिस्वामी सिलिकराम पिता धेड्डू उर्फ झाड्डू की दिनांक 03.10.2025 को फौत हो जाने से फौती के आधार पर वैध वारसानों का नाम दर्ज किये जाने हेतु अपने साक्ष्य दस्तावेज मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि की छायाप्रति आवेदन पेश किया गया है।

अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 13/07/2026 के पूर्व स्वयं या अपने अभिभाषक/अधिवक्ता सहित उपस्थित होकर इस न्यायालय में दावा आपत्ति पेश कर सकते है। नियत तिथि उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

जारी दिनांक 03/07/2026
स्थान लांजी

तहसीलदार लाजी

जिला पंवार क्षत्रीय संगठन की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। 9 जुलाई को जिला पंवार क्षत्रीय संगठन, बालाघाट की प्रबंध कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक बालाघाट मुख्यालय में जिला अध्यक्ष श्री विशाल बिसेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।बैठक में आगामी 26 जुलाई को राष्ट्रीय पंवार महासभा की प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के संबंध में जिला संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्य निर्धारित किए गए। इसके तहत प्रातः 9:00 बजे सर्वपूज्य राजा भोज की प्रतिमा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं समाजजनों द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा। प्रातः 10:00 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल चौधरी द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। प्रातः 10:30 बजे स्वल्पाहार की व्यवस्था रहेगी तथा प्रातः 11:00 बजे महासभा की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिला पंवार क्षत्रीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का सम्मान किया जाएगा। सभी कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे।

बैठक में जिला संगठन द्वारा निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार जो पदाधिकारी संगठन के कार्यक्रमों में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें पद से निष्कासित कर उनके स्थान पर नए एवं योग्य सदस्यों को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया। जिला संगठन ने यह भी प्रस्ताव पारित किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट से भेंट कर पंवार समाज के विवादों के निपटारे के संबंध में ऐसा समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे थाना जाने से पूर्व संबंधित सूचना जिला संगठन के संज्ञान में लाई जा सके। इस संबंध में पुलिस प्रशासन से भी सहयोग प्राप्त करने के लिए विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गया। जिला संगठन द्वारा बालाघाट नगर महिला प्रकोष्ठ की नगर कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इसमें श्रीमती इंदु बिसेन को नगर अध्यक्ष, श्रीमती वंदना बोपचे को नगर महासचिव तथा श्रीमती सुमिता बिसेन को नगर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रबंध कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय महासभा की बैठक के कारण आगामी प्रतिभा सम्मान समारोह को स्थगित कर शरद महोत्सव के साथ आयोजित करने का निर्णय भी सर्वसम्मति से पारित किया। आज आयोजित प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक में जिला अध्यक्ष श्री विशाल बिसेन, जिला महासचिव डॉ. राजेंद्र एल. कटरे, जिला उपाध्यक्ष डॉ. प्रतिभा बिसेन, जिला कोषाध्यक्ष शैलेंद्र राहंगडाले, जिला सहसचिव अधिवक्ता अजय बिसेन, जिला उपाध्यक्ष गायत्री बिसेन तथा जिला उपाध्यक्ष गरिमा गौतम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मनरेगा की जगह वीबी-जी रामजी योजना पर बड़ा दांव

मप्र में 10 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान

भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्रामीण रोजगार को नई दिशा देने के उद्देश्य से वीबी-जी रामजी योजना लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नई योजना के लिए राज्य सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया है। यह राशि पहले संचालित मनरेगा योजना के मुकाबले कहीं अधिक मानी जा रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत पिछले पांच वर्षों में लगभग 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए थे, जबकि नई योजना में केवल एक वर्ष के लिए ही इससे अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी। इसके साथ ही मजदूरी

के न्यूनतम स्तर में भी वृद्धि का प्रावधान किया गया है। नई व्यवस्था में राज्य सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी पहले की तुलना में अधिक होगी।

कृषि और पशुपालन पर भी फोकस

वीबी-जी रामजी योजना का दायरा मनरेगा की तुलना में काफी व्यापक रखा गया है। जहां मनरेगा मुख्य रूप से तालाब, कुएं, सड़क और अन्य निर्माण कार्यों तक सीमित थी, वहीं नई योजना में रोजगार के साथ आय बढ़ाने वाले कार्यों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत अब जिन क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा उनमें कृषि आधारित कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका से जुड़े अन्य उत्पादक कार्य शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य केवल मजदूरी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की स्थायी आय बढ़ाने वाले कार्यों को भी प्रोत्साहित करना है।

ग्रामीण विकास बजट में सबसे बड़ा हिस्सा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजट में वीबी-जी रामजी योजना का हिस्सा सबसे बड़ा रहेगा। विभागीय अनुमान के अनुसार योजना पर 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

मनरेगा और वीबी-जी रामजी में बड़ा फर्क

वीबी-जी रामजी में ग्रामीणों को दिए जाने वाले कामों को विस्तार दिया गया है। मनरेगा केवल गांवों में कुएं, तालाब और सडक़ बनाने जैसे कामों तक ही सीमित था। लेकिन नई योजना में पशुपालन, मछली पालन, कृषि से जुड़े कार्यों को भी शामिल किया गया है। पिछली योजना में केवल रोजगार दिया जाता था। नई योजना में रोजगार के साथ ग्रामीणों को पक्की आय उपलब्ध कराना है।

एनएमसी के रडार पर मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज

परिसर में नहीं लगाए सीसीटीवी; आयोग ने थमाया नोटिस

भोपाल। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी एनएमसी ने पढ़ाई की गुणवत्ता और अस्पताल प्रबंधन की निगरानी के लिए देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों को अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा है। इसके लिए तय हुआ था कि सभी मेडिकल कॉलेज निर्धारित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर आयोग को उसकी लाइव फीड उपलब्ध कराएंगे। प्रदेश के पांच सरकारी मेडिकल कालेज इस आदेश की नाफरमानी कर रहे हैं। एनएमसी ने देश भर के उन 70 मेडिकल कॉलेजों की सूची जारी की है, जिन्होंने अभी तक यह आदेश लागू नहीं किया। इस सूची में प्रदेश के गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा, डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम, शासकीय मेडिकल कॉलेज शहडोल और शासकीय मेडिकल कॉलेज श्योपुर शामिल हैं।

कंट्रोल सेंटर से जोडऩा है अनिवार्य

दरअसल, एनएमसी के यूजीएमएसआर-2023 और पीजीएमएसआर-2023 संशोधन के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के परिसर में 25 निर्धारित जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। एनवीआर लगाकर 30 दिन तक का वीडियो रिकार्ड सुरक्षित रखना जरूरी है। लाइव फीड एनएमसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोडऩा है। एनएमसी का कहना है कि इसका मकसद एमबीएस की पढ़ाई, परीक्षा और अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा में पारदर्शिता लाना है। इसके लिए एनएमसी वर्ष 2022 से लगातार पत्राचार कर रहा है।

मप्र के 7,788 करोड़ रुपये के दावे का क्या हुआ?

भोपाल। दिल्ली में सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े अंतरराज्यीय भुगतान विवाद के समाधान को लेकर हुए समझौते पर प्रदेश कांग्रेस ने मोहन सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूछा कि जब मध्यप्रदेश ने सरदार सरोवर परियोजना से हुए नुकसान के आधार पर 7,788 करोड़ रुपये का दावा किया था, तो आखिर वह दावा किस आधार पर छोड़ दिया गया। उन्होंने पूरे समझौते पर श्वेत पत्र जारी करने और विधानसभा में इस पर चर्चा कराने की मांग की।

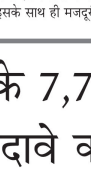

भोपाल स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पटवारी ने कहा कि नर्मदा मध्यप्रदेश की जीवनरेखा है और सरदार सरोवर बांध बनने से सबसे अधिक नुकसान भी प्रदेश को ही हुआ। उनके अनुसार सबसे अधिक कृषि भूमि, वन क्षेत्र और आदिवासी परिवारों का विस्थापन मध्यप्रदेश में हुआ तथा पुनर्वास का सबसे बड़ा बोझ भी राज्य ने उठाया। इसी आधार पर तत्कालीन सरकार ने 7,788 करोड़ रुपये का दावा प्रस्तुत किया था। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार अब इस दावे का कोई उल्लेख नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह प्रचार कर रही है कि गुजरात की लगभग 1,500 करोड़ रुपये की देनदारी को 421 करोड़ रुपये में निपटाकर 1,079 करोड़ रुपये की बचत कर ली गई, लेकिन यह नहीं बता रही कि मध्यप्रदेश के हजारों करोड़ रुपये के दावे का क्या हुआ। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर किस कानूनी और वित्तीय आधार पर यह फैसला लिया गया। क्या इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा हुई? क्या विधानसभा में विपक्ष को विश्वास में लिया गया? क्या पर्याक्षण विशेषज्ञों और विषय विशेषज्ञों से राय ली गई?

इतना बड़ा दावा आखिर कैसे समाप्त हो गया

पटवारी ने दावा किया कि दिल्ली जाने के दौरान विमान में उनकी मुलाकात उन अधिकारियों से हुई थी जो इस बैठक में शामिल होने जा रहे थे। अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि वे सरदार सरोवर से जुड़ी लगभग 7,500 करोड़ रुपये की देनदारियों के संबंध में पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार स्पष्ट करे कि इतना बड़ा दावा आखिर कैसे समाप्त हो गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश पर 5.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो चुका है और सरकार लगातार नया कर्ज लेकर प्रचार-प्रसार तथा सरकारी आयोजनों पर खर्च कर रही है। उन्होंने हाल ही में 3,400 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने का भी उल्लेख किया। पटवारी ने मांग की कि सरकार सरदार सरोवर समझौते से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करे और यह स्पष्ट करे कि मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच किन शर्तों पर सहमति बनी। साथ ही यह भी बताया जाए कि यदि मध्यप्रदेश का दावा उचित था तो उसे क्यों छोड़ा गया और यदि उचित नहीं था तो वह दावा किस आधार पर किया गया था।

गृह विभाग में ही अटकी डीपीसी

हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रमोशन पर फिर लगा ब्रेक, हजारों पुलिसकर्मियों को झटका

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस महकमे में सालों से जंग खा रही पदोन्नति की फाइलें जब हाईकोर्ट के हंटर के बाद खुलीं, तो लगा कि अब इंसाफ होगा। लेकिन, सिस्टम की सुस्ती और नीतिगत यू-टर्न ने हजारों वर्दीधारियों की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया है। जिस प्रक्रिया को अदालत की फटकार के बाद युद्धस्तर पर शुरू किया गया था, उसे पुलिस मुख्यालय ने एक झटके में आगामी आदेश तक फ्रीज कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश के दूसरे विभागों में पदोन्नति की गाडिय़ां सरपट दौड़ रही हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री के प्रभार वाले 'गृह विभाग' में ही आकर ब्रेक लग गया है।

लंबे समय से कार्यवाहक उच्च पद प्रभार से वंचित मऊगंज के सब-इंस्पेक्टर सहित सूबे के कई पुलिस अधिकारियों ने जब अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि पुलिस रेगुलेशन के तहत प्रभार देने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में 30 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। अदालती आदेश के बाद क्ष्ा।क्त में मानो करंट दौड़ गया था। आनन-फानन में जिलों और रेंज स्तर पर समितियां बनीं, एसपी स्तर से पात्र अफसरों की सूचियां मंगवाई गईं। लगा कि बरसों का इंतजार अब खत्म होने को है, लेकिन ऐन वक्त पर 'ऊपर' से खेल हो गया।

2 जुलाई के फरमान ने फेरा पानी

आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी इस कवायद को 2 जुलाई 2026 को जारी पीएचक्यू के एक नए आदेश ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के 30 जून के एक पत्र और विधिक परामर्श का हवाला देकर पूरी प्रक्रिया को आगामी आदेश तक सस्पेंड कर दिया गया है। इस 'प्रशासनिक यू-टर्न' ने सब-इंस्पेक्टरों से लेकर निरीक्षकों तक को वापस निराशा की उसी कतार में खड़ा कर दिया है, जहां वे सालों से खड़े थे।

कार्यवाहक का ठप्पा हटाने को तरस रहे 183 डीएसपी

सिर्फ प्रभार ही नहीं, नियमित पदोन्नति का संकट भी पुलिस महकमे में नासूर बन चुका है। सूबे के 183 कार्यवाहक डीएसपी आज भी नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। साल 2024 में पहले 103 और फिर बाद में कुल 183 निरीक्षकों को कार्यवाहक डीएसपी की कमान सौंपी गई थी। ये अफसर सिर्फ इसलिए तरस रहे हैं ताकि उनके नाम के आगे से 'कार्यवाहक' का ठप्पा हटे और उनके करियर का आगे का रास्ता साफ हो सके।

जब हर जगह हरी झंडी, तो गृह विभाग में 'नो एंट्री' क्यों?

एमपी लोक सेवा आयोग में 6 जुलाई से विभिन्न विभागों की डीपीसी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सामान्य प्रशासन, राजस्व और स्कूल शिक्षा जैसे बड़े विभागों में प्रमोशन की लिस्ट फाइनल हो रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस गृह विभाग की कमान खुद सूबे के मुखिया संभाल रहे हैं, वहां डीपीसी की तारीख तक तय क्यों नहीं हो पा रही है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक अड़ंगा है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कानूनी और नीतिगत खिचड़ी पक रही है? कोर्ट की अवमानना के जोखिम के बावजूद इस प्रक्रिया को क्यों रोका गया, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने वाले सूबे के हजारों पुलिसकर्मी आज खुद को प्रशासनिक चक्रव्यूह में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

10 वर्ष बाद जेल विभाग में शुरू हुई पदोन्नति प्रक्रिया, चरणबद्ध जारी होंगे आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के पदोन्नति संबंधी निर्णय के बाद जेल विभाग में करीब 10 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेल मुख्यालय ने विभिन्न संवर्गों के पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग का मानना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी सुधार आएगा।

जारी आदेशों के अनुसार सहायक ग्रेड-1, स्टेनो टाइपिस्ट, लेखापाल, उप अधीक्षक (उद्योग), वरिष्ठ बुनाई प्रशिक्षक, वरिष्ठ बढ़ईगिरी प्रशिक्षक, दफ्तरी तथा जमादार सहित विभिन्न पदों पर पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति के साथ ही उन्हें नवीन पदों के अनुरूप जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

जेल विभाग ने बताया कि पूरी पदोन्नति प्रक्रिया शासन के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से संचालित की जा रही है। विभाग अन्य पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। आगामी समय में शेष पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश भी चरणबद्ध रूप से जारी किए जाएंगे।

महानिदेशक जेल वरुण कपूर ने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि पदोन्नति केवल अधिकार नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का अवसर भी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नए दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन कर विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाएंगे।

प्रदेश के 473 सरकारी कॉलेजों में जनभागीदारी समितियां ठप

भोपाल। मध्यप्रदेश के 40 जिलों के करीब 473 शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पिछले एक वर्ष से रिक्त पड़े हैं। राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने के कारण अधिकांश कॉलेजों में समितियों का गठन ही नहीं हो सका है। इसका सीधा असर कॉलेजों के विकास कार्यों, वित्तीय निर्णयों, नए पाठ्यक्रमों, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य प्रशासनिक कार्यों पर पड़ रहा है। वर्तमान में समितियों के उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित जिले के कलेक्टर या उनके नामित प्रतिनिधि जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन समयाभाव के कारण नियमित बैठकें नहीं हो पा रही हैं, जिससे जनभागीदारी समिति के माध्यम से लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लंबित हैं।

प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों के विकास और स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में जनभागीदारी समिति की व्यवस्था शुरू की गई थी। समिति में सामान्य परिषद, प्रबंध समिति और वित्त समिति जैसी तीन प्रमुख इकाइयां होती हैं। समिति के अध्यक्ष का मनोनयन शासन द्वारा किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष कलेक्टर और सचिव संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य होते हैं। एक समिति में औसतन 20 सदस्य शामिल किए जाते हैं।

कोरोना के बाद नहीं हुई नियुक्तियां

उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, कोरोना काल के बाद से राजनीतिक कारणों के चलते अधिकांश कॉलेजों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप समितियां निष्क्रिय हो गई हैं और कॉलेजों का संचालन केवल प्राचार्य एवं कलेक्टर स्तर पर उपलब्ध सीमित अधिकारों के आधार पर किया जा रहा है।

विकास कार्य और नए प्रस्ताव अटके

जनभागीदारी समिति के अभाव में कॉलेजों में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लंबित हैं। इनमें नए भवनों का निर्माण, प्रयोगशालाओं और उपकरणों की खरीद, अतिथि शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति, स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारण तथा नए कोर्स शुरू करने जैसे निर्णय शामिल हैं। भोपाल के भेल शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय जैन ने बताया कि समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से कॉलेज कलेक्टर के मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई विकास कार्यों और वित्तीय मामलों में समिति की स्वीकृति आवश्यक होती है, इसलिए अनेक निर्णय लंबित हैं। वहीं शासकीय महाविद्यालय इटारसी के प्राध्यापक डॉ. संजय आर्य का कहना है कि समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने से नए पाठ्यक्रम शुरू करने, आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य विकास योजनाओं पर निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। कई प्रस्ताव लंबे समय से स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। जनभागीदारी समिति के पास कई जिम्मेदारियां होती है। जिनमें स्थानीय सहयोग से महाविद्यालय का समग्र विकास, जनसहयोग एवं अन्य स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाना, अतिथि विद्वानों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और मानदेय तय करना, भवन, प्रयोगशाला, खेल मैदान और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास करना।

एंबुलेंस न मिलने से 4 मौत का मामला, नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला, लिखा-

यह हादसा नहीं, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की हत्या

भोपाल। मध्यप्रदेश के मंडला जिले में एंबुलेंस न मिलने के कारण एक गर्भवती महिला को ऑटो से अस्पताल ले जाना पड़ा। इस दौरान महिला ने रास्ते में ही चार बच्चों को जन्म दिया, लेकिन चिकित्सीय सहायता न मिलने की वजह से चारों नवजातों की मौत हो गई। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मोहन यादव सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तीखा हमला बोला है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ङ्ग' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधे सवाल किए हैं। सिंघार ने लिखा कि मोहन यादव जी, इन चार मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या इसलिए जनता टैक्स देती है कि प्रसूता को एम्बुलेंस की

जगह ऑटो मिले? कहाँ गई वह एयर एंबुलेंस जिसके नाम पर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं? क्या आपकी सरकार में गरीब की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं बची?

इवेंट्स पर करोड़ों खर्च, गरीब के लिए एंबुलेंस नहीं

सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार हेलीकॉप्टर, इवेंट और विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा सकती है, लेकिन एक गर्भवती महिला तक समय पर एक बुनियादी एम्बुलेंस नहीं पहुँचा सकती। उन्होंने इस घटना को सामान्य हादसा मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह भाजपा सरकार की संवेदनहीनता और सूबे की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। उमंग सिंघार ने अपने बयान के अंत में कहा कि इन चार मासूमों की मौत सिर्फ एक पीड़ित परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की भाजपा सरकार के कुशासन का सबसे दर्दनाक और जीवंत प्रमाण है। इस लापरवाही और बदइंतजामी को लेकर आज पूरा मध्य प्रदेश सरकार से जवाब माँग रहा है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सख्ती, लापरवाही पर अधिकारियों को नोटिस और ठेकेदारों का पंजीयन निलंबित

भोपाल। प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। 6 जुलाई को मुख्य अभियंताओं के सात दलों ने रायसेन, पांढुर्णा, शिवपुरी, बुरहानपुर, उमरिया, मंदसौर और निवाड़ी जिलों में निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुके 34 कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इनमें सड़क एवं पुल, पीआईयू, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम और भवन विकास निगम के कार्य शामिल थे।

निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा प्रमुख अभियंता (सड़क/पुल) आर.एल. वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में की गई। समीक्षा के दौरान 20 निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुधार के लिए तत्काल निर्देश जारी किए गए, जबकि गंभीर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए गए।

बुरहानपुर जिले के सुंदर नगर-कुंदन डेयरी रोड स्थित पंडारोल नाला पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल में गुणवत्ता संबंधी कमियां मिलने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और तत्कालीन कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, हिवरा फाटा-हैदरपुर फाटा सड़क निर्माण कार्य में भी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और उपयंत्री के खिलाफ नोटिस जारी करने तथा निर्माण एजेंसी मेसर्स कालिका फर्नीचर इंडस्ट्रीज, खंडवा का पंजीयन निलंबित करने के निर्देश दिए गए।

लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

महादेव ऐप जुआ मामले में सीबीआई ने 6 चार्जशीट दाखिल की

- राजधानी में रहने वाले आरोपी भाई विदेश भागे - लुक आउट नोटिस जारी है दोनो के खिलाफ

भोपाल। बहुचर्चित अंतरराष्ट्रीय स्तर के महादेव एप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 6 चार्जशीट दाखिल की हैं। विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार ये चार्जशीट असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धम्माणी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओ के अपराधों के लिए दाखिल की गई हैं। सीबीआई ने मुख्य सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सहित अन्य लोगों के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी दाखिल किए हैं, जिनके खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। महादेव ऐप से जुड़े एक अन्य मामले में सीबीआई 66 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट दाखिल की हैं। इनमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और सट्टेबाजी सिंडिकेट पैनल के सदस्य शामिल हैं, जिनके माध्यम से अपराध से हुई कमाई का लेन-देन किया जाता था। ये 5 चार्जशीट आईपीसी और छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दाखिल की गई थीं।

- देश के सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक है महादेव ऐप

महादेव ऐप देश में सामने आए सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट में से एक है, जिसे भारत के बाहर से चलाया जाता था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने वाले एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के रूप में विकसित किया। जांच से पता चला है कि सिंडिकेट देश भर में अवैध सट्टेबाजी पैनल संचालित करता था। उपयोगकर्ताओं को जोड़ता था और गेम व सट्टेबाजी बाजार चलाता था, जिससे अवैध मुनाफा कमाया जाता था। इस मुनाफे को म्यूल अकाउंट्स (दूसरे के नाम

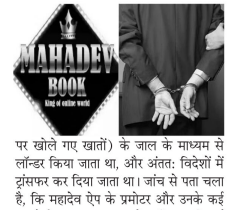

पर खोले गए खातों) के जाल के माध्यम से लॉन्डर किया जाता था, और अंततः विदेशों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। जांच से पता चला है, कि महादेव ऐप के प्रमोटर और उनके कई सहयोगी कुछ साल पहले पश्चिम एशियाई देशों में भाग गए थे, और भारत के बाहर से इस नेटवर्क को चलाना जारी रखे हुए हैं। विदेश भाग गए 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस सिंडिकेट के पूरे दायरे और इसे प्राप्त राजनीतिक व नौकरशाही संरक्षण का पता लगाने तथा इसमें शामिल अन्य सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आगे की जांच जारी है। भविष्य में और चार्जशीट दाखिल की जाएंगी।

भोपाल के रहने वाले हैआहूजा ब्रदर्स

सौरभ चंद्राकर के साथ भोपाल के दो भाई विशाल आहूजा और धीरज अहूजा के खिलाफ भी सीबीआई ने चार्ज सीट पेश की। विशाल आहूजा और धीरज अहूजा भोपाल में लालघाटी स्थित रैपिड ट्रेवल्स के संचालक है, और सौरभ चंद्राकर के राइट हैंड है। उनके यहां प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। उसके बाद दोनों भाई विदेश भाग गए थे उनके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, और दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी है।

आकाश चोपड़ा ने चौथे टी20 के लिए बनायी अपने पसंदीदा टीम, सूर्यकुमार को कप्तान बनाया

सैमसन और यशस्वी को रखा सलामी बल्लेबाज के लिए, चहल और सिराज भी टीम में शामिल

ब्रिस्टल। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के चौथे मैच के लिए अपनी वैकल्पिक अंतिम एकदश बनायी है। आकाश की इस टीम में बल्लेबाजी संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की वापसी हुई है। आकाश ने पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी सैमसन और यशस्वी जायसवाल को दी है। वहीं टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव को दी है। रोचक बात ये है कि इस दौरे के लिए यश्स्वी और सूर्यकुमार को शामिल नहीं किया गया है। सूर्यकुमार को तो कप्तानी से भी बाहर कर दिया है।

वहीं पहले टी20 में खराब प्रदर्शन के बाद सैमसन को भी बाहर कर दिया गया है हालांकि आकाश ने इन दोनो ही खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। इस मैच में टीम चयन में उन्होंने तीन मुख्य बातों पर ध्यान दिया है। इसमें पहला है कि खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया हो, वह अभी रिटायर न हुआ हों, और सबसे महत्वपूर्ण, वह वर्तमान में भारतीय

टी20 टीम की मुख्य योजना का हिस्सा न हों।

इस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी इस विशेष एकादश के लिए सैमसन और जायसवाल को ओपनर के तौर पर चुना है। सैमसन, जो इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा तो हैं लेकिन जिम्बाब्वे दौरे के लिए उन्हें आराम दिया गया पर आकाश ने उन्हें चोपड़ा ने अपनी टीम का अहम हिस्सा माना है। वहीं यशस्वी ने भी टी20 क्रिकेट में अपने विस्फोटक प्रदर्शन से प्रभावित किया, और बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के नाते उन्हें पारी की शुरुआत के लिए शामिल किया है। इस टीम की कप्तानी आकाश ने सूर्यकुमार यादव को दी है जबकि असल में सूर्या को भारतीय टी20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है। वह इस दौरे के लिए टीम में भी नहीं हैं। वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लगातार दो आईपीएल ट्रॉफी जिताने वाले रजत पाटीदार को उप-कप्तान बनाया गया है। रजत भी इस दौरे के लिए टीम में नहीं हैं। टीम में ध्रुव जुरेल, नमन धीर और करुणाल पांड्या को भी जगह दी गयी है।

वहीं गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी अनुकूल रॉय, अनुभवी भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल को दी गयी है। भुवनेश्वर ने आईपीएल 2026 में 28 विकेट लेकर यह साबित किया कि वह ज किसी भी परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।आकाश चोपड़ा ने मोहम्मद सिराज के चयन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वह भी टी20 क्रिकेट में प्रभावी हो सकते हैं, जबकि अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को भी उनकी फिरकी का जादू दिखाने के लिए टीम में जगह मिली है। यह एकादश भारतीय क्रिकेट की गहराई और उन खिलाड़ियों की क्षमताओं को उजागर करती है हालांकि ये खिलाड़ी मौजूदा टीम में शामिल नहीं किये गये हैं।

ब्रिस्टल में आज तक नहीं हारी है भारतीय टीम

ब्रिस्टल। भारतीय टीम आज यहां मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी के प्रयास करेगी। भारतीय टीम अभी इस सीरीज में 0-2 से पीछे है। वहीं दूसरी और मेजबान टीम का लक्ष्य इस मैच में जीत के साथ ही सीरीज में अपनी बढ़त 3-0 करना रहेगा। भारतीय टीम के लिए राहत की बात ये है कि ब्रिस्टल के इस मैदान पर भारतीय टीम पिछले 27 सालों से नहीं हारी है।

भारतीय टीम ने इस मैदान में अब तक कुल चार मुकाबले खेले हैं। इसमें से तीन एकदिवसीय और एक टी20 है। इन सभी मैचों में भारतीय टीम जीती है। इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने कुल चार शतक लगाये हैं।

आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्रिस्टल में भारतीय टीम के जीतने की शुरुआत साल 1999 विश्व कप से हुई थी। तब भारतीय टीम ने यहां केन्या को हराया था। उस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 140 रन और राहुल द्रविड़ ने नाबाद 104 रन बनाये थे।

वहीं इसके बाद साल 2002 में नेटवेस्ट सीरीज के दौरान भारत ने श्रीलंका को इसी मैदान पर हुए एकदिवसीय मैच में हराया था। इस दौरान 304 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने श्रीलंका को 63 रनों से हराया था। तब सचिन तेंदुलकर ने 113 रनों की शानदार पारी खेली थी।

वहीं तीसरा मुकाबला साल 2007 के इंग्लैंड दौरे पर खेला गया था, जहाँ भारत ने मेजबान टीम को 9 रनों से हराया था। तब पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 329 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 99 रनों की यादगार पारी खेली थी, जबकिराहुल द्रविड़ ने भी नाबाद 92 रन बनाए थे।

इस मैदान पर भारतीय टीम ने एकमात्र टी20 मुकाबला 2018 के इंग्लैंड दौरे पर खेला था। उस मैच में रोहित ने नाबाद शतक 100 रन बनाये थे। इंग्लैंड द्वारा दिए गए 199 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने रोहित के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 18.4 ओवर में ही 7 विकेट रहते आसानी से हासिल कर लिया था। अब देखना है कि इस बार भारतीय टीम यहां जीत पाती है या नहीं।

2026 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतना चाहते है प्रीति पंवार

नई दिल्ली। युवा महिला मुक्केबाज प्रीति पंवार का लक्ष्य आगामी 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतना है। 54 किलोग्राम वर्ग में उतरने वाली प्रीति ने पिछले कुछ समय में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। 23 साल की इस मुक्केबाज का मानना है कि राष्ट्रमंडल खेलों के बाद वह एशियाई खेलों और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भी पदक जीतना चाहती हैं। प्रीति ने हाल ही में कहा, मैं राष्ट्रमंडल खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती हूं और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहती हूं। साथ ही कहा कि खेल में कुछ भी पहले से तय नहीं होता। कई बार हम योजनाएं बनाते हैं, पर परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं आते, इसलिए हर मुकाबले को पूरी गंभीरता से लेना महत्वपूर्ण है।

गौरतलब है कि प्रीति ने साल 2023 सीनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, जहां उनके प्रदर्शन ने काफी प्रभावित किया। इसके बाद हांगझोउ एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया, जो उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि, पेरिस ओलंपिक से पहले हेपेटाइटिस-ए से संक्रमित होने के कारण उनकी तैयारियां बुरी तरह प्रभावित हुईं। बावजूद इसके, उन्होंने ओलंपिक में राउंड ऑफ-16 तक का सफर तय किया। इससे इस मुक्केबाज का मनोबल बढ़ा। पेरिस ओलंपिक के बाद प्रीति ने शानदार वापसी करते हुए लगातार सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, जो उनकी दृढ़ता का प्रमाण था। इसके तुरंत बाद, स्पेन में आयोजित बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उन्होंने रजत पदक हासिल किया। ही में, कड़े मुकाबलों के बीच उन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया है।

मेसी के नाम फीफा विश्वकप में दर्ज हुआ ये अनचाहा रिकार्ड

मियामी। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने फीफा विश्वकप फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम के क्वार्टर फाइनल तक के सफर में अहम भूमिका निभाई है। मेसी सबसे अधिक गोल के लिए मिलने वाले गोल्डन बूट की दौड़ में भी बने हुए हैं पर इसके बाद भी पैनाल्टी किक पर गोल दागने के मामले में वह फिसड्डी साबित हुए हैं।मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो ने टूर्नामेंट के एक सत्र में दो पेनल्टी लेने के बाद भी गोल नहीं कर पाये। मिस्र के खिलाफ राउंड ऑफ मुकाबले में भी वह पेनाल्टी को गोल में नहीं बदल पाये।

मेसी फुटबॉल के मैदान पर वह सब कुछ करने में सक्षम रहे हैं जो वे चाहते हैं पर जब भी पैनाल्टी लेने की बात आती है वह पिछड़ जाते हैं जबकि यह फुटबॉल के सबसे आसान शॉट्स में से एक है। मेसी जब पेनल्टी किक लेने के लिए गेंद के सामने खड़े होते हैं तो वे गोल से केवल 12 गज की दूरी पर होते है और उनके पास निशाना लगाने के लिए 196 वर्ग फीट की जगह होती है। इसके साथ ही उनके रोकने के लिए केवल एक गोलकीपर होता है। फिर भी किसी न किसी तरह, यही वह एकमात्र परिस्थिति है जहां उनकी सुपरपावर अचानक उनका साथ छोड़ देती हैं। मेसी का विश्व कप में पेनल्टी किक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। मेसी ने विश्व कप में अबतक कुल 8 पेनल्टी किक लिए हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 4 बार ही गोल में बदला है। वहीं मेसी ने अपने क्लब और अर्जेंटीना के लिए अपने 148 पेनल्टी किक में से केवल 114 को गोल में बदला है जो कि उनके जैसे स्टार फुटबॉलर के लिए बेहद खराब आंकड़ा है।

नेमार अब क्लब करियर को भी कह सकते हैं अलविदा

रियो डि जिनेरियो। ब्राजील के फीफा विश्वकप फुटबॉल से बाहर होने के बाद संन्यास लेने वाले स्टार खिलाड़ी नेमार अब क्लब करियर को भी अलविदा कह सकते हैं। इसका एक कारण उनकी खराब फिटनेस भी है जिससे वह लगातार परेशान रहे हैं । वहीं उनके क्लब सैंटोस ने उन्हें अपने भविष्य के बारे में विचार करने के लिए कुछ दिनों का समय दिया है जिससे वह आराम से फैसला कर सकें। नेमार ने इससे पहले रविवार को नॉर्वे के खिलाफ 2-1 की हार के तुरंत बाद ही ब्राजील के विश्व कप अभियान का अंत कर दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने के बाद क्लब स्तर पर भी खेलेंगे या पूरी तरह से खेल से दूर हो जाएंगे। वहीं ब्राजीलियाई मीडिया में इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि नेमार, जिनके सैंटोस के साथ मौजूदा अनुबंध में अभी लगभग छह महीने बाकी हैं आगे क्या फैसला लेते हैं। इस रिपोर्ट्स के अनुसार, सैंटोस प्रबंधन ने नेमार को सोचने का पर्याप्त समय दिया है। क्लब अधिकारियों का कहना है कि वे छुट्टियों के बाद नेमार और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनके अगले कदम पर गहन बात करेंगे। फिलहाल, नेमार अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में समय बिता रहे हैं और उन्हें कम से कम 10 दिनों का आराम दिया गया है। इससे पहले संन्यास की घोषणा करते हुए नेमार ने भावुक होकर कहा था, मैंने पूरी कोशिश की पर विश्वकप में असफल रहा।

हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स मामले में अभिषेक को दी राहत: आपत्तिजनक पोस्ट हटाने अंतरिम आदेश दिये जाएंगे

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राहत देते हुए कहा कि अभिषेक के व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने वाली विभिन्न आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक्स को हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। अदालत का यह फैसला अभिषेक शर्मा द्वारा अपने पर्सनैलिटी राइट्स के संरक्षण की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर दिया है।

अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समन जारी किया है और कहा है कि अभिषेक की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें उनकी अनुमति के बिना उनकी छवि का व्यावसायिक उपयोग करने और उन्हें बदनाम करने वाली ऑनलाइन सामग्री को हटाने का निर्देश दिया जाएगा। अभिषेक के वकील ने कोर्ट को उन विशिष्ट यूआरएल (यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर) की जानकारी देने के लिए एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है, जहाँ ये आपत्तिजनक पोस्ट और सामग्री मौजूद हैं।

वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि कुछ आपत्तिजनक पोस्ट पहले ही हटा दिए गए हैं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभी भी दो ऐसी पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें अभिषेक के लिए अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसके अतिरिक्त अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी दो ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर क्रिकेटर की अनुमति के बिना व्यावसायिक हितों के लिए उनकी छवि का उपयोग किया जा रहा था, ये सामग्री भी अब तक हटाई नहीं गई है। वहीं इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिषेक के वकील को संबंधित स्क्रीनशॉट और उल्लेख करने वाले यूआरएल के प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। पिछली सुनवाई में ये दस्तावेज याचिका के साथ संलग्न नहीं किए गए थे, जिसके चलते कोर्ट ने बिना उचित जांच के कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था और सुनवाई को टाल दिया था। बाद में, अभिषेक के वकील ने संबंधित स्क्रीनशॉट और विस्तृत जानकारी के साथ एक अलग हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया।

अभिषेक ने अपनी याचिका में पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें बदनाम करने के मकसद से बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंटेंट को भी हटाये जाने की मांग की है। इस मामले में, मेटा (जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है) के अलावा अमेज़न ने भी अदालत को आश्वासन दिया है कि वे अभिषेक की छवि को खराब करने वाले पोस्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे।

आईसीसी ने वेस्टइंडीज पर लगाया जुर्माना, डब्लयूटीसी अंक भी काटे

दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) धीमी ओवर गति के लिए वेस्टइंडीज टीम पर जुर्माना लगाते हुए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत काट लिया और साथ ही उनके महत्वपूर्ण विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्लयूटीसी) के दो अंक भी घटा दिए, इससे कैरेबियाई टीम को अंकतालिका में नुकसान हुआ है।

वहीं मेजबान वेस्टइंडीज ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 की ऐतिहासिक जीत हासिल की थी पर आईसीसी के इस कदम से उसकी खुशियों पर पानी फिर गया है।

आईसीसी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ये कार्रवाई नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ और बारबुडा में खेले गए टेस्ट मैच के बाद की। वहीं एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जवागल श्रीनाथ ने वेस्टइंडीज को निर्धारित समय में समय दो ओवर कम फेंकने का दोषी पाया। ऐसे में उसे आचारसंहिता के उल्लंघन का आरोपी पाया गया। न्यूनतम ओवर-रेट नियम के तहत तय समय में प्रत्येक ओवर पूरा न करने पर खिलाड़ियों पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा मैच फीस के 50 प्रतिशत तक हो सकती है।

वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने इस सजा को स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा को मान लिया, जिससे किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। आरोप ऑन-फील्ड अंपायर पॉल रीफेल और अहसान रजा, थर्ड अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और फोर्थ अंपायर डेइटन बटलर ने लगाए थे।

मैच फीस जुर्माने के अलावा, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की शर्तों के के तहत, एक टीम पर हर ओवर कम होने पर एक अंक का जुर्माना लगाया जाता है। इसी कारण वेस्टइंडीज के कुल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंकों में से दो अंक कम कर दिए गए। इन दो अंकों के कटने से उनके कुल अंक 20 से घटकर 18 रह गए हैं।

अंक खोन के बावजूद वेस्टइंडीज टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में अभी भी आठवें स्थान पर बनी हुई है। उनके प्रतिशत अंक (पीसीटी) कम होकर 15 हो गए हैं। यह उनके चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने की उम्मीदों के लिए एक और झटका है, क्योंकि उसने इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक केवल एक ही मैच जीता है, जो श्रीलंका के खिलाफ इसी सीरीज में जीता था। अभी डब्ल्यूटीसी तालिका में ऑस्ट्रेलिया 87.5 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष पर है। वहीं मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 48.15 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान 8.33प्रतिशत अंकों के साथ सबसे नीचे नौवें स्थान पर है। वेस्टइंडीज के खाते में अब 18 ही अंक रह गए हैं। फिलहाल टॉप-2 में डिफेंडिंग चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया है। भारत 5वें पायदान पर है।

बाबर आजम को फिर से टी20 कप्तान बना सकता है पीसीबी

लाहौर । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अनुभवी बल्लेबाज बाबार आजम को एक बार फिर टी20 में भी कप्तान बना सकता है। बाबर पहले भी इस प्रारुप में कप्तान रहे हैं और उनका कार्यकाल अच्छा रहा है। हाल में जिस प्रकार से उन्हें टेस्ट में कप्तानी मिली है। उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब इस बल्लेबाज को आगामी मैचों से पहले टी20 टीम की कप्तानी फिर से सौंपी जा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार, पीसीबी राष्ट्रीय टीम के हाल के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा है। यदि इस निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो बाबर एक बार फिर सलमान अली आगा की जगह लेंगे, जो बदलाव के दौर में टीम की कमान संभाल रहे थे पर उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा है।

बोर्ड एक बार फिर देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी पर अपना भरोसा जता सकता है। हालांकि, पीसीबी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है पर रिपोर्टों में कहा गया है कि बाबर

का नाम सबसे आगे चल रहा है। पाकिस्तान को आगामी अंतरराष्ट्रीय मैचों और आईसीसी इवेंट्स के लिए तैयारी करनी है।

बाबर पहले भी तीनों प्रारुपों में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं और टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्हें अच्छी सफलता मिली थी। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 2021 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था और 2022 के संस्करण में उपविजेता रहा था। यह प्रदर्शन उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। इतना ही नहीं, अपने पिछले कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के टी20 कप्तानों में उनका जीत का प्रतिशत भी सबसे बेहतरीन रहा था, जो उनकी प्रभावी रणनीतियों और टीम को एकजुट रखने की क्षमता को दर्शाता है।

वह सफेद गेंद क्रिकेट में बाबर पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक बने हुए हैं। माना जाता है कि उनका अनुभव, कुशल नेतृत्व क्षमता और कप्तानी की जटिल जरूरतों की गहरी समझ उन प्रमुख कारकों में शामिल हैं जो बोर्ड की इस सोच को प्रभावित कर रहे हैं।

विश्वनाथ और चंद्रिका के नेतृत्व में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उतरेगी भारतीय टीम

नई दिल्ली। एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश और विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में स्वर्ण विजेता रही चंद्रिका भोरेश पुजारी की अगुवाई में भारतीय मुक्केबाजी दल शुक्रवार से इंडोनेशिया में शुरू होने वाली अंडर-23 और अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने के इरादे से उतरेगा। भारतीय टीम में दोनों आयु वर्गों के लिए प्रतिभाशाली मुक्केबाज शामिल हैं, जिनसे इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में उसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीदें हैं।

इस चैंपियनशिप से भारतीय युवा मुक्केबाजों के लिए अपनी प्रतिभा और कौशल को एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ साबित करने का एक बेहतरीन अवसर मिलेगा। भारतीय टीम ने इस प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय शिविर में प्रशिक्षण हासिल किया है। जिससे उसका लक्ष्य एशियाई चैम्पियनशिप में पदक जीतना रहेगा। टीम में शामिल मुक्केबाज न केवल अपने लिए, बल्कि देश के लिए भी गौरव हासिल करने को उत्सुक हैं।

अंडर-23 पुरुष वर्ग में, 50 किग्रा भार वर्ग के एशियाई चैंपियन विश्वनाथ सुरेश टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ गंगा (55 किग्रा), सागर जाखड़ (60 किग्रा), वंशज (65 किग्रा), हितेश (70 किग्रा), नीरज (75 किग्रा), आर्यन मलिक (80 किग्रा), राँकी चौधरी (85 किग्रा), हेमंत सांगवान (90 किग्रा) और इशान कटारिया (90 किग्रा) जैसे प्रतिभाशाली मुक्केबाज शामिल हैं। यह एक अनुभव और युवा जोश का मिश्रण है, जो टीम को मजबूती प्रदान करता है।

वहीं महिला अंडर-23 टीम की अगुवाई निधि (48 किग्रा) और तनु (51 किग्रा) करेंगी। इस टीम में निशा (54 किग्रा), प्राची (57 किग्रा), निकिता चंद (60 किग्रा), काजल (65 किग्रा), शिवानी (70 किग्रा), मुस्कान (75 किग्रा), नैना (80 किग्रा) और प्रियंका (80 किग्रा) जैसी कई और प्रतिभाशाली मुक्केबाज भी हैं, जिनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ये सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर चुकी हैं और अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं।

अंडर-19 महिला टीम विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप की स्वर्ण पदक विजेता चंद्रिका भोरेश पुजारी के नेतृत्व में रिंग में उतरेगी। उनके साथ गुंजन (48 किग्रा), चिरोम जॉयश्री देवी (54 किग्रा) और प्राची (57 किग्रा) सहित कई उभरती हुई युवा प्रतिभाएं शामिल हैं, जो अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करने का लक्ष्य रखेंगी। यह टीम भविष्य के लिए भारतीय मुक्केबाजी की मजबूत नींव तैयार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अंडर-19 पुरुष टीम में भी युवा प्रतिभाओं को भरपूर मौका मिला है, जिसमें लैरेनलाकपम अंबेडकर मैतेई (50 किग्रा), आदित्य (55 किग्रा) और सिकंदर (60 किग्रा) जैसे मुक्केबाज शामिल हैं। चयनकर्ताओं को इन सभी खिलाड़ियों से टूर्नामेंट में प्रभावी प्रदर्शन और पदक जीतने की प्रबल उम्मीद है।

प्रदर्शन के साथ ही फिटनेस भी जरुरी - मनप्रीत

नई दिल्ली । भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने कहा है टीम में जगह बनाये रखने के लिए प्रदर्शन के साथ ही फिटनेस पर भी ध्यान देना सबसे जरुरी है। मनप्रीत ने कहा कि फिटनेस बनी रहने के कारण ही वह भारत की ओर से सबसे अधिक मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने में सफल रहे हैं। मनप्रीत ने खेल में अपनी सफलता का श्रेय अपने फिटनेस को दिया है। साथ ही कहा है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के कारण ही वह इतने लंबे समय तक वह देश के लिए खेल पाए हैं। इस खिलाड़ी ने कहा कि टीम में बने रहने के लिए उम्र और अनुभव पर ध्यान न देते हुए लगातार बेहतर प्रदर्शन करना होता है।

कार्यालय ग्राम पंचायत भोण्डवा

जनपद पंचायत बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र.

।। निविदा सूचना ।।

विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत भोण्डवा में विधायक मद, सांसद मद, 15 वॉ वित्त, 16 वॉ वित्त, एस बी एम, सर्व शिक्षा अभियान, गौण खनिज मद, मनरेगा मद, बीबी जीरामजी मद, 5वॉ वित्त, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत की मद, जनपद पंचायत की मद, एवं अन्य मद से निर्माण कार्य, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, वेस्टवेयर, पक्की नाली, सी सी सड़क, यात्री प्रतिक्षालय, पार्इप पुलिया, रपटा पुलिया, चेक डेम, स्टाप डेम, सभा मंच, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, काम्पलेक्स निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य हेतु ईंट, रेत, सीमेंट, लोहा, शौचालय शीट, गिटटी, वाश बेसिन, नल, टाईल्स, मिक्शर मशीन, स्ट्रीट लाईट के सामाग्री, कम्प्युटर से संबंधित सामाग्री, इलेक्ट्रानिक सामाग्री, एवं अन्य सामाग्री हेतु इच्छुक निविदाकार 10/09/2026 से 13/09/2026 तक कार्यालय ग्राम पंचायत भोण्डवा जनपद पंचायत बालाघाट में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकते है निविदा पर अंतिम निर्णय ग्राम पंचायत का मान्य होगा।

मुकेश पाटेल, सरपंच | जयपाल मर्सकोले, उपसरपंच | विमल बोरीकर, प्रभारी सचिव

एवं समस्त पंच गण ग्राम पंचायत भोण्डवा जिला बालाघाट(म.प्र.)

देश में हर दिन औसतन 13 स्कूल बंद, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक असर

यूडाइस प्लस की रिपोर्ट से हुए खुलासे से शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

नई दिल्ली, । देश में स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है। शिक्षा मंत्रालय की यूडाइस प्लस (यूडीआईएसई+) 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार बीते एक वर्ष में देशभर में 4,791 स्कूल बंद हो गए, यानी औसतन हर दिन 13 स्कूलों का संचालन बंद हो गया। वर्ष 2024-25 में देश में कुल 14,71,473 स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 14,66,682 रह गए। सबसे अधिक 2,426 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हुए, जबकि तेलंगाना में 1,392, पश्चिम बंगाल में 568, आंध्र प्रदेश में 474, तमिलनाडु में 369, कर्नाटक में 281 और हिमाचल प्रदेश में 266 स्कूल बंद हुए।

इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है, कि कई राज्यों में छोटे स्कूलों का बड़े विद्यालयों में विलय किया जा रहा है, जिसके कारण स्कूलों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ राज्यों में नए स्कूल खुले हैं, लेकिन वहां भी छात्रों के नामांकन में गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। बिहार में 946 नए स्कूल जुड़े, इसके बावजूद छात्र नामांकन में 4.37 लाख की कमी दर्ज की गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 234 और दिल्ली में 87 नए स्कूल बढ़े, लेकिन दोनों राज्यों में भी नामांकन घटा है।

बिना एनरोलमेंट वाले स्कूल घटे

ताजा रिपोर्ट में यह भी सामने आया, कि देश में पहली बार जीरो एनरोलमेंट यानी बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या घटी है। ऐसे स्कूलों की संख्या 7,993 से घटकर 5,663 रह गई है। हालांकि इन स्कूलों में अब भी 20,667 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं।

इन राज्यों में बिना छात्र वाले स्कूलों की संख्या बढ़ी

पश्चिम बंगाल में स्थिति इसके विपरीत है। वहां बिना छात्रों वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 4,133 हो गई है, जिनमें 19,502 शिक्षक तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे स्कूल 81 से बढ़कर 313 हो गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पहली बार 149 जीरो एनरोलमेंट स्कूल दर्ज किए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या राष्ट्रीय स्तर पर घटकर 1,00,843 रह गई है, जो पिछले वर्ष 1,04,125 थी। हालांकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ी है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना या घटाना समाधान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षकों की नियुक्ति छात्रों की वास्तविक संख्या के अनुरूप हो। जिन विद्यालयों में छात्र नहीं हैं, वहां से शिक्षकों का स्थानांतरण उन स्कूलों में किया जाना चाहिए जहां शिक्षकों की कमी है। इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी और संतुलित बन सकेगी।

ई20 पेट्रोल का विरोध और उसके नुकसान की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा

ई20 पेट्रोल से माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, इससे गाड़ी खराब नहीं होती

नई दिल्ली। देश में इस समय पेट्रोल में एथनॉल मिलाने को लेकर आम लोगों में मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या वाकई पेट्रोल में एथनॉल मिलाने से गाडिय़ों की परफॉर्मेंस और माइलेज पर क्या असर पड़ता है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है। इसलिए जब पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा बढ़ती है, तो गाड़ी का औसत माइलेज थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फर्क बहुत मामूली होगा। नितिन गडकरी ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर फैल रही ई20 पेट्रोल से गाडिय़ों को नुकसान की बातें भ्रामक हैं और उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये खबरें एक गलत धारणा बनाने की कोशिश का हिस्सा हैं।

माइलेज के सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा कि दो बातें समझनी जरूरी हैं। पहली बात, एथनॉल और पेट्रोल की कैलोरिफिक वैल्यू अलग होती है। एथनॉल की कैलोरिफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है। यह एक सच्चाई है। दूसरी बात, गाड़ी का माइलेज सिर्फ ईंधन पर ही निर्भर नहीं करता। यह सडक़ और ट्रैफिक की स्थिति पर भी निर्भर करता है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भारी ट्रैफिक होने के कारण गाडिय़ां अक्सर लो गियर में चलती हैं। इससे भी माइलेज कम हो जाता है। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि एआरएआई की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाडिय़ों में माइलेज की कोई समस्या नहीं होती। इसी वजह से सरकार फ्लेक्स फ्यूल इंजन तकनीक को बढ़ावा देने पर भी काम कर रही है।

पेट्रोल में एथनॉल मिक्स करने से पहले किए गए कई टेस्ट

उन्होंने बताया कि ई20 पेट्रोल (20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल) को पूरे देश में लागू करने से पहले इसको लेकर कई तरह के टेस्ट किए गए थे। ये टेस्ट पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) और वाहन बनाने वाली कंपनियों ने किए थे। सभी जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही ई20 पेट्रोल पूरे देश में शुरू किया गया। नितिन गडकरी ने कहा कि वाहन बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी कारों में अगर सर्विस के दौरान पुर्जे बदलने की जरूरत हो, तो उन्हें बदल दिया जाए। उन्होंने कहा, मुझे एक भी ऐसी गाड़ी दिखाइए जिसे ई20 पेट्रोल की वजह से नुकसान हुआ हो।

हरदीप सिंह निज्जर ने अर्श डल्ला को कनाडा भागने के लिए किया था प्रेरित

नई दिल्ली। खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क और संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में दायर आरोपपत्र में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपपत्र के अनुसार, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ने कुख्यात गैंगस्टर अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला को भारत छोड़कर कनाडा जाने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद अर्श डल्ला वर्ष 2017 में कनाडा पहुंचा और वहीं से अपने आपराधिक तथा आतंकी नेटवर्क का संचालन करने लगा। जानकारी के अनुसार, यह आरोपपत्र वर्ष 2022 में अर्श डल्ला के करीबी सहयोगी तरनजोत सिंह उर्फ टन्ना के खिलाफ दायर किया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि जेल से रिहा होने के बाद अर्श डल्ला, हरदीप सिंह निज्जर के संपर्क में आया और उसके प्रभाव में कनाडा चला गया। वहां उसने भारत में सक्रिय अपने गिरोह और आतंकी गतिविधियों का संचालन शुरू किया। जांच एजेंसियों का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर लंबे समय से कनाडा में प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों का नेटवर्क खड़ा करने और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्रिय था। भारत पहले भी कनाडा और अमेरिका को इस संबंध में कई बार जानकारी देता रहा है। हाल में अमेरिका में सार्वजनिक हुए अभियोग और भारतीय एजेंसियों के पुराने इनपुट में भी कई समानताएं सामने आई हैं। उल्लेखनीय है कि हरदीप सिंह निज्जर की वर्ष 2023 में कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर भारत और कनाडा के बीच लंबे समय तक कूटनीतिक तनाव बना रहा। वहीं हालिया घटनाक्रम में कनाडा की पुलिस ने कहा है कि अमेरिकी आरोपों में भारतीय सरकार की भूमिका से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं है।

ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत

टीएमसी के बैंक खातों से लेन-देन को दी मंजूरी, खर्च पर होगी स्पेशल ऑफिसर की नजर

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों में लेन-देन सामान्य करने का आदेश दिया है। अदालत ने इन खातों पर नजर रखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर भी नियुक्त किया है। अदालत ने ये अंतरिम व्यवस्था आगामी 30 सितंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है, ताकि राजनीतिक दल को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोजमर्रा के जरूरी खर्च किए जा सकें।

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने टीएमसी के तीन फ्रीज किए गए बैंक खातों में सीमित और सामान्य लेनदेन को फिर से बहाल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने ये अंतरिम व्यवस्था आगामी 30 सितंबर तक जारी रखने का आदेश दिया है।

रोजमर्रा के खर्चों के लिए ही मिलेगी अनुमति

अदालत ने कहा कि बैंक

खातों से होने वाला ये वित्तीय लेनदेन केवल राजनीतिक दल को चलाने के लिए होने वाले रोजमर्रा (डे-टू-डे) के खर्चों के लिए ही सीमित रहेगा, जैसा कि टीएमसी द्वारा अपने पूरक हलफनामे में बताया है। नियुक्त विशेष अधिकारी जस्टिस सुब्रत तालुकदार इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार के बाहरी खर्च या भुगतान की अनुमति नहीं देंगे। कोर्ट ने खर्च की निगरानी करने के लिए रिटायर्ड जज जस्टिस सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है। वह तृणमूल कांग्रेस के दो जिम्मेदार अधिकारियों के चेक पर हस्ताक्षर के आधार पर पैसे खर्च करने की अनुमति देंगे।

कोर्ट ने जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान बेंच ने शिकायतकर्ता से बेहद प्रासंगिक सवाल पूछे कि उन्होंने 4 मई से पहले इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई थी। अदालत ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने स्वयं इन खातों से पैसे स्वीकार किए थे और चुनाव लडक़र विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस से भी कड़े सवाल किए कि खातों को फ्रीज करने के पीछे आखिर कौन से आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे।

भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली बेसल इंसुलिन

डायबिटीज मरीजों को हफ्ते में एक बार ही लगाना होगा इंजेक्शन

नई दिल्ली। डेनमार्क की दवा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने बुधवार को भारत में अविक्ली(इंसुलिन आइकोडेक) लॉन्च की। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की पहली सप्ताह में एक बार दी जाने वाली बेसल इंसुलिन है, जो टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के वयस्क मरीजों के लिए है। इसके आने से रोजाना लगने वाले 365 इंसुलिन इंजेक्शन घटकर साल में 52 रह जाएंगे। कंपनी के मुताबिक, अविक्लीका उद्देश्य भारत में इंसुलिन शुरू करने में होने वाली देरी को कम करना है। नोवो नॉर्डिस्क का कहना है कि रोज इंजेक्शन लगाने का डर मरीजों के बीच इंसुलिन थेरेपी शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण औसतन सात से नौ साल की देरी हो जाती है।

कंपनी ने 700 यूनिट का पैक 2611 रूपए में लॉन्च किया है। यानी इसकी कीमत 3.73 रूपए प्रति यूनिट पड़ेगी, जो मौजूदा दैनिक बेसल इंसुलिन की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक सस्ती बताई गई है। यदि किसी मरीज को रोज 10 यूनिट इंसुलिन की जरूरत होती है, तो उसे सप्ताह में 70 यूनिट इंसुलिन लगेगी, जिसकी लागत करीब 261 रूपए प्रति सप्ताह होगी। मुंबई के डायबिटीज विशेषज्ञ डॉ. राजीव कोविल ने कहा कि अविक्लीकी सबसे बड़ी खासियत इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत है। उनके मुताबिक, यह मौजूदा दैनिक बेसल इंसुलिन के करीब है, जिससे यह तकनीक सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल में इस दवा ने कई मामलों में दैनिक बेसल इंसुलिन के बराबर या उससे बेहतर ब्लड शुगर नियंत्रण दिखाया है।

आंध्र प्रदेश में कोरोना से व्यक्ति की मौत

अमरावती। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 46 साल के एक व्यक्ति की कोविड-19 से मौत हो गई। व्यक्ति को पिछले महीने 24 जून को वेल्लोर के सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच में उसे निमोनिया पाया गया। कोविड की आशंका पर 26 जून को टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांच में पता चला कि उसके दोनों फेफड़े गंभीर रूप से संक्रमित होकर निमोनिया की चपेट में आ गए थे। इलाज के दौरान 28 जून को उसकी मौत हो गई। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रवि बाबू ने बताया कि मृतक शराब पीता था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मृतक को सांस फूलने और खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। मृतक के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उनकी ट्रेसिंग भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में सैनिटाइजेशन भी शुरू कर दिया है।

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ रच रही नई साजिश

नई दिल्ली। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ब्रिटेन और कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। खुफिया सूचनाओं के अनुसार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी समर्थक भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जाने वाले लोगों पर हमलों की साजिश रच रहे हैं। खुफिया अधिकारियों के अनुसार, हाल के वर्षों में ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा घृणा अपराध और हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। पहले जहां ऐसी घटनाएं छिटपुट होती थीं, वहीं अब आशंका है कि इन्हें अधिक संगठित तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। इन संभावित हमलों को रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही हैं।

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देने वाली आईएसआई ने यूरोप में सक्रिय अपने नेटवर्क को ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय समुदाय के खिलाफ गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी के अनुसार, अब इन घटनाओं को एक सुनियोजित अभियान के तहत अंजाम दिए जाने की आशंका है। अधिकारी ने कहा, आईएसआई भारतीय समुदाय के खिलाफ सिलसिलेवार और समन्वित हमलों की योजना बना रही है। इन तत्वों द्वारा लोगों को भारत समर्थक या प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक बताकर निशाना बनाया जा सकता है और इसी बहाने ऐसे हमलों को अंजाम देने की तैयारी है। अधिकारी के मुताबिक, आईएसआई की रणनीति में यह बदलाव खालिस्तान आंदोलन को गति नहीं मिलने से पैदा हुई निराशा का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि निशाने पर केवल भारतीय समुदाय ही नहीं होगा, बल्कि खालिस्तान से जुड़े मामलों की जांच और कार्रवाई करने वाली भारतीय एजेंसियों को भी लक्ष्य बनाने की योजना बनाई जा रही है।

अवैध इमारतों के लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों दी चेतावनी

4 अगस्त तक कार्रवाई नहीं की तो शीर्ष अधिकारियों की खैर नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में गैर-कानूनी और असुरक्षित इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, पटना और तमिलनाडु के नगर निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन अधिकारियों से उन जर्जर इमारतों को गिराने या खाली कराने के लिए की गई कार्रवाई की स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है, जिनसे आपदा का खतरा हो सकता है। हाल ही में साकेत और मालवीय नगर में इमारत गिरने की घटना व लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोर्ट के 20 मई के निर्देशों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी बेंच के सामने रखें। कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे 4 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों।

सुप्रीम कोर्ट ने साकेत, मालवीय नगर और लाजपत नगर का तय समय-सीमा के अंदर जमीनी सर्वे करने के लिए आईआईटी दिल्ली के दो सीनियर प्रोफेसर और दो ड्राफ्ट्समैन वाली एक स्पेशल टीम (कमेटी) बनाने को कहा। इस टीम के साथ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी भी होंगे। इसी तरह का सर्वे सरोजिनी नगर में भी किया जाएगा, जो नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के अधिकारी क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस काम में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए और कमेटी को एक सच्ची रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हम यह साफ करते हैं कि कमेटी की ओर से सच्ची रिपोर्ट देने में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अगर हमें इस पर शक हुआ तो रिपोर्ट की सच्चाई जानने के लिए इस कोर्ट से एक स्पेशल टीम भेजी जा सकती है।

कमिश्नर, सीईओ पर होगा एक्शन

कोर्ट ने यह चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम और विकास प्राधिकरण के कमिश्नर, सीईओ और दूसरे जिम्मेदार अधिकारी अगली तारीख तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट रिकार्ड पर नहीं रखते या कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करते तो, उनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोर्ट सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों यानी ऐसी नगर पालिकाओं या संबंधित विकास प्राधिकरण के कमिश्नर या सीईओ के खिलाफ 'सुओ मोटो' अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

कोर्ट ने आगे चेतावनी दी कि यदि अगली तारीख पर यह पाया गया कि पहले दिए गए निर्देशों और तोडफ़ोड़ के आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो संबंधित अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी प्रमुखों की सीधी जिम्मेदारी तय की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर अगली तारीख पर हमें पता चला कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो सीधे तौर पर हम उस अथॉरिटी के सीईओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बेंच ने एमिकस (कोर्ट की ओर से नियुक्त वकील) की इस बात से सहमति जताई कि अथॉरिटीज अपनी साख बचाने वाला रवैया अपना रही हैं, वे इमारत गिरने या आग लगने की घटनाओं के बाद सिर्फ बिल्डरों को गिरफ्तार करती हैं, लेकिन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए जिम्मेदार अपने ही अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती।

अभाविप ने उत्साहपूर्वक मनाया 78वॉ स्थापना एवं राष्ट्रीय विघार्थी दिवस

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 78वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत गुरुवार को नगर के प्रमुख चौराहे काली पुतली चौक पर भव्य भारत माता आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ताओं, नगर के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने विधिवत भारत माता की आरती की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर, मिष्ठान वितरित कर,अभाविप के प्रेरणादायी गीतों की धुन पर पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम को यादगार बनाया।आयोजन को लेकर कार्यक्रम स्थल को पुष्पों एवं रंगोली से बड़ी सुंदरता से सजाया गया था, जिसमें अभाविप के 78वें स्थापना दिवस की झलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी।

9 जुलाई 1949 को हुई थी,परिषद की स्थापना

बताया गया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी,तभी से प्रतिवर्ष इस दिवस को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जिलेभर में साप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आगामी दिनों में भी विभिन्न रचनात्मक एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व कार्यकर्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए वर्तमान कार्यकर्ताओं को संगठन के प्रति समर्पण एवं निरंतर सक्रियता बनाए रखने हेतु प्रेरित किया।कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में राष्ट्रभक्ति एवं उल्लास का वातावरण बना रहा, तथा उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की।

आज का दिन सबसे प्रमुख दिन है- आदित्य

इस अवसर पर अभाविप जिला संयोजक आदित्य अग्रवाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एवं अभाविप का स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि विद्यार्थी शक्ति के संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आज का दिवस सबसे प्रमुख रहा, क्योंकि यह दिवस संगठन की स्थापना की उस भावना का स्मरण कराता है जिसके आधार पर लाखों विद्यार्थी ज्ञान, शील और एकता के मार्ग पर चलकर राष्ट्र सेवा में समर्पित हुए हैं।

यह व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मूल मंत्र है-कलश

नगर मंत्री कलश असाटी ने कहा कि विद्यार्थी परिषद प्रारंभ से ही व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के मूल मंत्र पर कार्य करती आई है, और आज का यह भव्य आयोजन उसी परंपरा की एक कड़ी है। उन्होंने उपस्थित सभी वर्तमान एवं पूर्व कार्यकर्ताओं तथा नगर के गणमान्य नागरिकों का हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल एवं गरिमामय बनाया।कार्यक्रम में विघार्थी परिषद कार्यकर्ता मुख्य रूप से जिला संगठन मंत्री राहुल विश्वकर्मा,प्रांत कार्यकारिणी सदस्य कोमल भंडारकर, कुबेर सिंह बैस, राहुल बुरडे, अमन दशरिए, प्रियांशु तिवारी, आरव कुमरे, मुदित धनेश्वर, आशु पटले, भारती ठाकरे, प्रियांशु तिवारी, सागर कोहले लक्की बुरडे, मोहित बोकड़े, हार्दिक बुरडे, रोहित कोल्हे, हिमांशु हरिनखेड़े अभय बांगड़े, प्रख्यात मिश्रा, आर्या चौधरी, नारायण पटले, क्रिस सोनवाने, आशा डोंगरे, खुशी मुनेश्वर एवं समस्त पूर्व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पद्मेश न्यूज़
शहर | समाज | गांव

/padmeshmedia /padmeshmedia epaper.balaghatexpress.in E-mail: balaghatexpress@gmail.com

न्यूज गैलरी

जीएसटी रिटर्न में देरी पर 56 व्यापारियों को नोटिस, विलंब शुल्क वसूली की कार्यवाही शुरू

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। बालाघाट वाणिज्यिक कर विभाग ने समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है। विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर त्रस्त्रक्र-1 रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने वाले 56 पंजीकृत व्यापारियों को विलंब शुल्क के संबंध में सूचना पत्र जारी किए हैं। साथ ही उनसे विलंब शुल्क की वसूली की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।

राज्य कर सहायक आयुक्त श्रीमती सरिता सिरसाम ने बताया कि प्रत्येक पंजीकृत करदाता के लिए समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करना वैधानिक दायित्व है। इसके बावजूद कई करदाता निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले नियमित मासिक करदाताओं के लिए त्रस्त्रक्र-1 रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 11 तारीख तथा त्रस्त्रक्र-3क्र की अंतिम तिथि 20 तारीख निर्धारित है। वहीं, 5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वाले त्रैमासिक नियमित करदाताओं के लिए त्रस्त्रक्र-1 की अंतिम तिथि 13 तारीख और त्रस्त्रक्र-3क्र की अंतिम तिथि 22 तारीख तय की गई है।

सहायक आयुक्त श्रीमती सिरसाम ने स्पष्ट किया कि रिटर्न दाखिल करने में विलंब होने पर नियमानुसार विलंब शुल्क, ब्याज एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं के विरुद्ध जीएसटी पंजीयन निरस्तीकरण जैसी कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी लंबित करदाताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया जीएसटी रिटर्न तत्काल दाखिल करें तथा भविष्य में निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करें। विभाग के अनुसार समय पर रिटर्न दाखिल करने से कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है और कर अनुपालन को मजबूती मिलती है। विभाग ने यह भी कहा है कि किसी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत समस्या होने पर करदाता राज्य कर सहायक आयुक्त कार्यालय, बालाघाट वृत्त अथवा जीएसटी सहायता केंद्र से संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

5 रुपये की थाली पर संकट, गंदगी के बीच भोजन करने को मजबूर जरूरतमंद

दीनदयाल अंत्योदय रसोई में एक माह से मटन मार्केट का दूषित पानी बना मुसीबत,किचन तक पहुंच रहा गंदा पानी, मजबूरी में भोजन कर रहे जरूरतमंद, नपा. ने माना समस्या, कार्रवाई का दिया भरोसा

सिटी रिपोर्टर।
पद्मेश न्यूज। बालाघाट।

शासन की महत्वाकांक्षी दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का उद्देश्य गरीब, श्रमिक, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को मात्र पांच रुपये में पौष्टिक, स्वच्छ और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना है। लेकिन बालाघाट शहर के अवंतीबाई चौक स्थित बूढी रोड पर संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई की वर्तमान स्थिति इस योजना के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े कर रही है। यहां पिछले लगभग एक माह से गंदगी, जलभराव और असहनीय बदबू के बीच रसोई का संचालन किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि रसोई परिसर में कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोग मजबूरी में इसी स्थान पर भोजन करने को विवश हैं। जानकारी के अनुसार रसोई के आसपास नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। नाली खोदकर छोड़ दिए जाने से पानी की निकासी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। इसके चलते पीछे स्थित मटन मार्केट की ओर से निकलने वाला गंदा एवं बदबूदार पानी सीधे रसोई परिसर में प्रवेश कर रहा है। यही नहीं, यह दूषित पानी रसोई के किचन क्षेत्र तक पहुंच रहा है, जिससे पूरे परिसर में दुर्गंध फैल गई है। रसोई में भोजन तैयार करने और परोसने का कार्य भी इसी वातावरण में किया जा रहा है।

रसोई संचालन से जुड़ी महिला कर्मी ने बताया कि यह समस्या कोई एक-दो दिन की नहीं बल्कि पिछले लगभग एक महीने से बनी हुई है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष तथा प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कई बार लिखित और मौखिक रूप से इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लगातार गंदगी और बदबू रहने के कारण यहां आने वाले लोगों की संख्या भी प्रभावित हुई है और कई लोग भोजन किए बिना ही वापस लौट जाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि रसोई को लगभग पांच दिनों तक बंद रखना पड़ा था। बाद में किसी तरह अस्थायी व्यवस्था कर दोबारा संचालन शुरू किया गया, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। मटन मार्केट का गंदा पानी लगातार परिसर में आ रहा है और किचन में भी पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसे माहौल में स्वच्छता बनाए रखना बेहद कठिन हो गया है। रसोई संचालकों का कहना है कि जिस स्थान पर स्वच्छता और साफ-सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, वहीं सबसे अधिक गंदगी फैली हुई है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यहां भोजन करने आने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। वहीं रसोई में भोजन करने पहुंचे जरूरतमंद लोगों ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके पास यही एक सहारा है। उन्होंने कहा कि गंदगी और बदबू के बीच भोजन करना उनकी मजबूरी है। कई लोगों ने बताया कि यहां बैठकर भोजन करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें यही भोजन करना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो यहां संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा हो सकता है। स्थानीय नागरिकों ने भी नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि या तो रसोई परिसर की स्वच्छता और जल निकासी की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त की जाए अथवा इस रसोई को किसी सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। उनका कहना है कि शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य गरीबों को सम्मानपूर्वक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान हालात में योजना का उद्देश्य ही प्रभावित होता नजर आ रहा है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं। ऐसे में रसोई परिसर में फैली गंदगी, दूषित पानी और बदबू न केवल योजना की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगा रही है, बल्कि नगर पालिका की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस गंभीर समस्या का कब तक स्थायी समाधान करता है, ताकि किसी संभावित बीमारी या संक्रमण की स्थिति बनने से पहले जरूरतमंदों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

मटन मार्केट की गंदगी से ही बढ़ी समस्या - भारती सुरजीत ठाकुर

इस पूरे मामले में नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत ठाकुर से दूरभाष पर चर्चा की गई। उन्होंने स्वीकार किया कि दीनदयाल रसोई के समीप स्थित मटन मार्केट से निकलने वाले गंदे पानी और दुर्गंध के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि स्वयं मौके का निरीक्षण कर मटन मार्केट में व्यवसाय करने वालों को नोटिस जारी कराया गया है तथा स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार, नियमित रूप से सफाई कराए जाने के बावजूद कुछ समय बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। कई बार समझाइश और चेतावनी देने के बाद भी कुछ व्यवसायी गंदे पानी और अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से निस्तारण नहीं कर रहे हैं, जिससे आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है और दीनदयाल रसोई का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि संबंधित व्यवसायियों ने जल्द ही स्वच्छता व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो नगर पालिका उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।

आवश्यकता है
डाटा एण्ट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है
संपर्क करें-पद्मेश सिटी केबल
काली पुतली चौक, बालाघाट

ग्रेसियस कॉलेज
2026-27 ADMISSION OPEN
SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को म. प्र. शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति
नर्सिंग
बी.एस.सी. नर्सिंग
4 वर्षीय डिग्री
मान्यता : आई.एन. सी. नई दिल्ली, म.प्र. नर्सिंग रजि. काउंसिल भोपाल, राजा शंकरशाह वि. वि. छिंदवाड़ा
फार्मेसी
बी.फार्मा. 4 वर्षीय डिग्री
डी.फार्मा. 2 वर्षीय डिप्लोमा
मान्यता : पी.सी.आई. नई दिल्ली, आर.जी.पी.जी. भोपाल, डी.टी.ई. भोपाल
योग्यता : 12 वी उत्तीर्ण (जीव विज्ञान/गणित संकाय)
73820 53000 / 73820 54000
आर.टी.ओ.ऑफिस के पास, वारासिवनी रोड, बरबसपुर - कायदी,बालाघाट म.प्र.

जिला अस्पताल से उपचाराधीन मरीज लापता

कोतवाली पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी

पद्मेश न्यूज। बालाघाट। शहीद भगत सिंह शासकीय जिला अस्पताल बालाघाट में उपचाररत एक मरीज संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मरीज शिखरचंद मरकाम पिता भैयालाल मरकाम 54 वर्ष ग्राम बुढ़ियागांव थाना लामता निवासी बताया गया है है। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिखरचंद मरकाम खेती किसानी का कार्य करते हैं। पेट दर्द की शिकायत के चलते उन्हें 1 जुलाई को उनके पुत्र धर्मेंद्र मरकाम एवं दामाद दुर्गेश इड़पाचे ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उनका उपचार चल रहा था। बताया गया कि 3 जुलाई को शिखरचंद अपने दामाद दुर्गेश के साथ अस्पताल में थे। जबकि उनका पुत्र धर्मेंद्र सुबह अपने गांव बुढ़ियागांव लौट गया था। उसी दिन शाम करीब 4 बजे शिखरचंद ने दामाद से यह कहकर अस्पताल से बाहर निकले कि वह चाय पीने जा रहे हैं। लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे। करीब 4:30 बजे तक उनके अस्पताल वापस नहीं आने पर दामाद दुर्गेश ने अस्पताल परिसर, आसपास की चाय दुकानों एवं अन्य स्थानों पर उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र मरकाम को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर धर्मेंद्र तत्काल जिला अस्पताल पहुंचा और दोनों ने अस्पताल परिसर, बालाघाट नगर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा रिश्तेदारों के यहां भी खोजबीन की, लेकिन शिखरचंद का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद धर्मेंद्र मरकाम ने कोतवाली थाना पहुंचकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 98/2026 कायम कर मामले की जांच एवं तलाश शुरू कर दी है। शिखरचंद मरकाम का कद लगभग 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला है। घटना के समय उन्होंने गुलाबी-सफेद पट्टेदार शर्ट तथा काला चड्डा पहन रखा था। कोतवाली पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को शिखरचंद मरकाम के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा कोतवाली बालाघाट को सूचित करें ताकि उन्हें सकुशल परिजनों तक पहुंचाया जा सके।

NEW HOLLAND
आज आखिरी मौका
10 पे 35 का दम
छूटे ना हाथ से!
₹10 000/- की बुकिंग पर पाएं
₹35 000/- की रसीद
साई ट्रेक्टर ने बालाघाट की धरती में पहली ट्रेक्टर डीलरशीप की शुरुआत 1997 में की, साई ट्रेक्टर बालाघाट 30 वर्षों से ट्रेक्टर में नं. 1, किसानों के विश्वास के साथ अब दुनिया के बेहतरीन, उन्नतशील टेक्नोलॉजी वाली 130 वर्ष पुरानी ट्रेक्टर कंपनी (न्यू हालैण्ड भारत वर्ष में 25 वर्षों से) के साथ...
20 से 110 एच.पी. ट्रेक्टर श्रेणी
25000/- का फायदा
- न्यू हालैण्ड ट्रेक्टर अलग क्यों
- लिफ्टोमेटिक बटन, सात प्रकार की स्पीड
- पीटीओ गेयर बाक्स के साथ
- डबल क्लॅच सभी 4x4 मॉडल पर
- सिप्रोमेश फुल्ली लोडेड गेयर बॉक्स
- एसीबी (आक्जरी कंट्रोल वॉल युनिट उपलब्ध)
- 4x4 के सभी मॉडल पर उपलब्ध
- सभी गाड़ियों में डबल डीजल फिल्टर उपलब्ध
- इंडिगलेज ग्लॉस मिरर में
- हाईडेन्सिटी फायबर डीजल टेंक
असली हीरो की असली ताकत
सांई ट्रेक्टर्स (EX पॉवरट्रेक वाले)
नर्मदा नगर, बालाघाट, मो. 8770334649 | 9425138685

PADMESH X FIBERNET
Connecting the Unconnected...
PADMESHXFIBERNET SERVICE
providing you the very best connection in town.
for you
NOTHING BUT THE VERY BEST FOR YOU.
Follow us on @padmeshxfibernet 08045777666 www.padmeshdigital.in

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमेश बागरेचा द्वारा पद्मेश पब्लिकेशन, वार्ड नं.9, गुजरी चौक, बालाघाट (म.प्र.) से मुद्रित कराकर दैनिक बालाघाट एक्सप्रेस कार्यालय, काली पुतली चौक, बालाघाट(म.प्र.) से प्रकाशित,
प्रधान संपादक : उमेश बागरेचा, मो.नं. :9425138710, , ई-मेल- balaghatexpress@gmail.com पंजीयन क्रं. MPHIN/2009/32311, न्यायालयीन क्षेत्राधिकार बालाघाट